R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 19
01 से 15 जुलाई 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

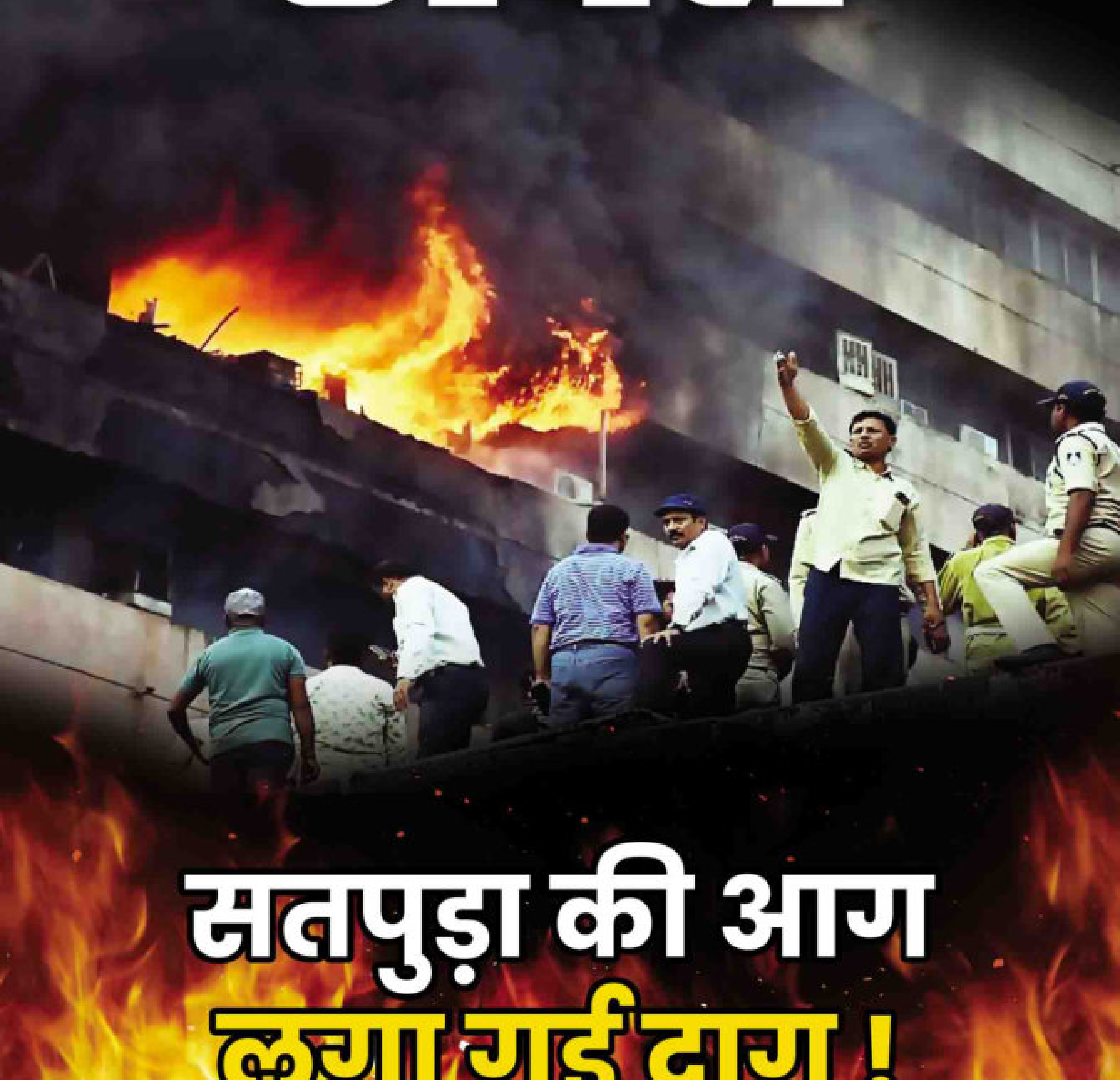

सतपुड़ा की आग लगा गई दाग !

आग ने खोली मप्र में फायर सेफ्टी और फायर फाइटर की पोल

अग्निकांड से सबक लेते हुए सरकार ने शुरू कराया सेफ्टी ऑडिट

ANU SALES CORPORATION
We Deal in
Pathology & Medical
Equipment
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

खनिज

9 | 3 साल के लिए नीलाम होंगे...

कैबिनेट के द्वारा मप्र रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब प्रदेश में 44 जिलों के रेत समूहों का ई-निविदा के स्थान पर ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया...

राजपथ

10-11 | इस बार डबल...

मप्र में विधानसभा चुनाव अभी भले पांच महीने दूर हों, लेकिन इसका बिगुल बज चुका है। भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। यह तय हो चुका है कि चुनाव में भाजपा शिवराज के ही चेहरे पर...

विकास

14 | माननीयों की मांग सीएम...

सरकारी खर्चे पर आधुनिक क्लास में पढ़ने की लालसा को पूरा कर रहे सीएम राइज स्कूल आज मप्र में विकास का ऐसा मॉडल बन गए हैं कि हर सांसद और विधायक की कोशिश है कि उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक सीएम राइज स्कूल स्थापित हों।

राजतंत्र

16-17 | नेता चले आदिवासी...

मप्र में आदिवासियों की आबादी भले ही 20-22 फीसदी है, लेकिन उनका राजनीतिक महत्व सबसे अधिक है। यही कारण है कि मप्र की राजनीतिक पार्टियों का सबसे अधिक फोकस आदिवासी क्षेत्रों पर रहता है। खासकर चुनावी समय में तो आदिवासी बहुल क्षेत्र राजनीति का ऐसा तीर्थ बन...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

कभी-कभी एक गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि बरसों की मेहनत पर दाग लग जाता है। ऐसा ही दाग मप्र की सरकार पर सतपुड़ा भवन की आग से लगा है। वैसे तो यह बिल्डिंग जिस समय बनी थी उस समय फायर सेफ्टी का कोई प्रावधान नहीं था। समय के साथ-साथ इस बिल्डिंग में मैन पावर बढ़ता गया और एसी, कूलर, कम्प्यूटर, फाइलों का बोझ बढ़ता गया, लेकिन सरकार कई बार की आग के बाद भी नहीं चेती और परिणाम यह हुआ कि सतपुड़ा भवन की ऊपरी तीन मंजिलें आग से तबाह हो गईं।

राजनीति

30-31 | मुफ्तखोरी का जाल

वोट के बदले मुफ्त के वादे की शुरुआत करने का श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। उसने पहले दिल्ली और बाद में पंजाब के विधानसभा चुनावों में ऐसा किया और जीत दर्ज की। लेकिन पंजाब में उसकी सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। इस साल के आखिर में देश के 4 राज्यों...

महाराष्ट्र

35 | बेटी को कमान...

जून 2022 में एकनाथ शिंदे अपनी ही पार्टी शिवसेना के 39 विधायकों के साथ विद्रोह कर उद्धव सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय शरद पवार के भतीजे और राज्य के उपमुख्यमंत्री रहे अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच कहा था कि अगर...

बिहार

38 | उद्घाटन से पहले ही...

1710 करोड़ रुपए के बजट से बन रहा बिहार का अगवानी-सुल्तानगंज गंगा महासेतु अपने आप, खड़े-खड़े पल भर में नदी में समा गया। पुल लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका था और कुछ महीने बाद ही इसका उद्घाटन होने वाला था। जिस तरह यह पुल...

6-7	अंदर की बात
41	महिला जगत
42	अध्यात्म
43	कहानी
44	खेल
45	फिल्म
46	व्यंग्य

अपनी बात

चुनावी रेवड़ी न बनकर रह जाए वंदे भारत...

किसी ने क्या खूब कहा है...

गरीब की थाली में पुलाव आ गया है...
लगता है शहर में चुनाव आ गया है।

भारत की राजनीति पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी हैं। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात करते हैं, उससे एक नया शब्द रेवड़ी कल्चर चर्चा में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी नफा-नुकसान देखे बिना चुनावी घोषणाएं की जाती हैं, सौगातें दी जाती हैं। गत दिनों प्रधानमंत्री ने मप्र की राजधानी भोपाल से 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी, जिनमें से दो ट्रेनें मप्र के लिए हैं। एक रानी कमलापति स्टेशन से इंदौर और दूसरी भोपाल से जबलपुर। अभी तक इंदौर रूट पर चलने वाली वंदे भारत को आधे भी यात्री नहीं मिल पाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है महंगे टिकट। आलम यह है कि वंदे भारत ट्रेन चलने के बाद भी लोग कार और बसों से इंदौर आ-जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि कहीं वंदे भारत ट्रेन चुनावी रेवड़ी न बनकर रह जाए। गौरतलब है कि रेलवे ने कुछ साल पहले भोपाल और इंदौर के बीच डबल डेकर ट्रेन भी चलाई थी। लेकिन वह ट्रेन भी कुछ दिन ही चल पाई, क्योंकि वह निरंतर घाटे में चल रही थी। जबकि उसके और वंदे भारत ट्रेन के भाड़े में काफी अंतर था। वंदे भारत ट्रेन में इंदौर से भोपाल जाते समय एसी चेयर कार श्रेणी का किराया 810 और एक्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1510 रुपए है। इसी तरह भोपाल से इंदौर का एसी चेयर कार किराया 910 और एक्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1600 रुपए वसूला जा रहा है। इस किराए में दोनों तरफ से फूड का खर्च भी जोड़ा गया है। बगैर फूड (नाश्ता/खाना) के किराया दोनों दिशाओं में कम है। वहीं ट्रेन का टाइम भी ऐसा है, जिससे वंदे भारत को महू-इंदौर-भोपाल इंटरसिटी ट्रेन कड़ी टक्कर दे रही है। वंदे भारत ट्रेन सुबह (रविवार छोड़कर) 6:30 बजे इंदौर से रवाना होगी, जबकि इसके पांच मिनट बाद इंटरसिटी चलेगी। इसकी सामान्य आरक्षित सीटिंग का किराया 100 रुपए है, जबकि एसी चेयर कार (बिना नाश्ता-खाना) का किराया 365 रुपए है। हालांकि इंटरसिटी को समय के मामले में वंदे भारत पीटेगी। जहां वंदे भारत दोनों दिशाओं का सफर महज तीन घंटे पांच मिनट में तय करेगी, वहीं इंटरसिटी इंदौर से भोपाल जाते समय चार घंटे 20 मिनट और भोपाल से इंदौर आते समय तीन घंटे 55 मिनट का समय लेती है। वहीं रेलवे के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल से इंदौर के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन को सबसे कड़ी टक्कर भोपाल-इंदौर के बीच चलने वाली चार्टर्ड बस से मिल रही है। ये बसें 24 घंटे भोपाल से इंदौर के बीच सफर की सुविधा देने के साथ ही कम किराया और इंदौर, भोपाल में एक से ज्यादा स्थानों पर पिक एंड ड्राप की सुविधा भी दे रही हैं। वंदे भारत से चार्टर्ड बस की तुलना करें तो सामने आता है कि चार्टर्ड बस में 3 घंटे 20 मिनट में इंदौर से भोपाल के बीच सफर किया जा सकता है, जबकि वंदे भारत 3 घंटे 5 मिनट में यह सफर पूरा कर रही है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन कितने दिन चलेगी, इसको लेकर लोगों में संशय है। हालांकि वंदे भारत को लेकर उनकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रेलवे की आय घटी है और दुर्घटनाएं बढ़ी हैं और यह आमतौर पर अपर्याप्त आधुनिकीकरण की वजह से हुआ है, लेकिन रेलवे घाटे में यह ट्रेन कितने दिनों तक चलाएगा?

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 19, पृष्ठ-48, 1 से 15 जुलाई, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्कण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

महिला वोटर्स पर फोकस

मप्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस तैयारियों में लगी हुई है। दोनों पार्टियों का अधिक फोकस महिला वोटर्स को साधने में लगा है। इसके साथ ही युवाओं और किसानों के मुद्दे भी सक्रिय हैं। साथ ही अन्य पार्टियां भी अपनी तैयारियों में लगी हैं।

● **हेमलता सोनी,** जबलपुर (म.प्र.)

छवि पर पड़ रहा असर

नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जिन चीतों को मप्र के कूनो नेशनल पार्क लाया गया था, उनमें से 3 चीतों और 3 चीता शावकों की मौत हो चुकी है। इससे मप्र की छवि पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चीतों की मौतों पर चिंता जताई है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए।

● **राजेश वर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

गर्व की बात

लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के मामले में मप्र को पहला स्थान मिला है। हर मापदंड पर पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए यह मूल्यांकन किया गया था। इससे मप्र एक बार फिर देश में नंबर वन की श्रेणी में आ गया है, जो मप्र के लोगों के लिए गर्व की बात है।

● **प्रीतम सिंह,** भोपाल (म.प्र.)

रेल दुर्घटनाओं पर नियंत्रण कब?

आज के समय में जब दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस समय में ओडिशा जैसे रेल हादसों का होना दुर्भाग्य की बात है। बीती सदी में जबकि तकनीक कमजोर थी और संसाधनों की किल्लत थी तो भारतीय रेल की अलग स्थिति थी, लेकिन आज साधन संपन्नता और फुलप्रूफ तकनीक के इस दौर में ओडिशा में जैसा रेल हादसा हुआ है वह कई सवाल खड़े करता है। आज हम नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल करके ऐसे हादसों पर लगाम लगा सकते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। हम दूसरे देशों की रेल पॉलिसीज से सीखकर उन्हें हमारे देश में लागू कर सकते हैं, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं कम हो सकें।

● **कमलेंद्र यादव,** ग्वालियर (म.प्र.)

भारत को सजग होने की जरूरत

भारत-चीन के मध्य संसार की सबसे लंबी विवादित सीमा का प्रबंधन भारत और चीन दोनों के लिए अस्मिता के प्रश्न से जुड़ा है।रत सैद्धांतिक रूप से मानता है कि यह सीमा तिब्बत के साथ है जिस पर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। भारत इस क्षेत्र को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से अधिक कुछ नहीं मानता। केंद्र की मोदी सरकार को सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन से बैठकर इस मामले में बातचीत करनी चाहिए। आने वाले समय में दोनों के बीच संबंध न बिगड़े इसको लेकर भारत को पहले ही सजग होने की जरूरत है।

● **मुस्कान पांडे,** विदिशा (म.प्र.)

समझना होगा

देश में इस समय मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट मांगे जा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अलग-अलग राज्यों में मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति को आगे कर अपना जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। यह जानते हुए भी कि भगवान के आशीर्वाद के अलावा दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। लोग मुफ्त की आस लगाए हुए हैं। यह एक आत्मघाती मानसिकता है क्योंकि करदाताओं का पैसा ही सरकारें मुफ्त के नाम पर लोगों में बांटकर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लेती हैं। यह दुखद है।

● **राजू मकोडिया,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

दांव-पेच

भाजपा-जजपा गठबंधन में दरार

अगले साल लोकसभा और इस साल के अंत में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर एक ओर जहां भाजपा अपने सहयोगी पार्टियों को मनाने में जुटी हुई है वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में गठबंधन सरकार चला रही भाजपा और जजपा के बीच मतभेद दिन-प्रतिदिन बढ़ते दिख रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों दलों के बीच मनमुटाव खत्म नहीं हुआ तो जल्द ही यह गठबंधन टूट सकता है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है और दोनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। दरअसल हरियाणा में अगले साल लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। इस बीच हरियाणा के भाजपा प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने बीते दिनों उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा था, जिसे लेकर जजपा खासी नाराज है। जिस पर खट्टर ने सफाई देते हुए कहा कि प्रभारी संगठन के लिए होते हैं सरकार के लिए नहीं। उनका हमारा गठबंधन चुनावी नहीं था, दोनों की आवश्यकता थी, जनहित में यह करना था, किया। जनहित में सबसे जरूरी यही होता है। गौरतलब है कि हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटें जीती थीं, वहीं जजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

वसुंधरा का बढ़ेगा कद

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुलाकात की है। राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर दोनों नेताओं की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा के कद और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए पार्टी उन्हें कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। दरअसल यह मुलाकात इसलिए भी अहम है, क्योंकि इस समय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुनावी राज्यों समेत समूचे संगठन की समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली में वसुंधरा राजे को खासा महत्व भी दिया गया था। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनाव के लिए बनने वाली चुनाव प्रबंधन कमेटी की कमान सौंपने सहित कई अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में वसुंधरा पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन वह राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वसुंधरा खेमे की तरफ से लगातार आलाकमान से यह मांग की जा रही है कि पार्टी उन्हें अपना चेहरा घोषित कर चुनाव में उतारे, जबकि उनके विरोधी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं।

दांव पर भाजपा के रिश्ते

देश की सत्ताधारी पार्टी एक ओर जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सहयोगियों को साधने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी दलों की नाराजगी का खामियाजा उसे आगामी चुनावों में उठाना पड़ सकता है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल से साथियों की नाराजगी की अटकलें हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि ये सियासी घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब पार्टी 2024 के चुनाव के लिए कवायद तेज कर रही है और विपक्ष एकजुटता की बातें कर रहा है। दरअसल हरियाणा में भाजपा जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार में है और दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब की निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। साथ ही वह उचाना सीट से भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा कर चुके हैं। जबकि इस सीट पर चौटाला का प्रभाव है और वह यहां से मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन ने भी दोनों दलों में दूरी बढ़ाई है। हालांकि चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों ही नेता मतभेद की अटकलों से इनकार कर रहे हैं।

दक्षिण से दांव खेलेंगे मोदी!

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 350 के फॉर्मूले पर काम कर रही भाजपा का फोकस अब दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के अलावा तमिलनाडु के रामनाथपुरम संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात को बल मिला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई तमिल को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत से। इस बीच तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय बाधा को पार कर लिया है और उन्हें दक्षिणी राज्य में अंदरूनी माना जाता है, न कि बाहरी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव दो निर्वाचन क्षेत्रों उप्र के वाराणसी और गुजरात के वडोदरा से लड़ा था। प्रधानमंत्री ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन वाराणसी का प्रतिनिधित्व किया। अन्नामलाई के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की बात चर्चा का विषय बन गई है। गौरतलब है कि अगले साल की शुरुआत में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं।

फिर पलटी मारेंगे सुभासपा!

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के मिशन लोकसभा चुनाव की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते वाराणसी पहुंचे योगी से सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की। तकरीबन 25 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद प्रदेश के सियासी हलकों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सुभासपा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, विधानसभा चुनाव में साथी रहे राजभर के अलग होने पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, अयोध्या से देर रात वाराणसी पहुंचे योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में रुके थे। वहीं सुभासपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी ठहरे थे। इस दौरान दोनों के बीच 25 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद जब राजभर बाहर आए तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की। लेकिन उनके बेटे अरुण ने दोनों की मुलाकात की पुष्टि की।

अब पैसे के लिए लगा रहे चक्कर

अक्सर आप लोगों को यह कहते सुनते हैं कि पुलिस की दोस्ती और पुलिस की दुश्मनी दोनों खराब होती हैं। मप्र में पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी की दोस्ती एक मकान मालिक को भारी पड़ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साहब ने हाल ही में उक्त व्यक्ति से उनका मकान खरीदा है। शहर की पॉश कॉलोनी में स्थित मकान की कीमत कई करोड़ आंकी जा सकती है। बताया जाता है कि साहब ने पहले तो उक्त व्यक्ति को बड़े-बड़े सपने दिखाकर मकान खरीद लिया। उसके बाद उस मकान की रजिस्ट्री भी करा ली है। साहब ने इस दौरान उक्त मकान की कीमत की उतनी रकम तो चुका दी है, जितनी रजिस्ट्री में दर्शायी गई है, लेकिन ऊपर का पैसा नहीं दिया है। बताया जाता है कि साहब ने उक्त मकान मालिक को दिलासा दिया था कि मकान की कीमत कम बताकर रजिस्ट्री करा ली जाए। उसके बाद ऊपर की जो भी रकम है उसे नगद दे दी जाएगी। साहब की बातों में आकर उक्त व्यक्ति ने मकान की रजिस्ट्री तो कर दी है, लेकिन अब साहब ऊपर की रकम देने के लिए उन्हें चक्कर लगवा रहे हैं। बताया जाता है कि पुलिसिया रसूख के कारण उक्त व्यक्ति साहब पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने से डर रहा है। उधर, साहब हैं कि मकान मालिक को पैसों के लिए चक्कर लगवा रहे हैं। अब देखना यह है कि साहब पैसा देते हैं या फिर उसे हजम कर जाते हैं।

कांग्रेस सरकार की कामना

प्रदेश में तकरीबन 4 माह बाद चुनाव का बिगुल बजेगा। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जोरशोर से लगी हुई हैं, वहीं प्रदेश की नौकरशाही में भी भावी सरकार को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ अफसर वर्तमान सरकार के पक्ष में हैं, तो कुछ बदलाव चाहते हैं। ऐसे ही अफसरों में कुछ अफसर कामना कर रहे हैं कि जैसे भी हो, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाए। दरअसल, ये वे अफसर हैं, जो वर्तमान सरकार की उपेक्षा या प्रताड़ना के शिकार बने हैं। इनमें दो पूर्व मुख्य सचिव तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के सपने देखने लगे हैं। यह रिटायर अफसर फिलहाल अपने-अपने गृहराज्य में बस गए हैं। दोनों की महत्वाकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक को उम्मीद है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो वे मुख्यसचिव व पुलिस महानिदेशक से ज्यादा ताकतवर होकर मप्र लौटेंगे। वे अपने लोगों को खबर भेज रहे हैं कि कमलनाथ उनके लिए सबसे ताकतवर प्रशासनिक पद का गठन करेंगे। दूसरे रिटायर अफसर को उम्मीद है कि कमलनाथ के सीएम बनते ही वे मुख्य प्रशासनिक सलाहकार के रूप में आमद देंगे। उधर, दो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी कांग्रेस की सरकार बनने की कामना कर रहे हैं। इन दोनों अफसरों के खिलाफ अभी हाल ही में सरकार ने जांच बैठाई है।

न इधर के, न उधर के

अपनी नौकरी के दौरान पाक साफ रहे एक आईएफएस अफसर इन दिनों रिटायरमेंट के बाद आजीविका मिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे साहब स्कूली बच्चों को बांटे जाने वाली ड्रेस को लेकर विपक्ष के साथ अपनों के भी निशाने पर हैं। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि खुद सरकार की ओर से फेक्ट चेक कर इस पर सफाई दी गई। उसके बाद केवल विपक्ष के निशाने पर रहने वाले साहब को लेकर सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक ने उच्च स्तरीय जांच को पत्र लिख दिया है। साहब की मिशन संचालक की नियुक्ति पहले भी सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में विपक्ष उन पर टेढ़ी नजर बनाए हुए है। आरोप है कि विद्यार्थियों को गणवेश तक नहीं मिल रहे हैं। समूहों के नाम पर ठेकेदार काम कर रहे हैं। विदिशा में आजीविका मिशन में अधिकारी दोषी भी पाए गए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लेकर कई शिकायतें हैं पर उन्हें अब तक नहीं हटाया गया है। वे 12 वर्ष से मिशन में जमे हुए हैं। भर्तियों में गड़बड़ियों की बात भी सामने आई पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। विपक्ष ने महिला स्व-सहायता समूहों के नाम पर हुई गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उधर, सत्तापक्ष के कुछ नेता भी अब साहब से खार खाने लगे हैं। ऐसे में साहब की स्थिति न घर के, न घाट के वाली बन गई है।

नजर लागी बंगले पर

फिल्म काला पानी का यह गाना तो आपने सुना ही होगा- नजर लागी राजा तेरे बंगले पर...। ऐसी ही नजर राजधानी में रसूखदार अफसरों के बंगले पर लग गई है। दरअसल, भोपाल के नए मास्टर प्लान में अफसरों के बंगले बाघ भ्रमण क्षेत्र में दर्शाए गए हैं। उसके बाद से ही अफसरों की नींद उड़ गई है। दरअसल, भोपाल में तालाब के किनारे, टाइगर मूवमेंट इलाके में मप्र के आईएएस-आईपीएस अफसरों ने अपने रसूख का उपयोग कर अवैध कॉलोनी और उसमें नियमों की धज्जियां उड़ाकर बड़े-बड़े बंगले तो बना लिए। इन्हें कानूनन जायज ठहराने इन अफसरों ने भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान में लगभग 3 वर्ष पहले यहां का एफएआर 0.06 से बढ़वाकर 0.75 प्रस्तावित करा लिया। इस प्रस्ताव के बाद इस अवैध कॉलोनी में जमीनों की रेट आसमान छूने लगी। लेकिन मास्टर प्लान में यहां का एफएआर 0.06 ही कर दिया है। यानि 10 हजार वर्गफीट प्लॉट पर मात्र 600 वर्गफीट ही निर्माण जायज माना जाएगा। ऐसे में रातों रात करोड़ों की हवेलियां कौडियों की हो गई हैं। जिससे अफसरों का चैन छिन गया है।

नौटंकीबाज से श्रीमंत खुश

अपनी पार्टी का पाला बदलकर दूसरी पार्टी में जाकर उसकी सरकार बनाने वाले अधिकांश विधायक सरकार में मंत्री बनकर जमकर मलाई काट रहे हैं। इनकी कमाई और इनके रसूख को देखकर सत्तारूढ़ पार्टी के मूल नेता हैरान-परेशान और हताश हैं। वहीं इन मंत्रियों में एक मंत्रीजी ऐसे हैं, जो अभी तक की जानकारी में तो पाक साफ हैं, लेकिन वे अपनी नौटंकी से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इन मंत्रीजी में इतनी ऊर्जा है कि वे आए दिन उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि इनके संरक्षक श्रीमंत को भी इनकी नौटंकी खूब भाती है। शायद यही वजह है कि विगत दिनों एक कार्यक्रम में जब मंत्रीजी के सिर पर बल्ब रखकर एक जादूगर ने उसे जलाया तो श्रीमंत भी खूब खुश हुए। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुए। मंत्रीजी भले ही भ्रष्टाचार से दूर हैं, लेकिन उनकी नौटंकीबाजी कभी-कभी इस कदर हास्यास्पद हो जाती है कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गौरतलब है कि दूसरी पार्टी से आकर वर्तमान सरकार में मंत्री बने ये सभी अपने राजनीतिक संरक्षक के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।

बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। लोगों ने मुझे भी बहुत सी बातें बताईं, मुझे किस तरह के नाम दिए, मेरे बारे में क्या-क्या कहा, लेकिन क्या मैं उनकी वजह से चीज बनूंगी? क्या मैं उनके कारण से अपनी जिंदगी में रुकूंगी? बिलकुल भी नहीं।

● रिया चक्रवर्ती

मेरी वजह से कुश्ती की बदनामी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसा न हो। कुश्ती की वजह से ही मैं 4-5 करोड़ की कोठी में बैठा हूं, बड़ी गाड़ियों में घूमता हूं। मुझे कई लोगों ने कह दिया है कि योगेश्वर तुम्हारी वजह से कुश्ती का मजाक बना रहे हैं। पर अब जो हो गया, वो मैं वापस नहीं कर सकता हूं। आगे ध्यान रखूंगा कि फिर ऐसी कोई बात न हो जाए।

● योगेश्वर दत्त

जनवरी में जारी अमेरिका-बेस्ड शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मकसद हमारी रेपुटेशन को डैमेज कर मुनाफा कमाना था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और गलत आरोपों का एक संयोजन थी। रिपोर्ट के कारण हमने एफपीओ को वापस लेने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें पैसा लौटाने का फैसला किया।

● गौतम अडाणी

अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और खास दोस्ती में से एक है। यह और ज्यादा मजबूत हो गई है। दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत होने से विश्व में शांति और एकता और मजबूत होगी। इस दोस्ती से विकास का मजबूत आधार बनेगा।

● जो बाइडेन

मेरे और सिद्धार्थ के बीच प्यार की शुरुआत शेरशाह के सेट पर हुई थी। हमने लव मैरिज की है, इसलिए जाहिर तौर पर हम सच्चे प्यार पर यकीन करते हैं। घर दो लोगों से बनता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि जो मेरे साथ है, जिसके साथ मैंने अपना जीवन जीने के लिए चुना है, मेरे जो पति हैं, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरे लिए वे सबकुछ हैं। वे मेरा घर हैं। हम जहां भी हों, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में, शहर के किसी भी कोने में, मेरे लिए वही मेरा घर हैं। आज हम दोनों अपने-अपने निर्णय से खुश हैं।

● कियारा आडवाणी

वाक्युद्ध

मप्र हो या देश अगर विकास देखा जा रहा है तो यह भाजपा के कारण ही। आजादी के बाद से लेकर कांग्रेस ने केवल देश का शोषण किया है। पिछले 9 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का सबसे विकासशील देश तो बना ही है, देश की ताकत भी बढ़ी है। जिससे आज भारत का मान बढ़ा है।

● जेपी नड्डा

केंद्र में जबसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, विकास के तो बड़े-बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, यह जनता जानती है। महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, अपराध तेजी से बढ़े हैं। शायद भाजपा की नजर में यही विकास है। अगर भाजपा ने विकास किया होता तो उसे राज्यों में लगातार हार नहीं मिलती।

● दिग्विजय सिंह

3 साल के लिए नीलाम होंगे रेत के ठेके

कैबिनेट के द्वारा मप्र रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब प्रदेश में 44 जिलों के रेत समूहों का ई-निविदा के स्थान पर ई-निविदा सह नीलामी प्रक्रिया की जाएगी। इसमें समूह में ठेके तीन वर्ष के लिए दिए जाएंगे। इसमें दो वर्ष का विस्तार किया जा सकेगा। माईनिंग प्लान, पर्यावरण अनुमति, जल-वायु की अनुमतियां मप्र राज्य खनिज निगम द्वारा ली जाएगी। ठेका राशि अब त्रैमासिक के स्थान पर मासिक किश्त के रूप में तथा ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई के स्थान पर ठेका संचालन का एक वर्ष पूर्ण होने पर की जाएगी।

मप्र में अब रेत की खदानें तीन साल के लिए नीलाम होंगी और जिला प्रशासन (कलेक्टर) के बजाय नीलामी खनिज विकास निगम करेगा। ठेका वृद्धि की सालाना दर 10 प्रतिशत बढ़ाई गई है। नई रेत नीति-2023 के जरिए रेत की खदानें सुचारू रूप से चलाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि रेत की कीमतें न बढ़ें। खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति भी खनिज विकास निगम ही लेगा, ताकि नए ठेके होने पर खदानों से रेत निकालने का काम न रुके। इसके साथ ही रेत की चोरी रोकने के लिए नए चेक पोस्ट लगाया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे रेत के अवैध खनन पर रोक लग सके।

मप्र में रेत से होने वाली कमाई को बढ़ाने के लिए सरकार ने रेत नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब रेत का ठेका पांच साल के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही ई टेंडर-कम-ऑक्शन प्रणाली लागू की जाएगी और नीलामी भी खुली होगी। बता दें कि, अब तक मप्र सरकार को 900 करोड़ रुपए की रेत से कमाई होती है। इस कमाई को 900 करोड़ से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपए करने के लिए सरकार ने रेत नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब रेत का ठेका तीन साल के लिए नहीं बल्कि पांच साल के लिए दिया जाएगा। दरअसल, तीन साल का ठेका होने के बाद उसी ठेकेदार को 10 फीसदी राशि बढ़ाकर दो साल के लिए ठेका नियमित कर दिया जाएगा। रेत के नियमों में बदलाव के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि, कैबिनेट में मप्र रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम-2019 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

बता दें कि, वर्तमान में मप्र में 44 जिलों में समूह है। इनमें से 37 के ठेके जून महीने में खत्म हो गए और बाकी के अगस्त महीने में समाप्त हो जाएंगे। मप्र में पहली बार राज्य सरकार द्वारा खनिज निगम को रेत की खदानें 10 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। लीज की दरें भी जल्द ही तय होंगी। खदानों की नीलामी खनिज निगम करेगा और लीज की राशि सरकार को देगा। खनिज विभाग द्वारा बनाई गई नई रेत नीति में एक और बदलाव किया गया है। अब तक ठेकेदार द्वारा पर्यावरण और उत्खनन की अनुमति ली जाती थी, लेकिन अब विभाग द्वारा यह अनुमति ली जाएगी। विभाग का मानना है कि कई ठेकेदार अनुमति नहीं ले पाते और रेत के ठेके की अवधि ही समाप्त हो जाती थी, लेकिन अब ठेकेदार को सभी अनुमति के साथ खदानें सौंपी जाएंगी। अब ठेकेदार को ठेके की आधी राशि पहले ही जमा करानी होगी। इसके अलावा विभाग पर्यावरण और उत्खनन की अनुमति लेने के बाद ही खदान को ठेकेदार को सौंपेगा।

खनिज विभाग की ओर से बनाई गई नई रेत नीति के अनुसार अब रेत ठेकेदार को ठेके की आधी राशि पहले ही जमा करना होगी, जबकि पहले 25 प्रतिशत राशि अग्रिम जमा कराई जाती थी। इसके साथ ही अब ठेकेदार मनमाने दामों पर रेत नहीं बेच सकेंगे। इस नई रेत नीति में कीमतों के नियंत्रण के भी प्रयास किए गए हैं। नई रेत नीति में रेत खदानों की नीलामी तीन साल के लिए होगी। नई रेत नीति में तहसील स्तर पर समूह बनाकर खदानें नीलाम करने का प्रावधान किया गया है। खनिज विभाग का मानना है कि ऐसे में ज्यादा ठेकेदार खदानें ले सकेंगे, किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही राजस्व में भी इजाफा होगा। खनिज विभाग की नई रेत नीति में एक और बदलाव किया गया है। अब तक ठेकेदार द्वारा पर्यावरण और उत्खनन की अनुमति ली जाती थी, लेकिन अब विभाग ही यह अनुमति लेगा। विभाग का मानना है कि कई ठेकेदार अनुमति नहीं ले पाते और रेत के ठेके की अवधि ही समाप्त हो जाती थी, लेकिन अब ठेकेदार को सभी अनुमति के साथ खदानें सौंपी जाएंगी।

नई नीति के तहत हितग्राही को मकान बनाने के लिए 16 घन फीट रेत की पात्रता होगी। खनिज अधिकारी हितग्राही को पास जारी करेगा और इसी आधार पर हितग्राही रेत खदान से 16 घन फीट में रेत उठा सकेगा। वहीं इसमें रेत केवल उसी हितग्राही को निशुल्क दी जाएगी, जो स्वयं का मकान बनाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों में बहुमंजिला इमारत बनाकर हितग्राही को फ्लैट दिए जा रहे हैं, ऐसे में फ्री रेत का लाभ शहर के हितग्राही को संभवत: नहीं मिल पाएगा।

● कुमार राजेंद्र

जब ठेका खत्म होगा, तभी नीलामी की जाएगी

नई रेत नीति में यह भी अहम है कि रेत की खदान की नीलामी हर साल जुलाई में करने के बजाय जब रेत का ठेका खत्म होगा, उसी अवधि में नीलामी की जाएगी। अभी अलग-अलग महीने के हिसाब से और कम वर्षों के लिए ठेके देने का नियम है। साथ ही नई रेत नीति में रेत खनन से पर्यावरण पर पढ़ने वाले प्रभाव, नदी के आकार में होने वाले परिवर्तन और आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या पर होने वाले प्रभाव को शामिल किया गया है। इसमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखना खास होगा। मप्र के 28 जिलों के रेत समूह में से 21 जिलों में ठेका अवधि 30 जून 2023 को समाप्त हो रही है। बाकी सात जिलों में यह अवधि 30 अगस्त 2023 तक है। सितंबर 2023 में रेत खदानों को नीलाम करने की कार्यवाही की जानी है। अभी तक ठेके खनिज विभाग जिला प्रशासन के माध्यम से करता था, लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था में यह कार्य खनिज निगम के पास रहेगा। ठेके की स्वीकृत वार्षिक राशि का 25 प्रतिशत नकद और इतनी ही राशि की सुरक्षा राशि बैंक गारंटी के रूप में देनी होगी।

देश में मप्र की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार आज सेवा, सुशासन और विकास के मामले में नंबर वन है। यही कारण है कि शिवराज और भाजपा आज मप्र के लिए जरूरी हो गए हैं। मप्र के इतिहास में शिवराज अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस की सत्ता में वापसी और कमलनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की राह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक और शिवराज का चेहरा बड़ी चुनौती है।

इस बार डबल इंजन का वार

मप्र में विधानसभा चुनाव अभी भले पांच महीने दूर हों, लेकिन इसका बिगुल बज चुका है। भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। यह तय हो चुका है कि चुनाव में भाजपा शिवराज के ही चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस की ओर से कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। चुनावी वादों से लेकर प्रत्याशियों का चयन तक-अंतिम फैसला कमलनाथ के ही हाथों में होगा। कमलनाथ ने यह ऐलान भी कर दिया कि वे छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए यह शायद काफी नहीं है। भाजपा की चुनौती से पार पाने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इसी अनुरूप अपनी रणनीति बनानी होगी। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने सेवा, सुशासन और विकास का जो मॉडल स्थापित किया है उससे पार पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है।

गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अतिविश्वास का शिकार हो गई थी। इस कारण पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। बाद में सरकार जरूर भाजपा ने दोबारा बना ली, लेकिन जमीन से मिला संकेत स्पष्ट था। अब उसी संकेत को समझते हुए भाजपा ने जमीन पर मप्र चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी ना सिर्फ अपनी रणनीति पर काम कर रही है, बल्कि दूसरी पार्टियों से किन्हें अपने दल में शामिल किया जा सकता है, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार का मप्र विधानसभा चुनाव भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ेगी। अब प्रधानमंत्री तो हर बार की तरह पार्टी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहेंगे ही, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इस लोकप्रियता के दम पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश रहेगी। चेहरों के दम पर तो पार्टी आगे बढ़ने ही वाली है, टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा ने अब तक 65 हजार बूथ समितियों का डिजिटल सत्यापन कर दिया है। पूरे देश में मप्र इकलौता राज्य है जहां पर भाजपा ने ये कर दिखाया है। अब उसी कड़ी में हर बूथ समिति को मतदाता सूची, पिछले दो विधानसभा तथा दो लोकसभा चुनावों के उस बूथ पर परिणामों का विश्लेषण दिया गया। साथ ही, उस बूथ पर राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची भी सौंपी गई है ताकि उनसे सीधा संपर्क हो सके। इसके अलावा हर बूथ समिति को उस बूथ पर प्रभावी व्यक्तियों की पहचान करने और उनसे संपर्क करने को कहा गया जो मतदाताओं पर असर डाल सके। बूथ मैनेजमेंट के साथ-साथ जातीय और धार्मिक समीकरण साधने पर भी जोर दिया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मप्र में हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहेगा। वहां भी महाकाल कॉरिडोर और दर्शन जैसी अन्य धार्मिक योजनाओं को गिनाया जाएगा। वैसे इस बार के टिकट वितरण को लेकर भी भाजपा हाईकमान ने अपना रुख साफ कर दिया है। परिवारवाद को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, किसी के भी रिश्तेदार को टिकट नहीं देने की बात हो रही है। सिर्फ जीतने वाले प्रत्याशी पर ही दांव चलने की तैयारी है।

भाजपा की एक खासियत है। वह चुनाव में अपना सबकुछ झोंक देती है। किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो, पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक,

भाजपा विकास, कांग्रेस मुद्दों के साथ

विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। गत दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रचार प्रभारी पवन खेड़ा और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भोपाल प्रवास पर कहा कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं की स्थिति, कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर भाजपा सरकार से जवाब चाहेंगे। पार्टी जो भी विषय उठाएगी, वह जनता की आवाज होंगे। हमने कर्नाटक चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा और जनता ने उन पर विश्वास किया। जो वादे हमने किए थे, उन पर कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिए गए। मप्र में भी किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं को प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपए, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करना, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ करने का वचन दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस वचनबद्ध है।

भाजपा को जिताने के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगा देते हैं। पार्टी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ लोगों का असंतोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे गौण हो जाता है। पार्टी मप्र में भी प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रखकर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना चुकी है। पिछले कुछ महीनों में मोदी जिस तरह बार–बार मप्र आए हैं, उससे यह स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस के पास मोदी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है। यह कमलनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। उन्हें ऐसी रणनीति बनानी होगी कि चुनाव में मुकाबला शिवराज बनाम कमलनाथ हो ना कि मोदी बनाम कमलनाथ। भारतीय राजनीति में सबका साथ सबका विकास का नारा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में अपनी विशेष पहचान बनाने में सफल रहे हैं। पार्टी की मजबूती की बात करें, तो नरेंद्र मोदी ने भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने में अद्‌भुत परिश्रम किया है। पूरे देश में सभी स्तर के चुनावों का संचालन करने में नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के पितृ पुरुषों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पार्टी का विस्तार किया तथा इसका जनाधार बढ़ाया। भाजपा आज देश में प्रथम स्थान की पार्टी है। साथ ही यह विश्व में सबसे अधिक सदस्यता वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में जानी जाती है। मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में गौरवशाली भारत से आधुनिक भारत तक की यात्रा को मजबूती प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1984 में भाजपा के लोकसभा में केवल दो ही सदस्य थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 282 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इस चुनाव की विशेषता यह थी कि तीन दशक के पश्चात किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 303 सीटों पर विजय प्राप्त की, जो किसी पार्टी द्वारा जीती गईं सर्वाधिक सीटें थीं। नरेंद्र मोदी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे, तब देश के केवल सात राज्यों में भाजपा की सरकार थी। गुजरात, राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़ एवं गोवा में भाजपा के मुख्यमंत्री थे, जबकि पंजाब में शिरोमणि

अकाली दल एवं आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ भाजपा सत्ता में भागीदार थी। वर्ष 2018 में भाजपा अपने शीर्ष पर थी। उस समय 21 राज्यों में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां सत्ता में थीं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि मोदी के विराट एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं कुशलता के कारण ही आज भाजपा सत्ता के केंद्र में बनी हुई है। वास्तव में राज्यों में भाजपा को सत्ता में लाने में भी मोदी ने अथक परिश्रम किया है। यह बात भी उल्लेख करने के योग्य है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात से देश में विपक्ष नाम की वस्तु भी प्राय: लुप्त हो गई। देश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस भी सिकुड़ती गई। देश ही नहीं, अपितु उन सभी राज्यों की यही स्थिति है जहां भाजपा सत्ता में है। कोई भी पार्टी भाजपा के समक्ष खड़ा होने में सक्षम प्रतीत नहीं हो रही है। मोदी के सुशासन एवं कौशल्य के समक्ष सभी पार्टियां धराशायी हुई पड़ी हैं। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जिससे वह सत्ताधारी पार्टी को घेर सके। वामपंथी पार्टियां भी लुप्त सी हो चुकी हैं।

कमलनाथ अक्सर अपने भाषणों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर बताते हैं। वे उनकी घोषणाओं को चुनावी जुमला बताकर खारिज करते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि शिवराज की लोकप्रियता का यह एक बड़ा कारण है। वे लोकलुभावन घोषणाएं करने में माहिर हैं और कमलनाथ को इसकी काट ढूंढनी होगी। समस्या यह है कि सरकार के मुखिया के रूप में शिवराज अपनी घोषणाओं को तत्काल लागू कर सकते हैं, लेकिन कमलनाथ केवल वादा कर सकते हैं। उन्हें आम जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि सरकार बनने पर उनकी घोषणाओं पर अमल किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक मप्र के मुख्यमंत्री बने रहे, इसका सबसे बड़ा कारण उनका ओबीसी होना है। राज्य में करीब 50 फीसदी आबादी ओबीसी की है। शिवराज के चेहरे के सहारे उनके अधिकांश वोट भाजपा के खाते में आते हैं। दूसरी ओर, कमलनाथ सवर्ण वर्ग से हैं। कांग्रेस के पास जो ओबीसी नेता हैं, उनका प्रभाव खास नहीं है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देकर उन्हें कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यह मुद्दा अब भी कानूनी दांवपेंचों में उलझा हुआ है। चुनाव के दौरान वे इसकी क्या काट ढूंढते हैं, यह कांग्रेस का भविष्य तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों जिस आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं, वह इस बात का साफ संकेत है कि अब पार्टी उनके ही नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने जा रही है।

● सुनील सिंह

मप्र कांग्रेस की राह में गुटबाजी बड़ी बाधा

गुटबाजी की समस्या कांग्रेस के लिए नई नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि मप्र में शायद इससे पार्टी को छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बीते तीन साल में कई नए गुट बन चुके हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके अजय सिंह राहुल और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कई बार कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आलाकमान के निर्देश पर फिलहाल इन नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन यह तय है कि टिकट बंटवारे के समय अपने समर्थकों के लिए ये दबाव बनाएंगे। कमलनाथ इनके साथ कैसे संतुलन बनाते हैं, यह देखना रोचक होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ के अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनकी अनदेखी करने की गलती वे नहीं कर सकते। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पूरी तरह से खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस बीच, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में गांठ दिखाई दे रही है। भले ही यह रार सार्वजनिक मंचों में नहीं दिख रही हो लेकिन जिसे मौका मिल रहा है तो बयानों का चौका लगाने से कोई नहीं चूक रहा। हालांकि मप्र में सत्ता में आने की आस लगाए बैठी कांग्रेस इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हर कमियों पर काम कर रही है।

मिशन 2023 में ताल ठोकेंगे सांसद

मप्र में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक पार्टियों की तैयारी परवान चढ़ती जा रही है। खासकर भाजपा और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनावी तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा का लक्ष्य है कि गुजरात की तरह ही मप्र में भी रिकॉर्ड जीत दर्ज की जाए। इसके लिए पार्टी की रणनीति है कि पुराने चावलों को विधानसभा के मोर्चे पर उतारा जाए। पार्टी सूत्रों के अनुसार क्षेत्रीय, जातीय समीकरणों को देखते हुए भाजपा आगामी चुनाव में सांसदों को विधानसभा का टिकट देने की रणनीति पर काम कर रही है। गौरतलब है कि मप्र भाजपा के कई सांसद भी विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। 2018 के चुनाव से सबक लेते हुए भाजपा इस बार केवल उन्हीं चेहरों पर दांव लगाएगी जो जिताऊ हैं। वहीं पार्टी अपने कुछ सांसदों को भी उतार सकती है। भाजपा इस बात का पता लगा रही है कि सांसदों को उतारने से जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़े क्या फायदे हो सकते हैं। भाजपा इस कवायद के जरिए मुख्य तौर पर जातीय संतुलन और जीत की संभावना को बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। भाजपा सूत्रों के अनुसार इस बार गणेश सिंह, राव उदयप्रताप, अनिल फिरोजिया, रमाकांत भार्गव, रोडमल नागर, रीति पाठक, केपी यादव, दुर्गादास उइके, गजेंद्र सिंह पटेल और जीएस डामोर जैसे सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारे जाने की चर्चा हैं। ये नेता एक से तीन बार तक के सांसद हैं। इनके अलावा भाजपा भिंड की सांसद संध्या राय, ग्वालियर के विवेक नारायण शेजवलकर, सागर के राजबहादुर सिंह, रीवा के जनार्दन मिश्रा, भोपाल की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और इंदौर के शंकर लालवानी को भी विधानसभा चुनाव लड़वाने की संभावना तलाश रही है।

पार्टी सूत्रों की मानें तो कुछ सांसदों ने खुद ये इच्छा जाहिर की है। पार्टी अभी हार-जीत की संभावनाएं खोज रही है। पार्टी अंदरूनी तौर पर सांसदों की छवि और उनके प्रभाव वाले इलाकों में पकड़ को लेकर भी रिपोर्ट तैयार करा रही है। दरअसल, भाजपा का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतकर सत्ता हासिल करने पर है। निकाय पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा को कई जिलों से मैदानी स्थिति की रिपोर्ट मिल चुकी है। वहीं कई विधायकों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कांग्रेस की विधायकी छोड़कर भाजपा में जो लोग आए उनमें से 3 मंत्री सहित 11 तो उपचुनाव में ही हार गए थे। लेकिन जो भाजपा के टिकट पर चुन लिए गए हैं, फिर भी अगले चुनाव में उनके टिकट को लेकर अनिश्चय बना हुआ है। क्योंकि उन सभी सीटों के पुराने नेता भी अब पूरी ताकत से अपनी दावेदारी जताएंगे। ऐसे में पार्टी अपने कई सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है।

अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर भाजपा क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश करेगी। पार्टी अपने गढ़ विंध्य को और मजबूत करने के लिए सीधी सांसद रीति पाठक को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। भाजपा के पास डॉ. गिरीश गौतम, राजेंद्र शुक्ला, शरदेंदु तिवारी, केदारनाथ शुक्ला जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। अगर रीति पाठक भी विधानसभा पहुंचती हैं, तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वहीं सतना के सांसद गणेश सिंह का सतना-रीवा और सीधी के कुछ हिस्सों में कुर्मी समाज का खासा दखल है। इसका भाजपा को विधानसभा में लाभ मिल सकता है, क्योंकि उसके पास कोई बड़ा कुर्मी चेहरा नहीं है। जबकि कांग्रेस में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जैसे कुर्मी चेहरे हैं। गणेश सिंह इनको चुनौती दे सकते हैं। गुना के सांसद केपी यादव ने 2019 के चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। बाद में सिंधिया बगावत कर भाजपा में शामिल हो गए थे। वो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में संभावना इस बात की है कि भाजपा सिंधिया को 2024 में गुना से ही मौका दे। इसलिए गुना के भाजपा सांसद केपी यादव को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। एक वजह यह भी है कि भाजपा नेता राव देशराज सिंह के बेटे यादवेंद्र ने हाल ही में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में यादव वर्ग में संतुलन बनाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। नर्मदापुरम क्षेत्र में सरताज सिंह और सीतासरन शर्मा वरिष्ठ हो चुके हैं। ऐसे में राव उदयप्रताप को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अनिल फिरोजिया सांसद बनने के पहले विधायक भी रह चुके हैं। विधानसभा में लौटते हैं, तो खटीक समाज को मजबूती मिलेगी। बलाई वर्ग को छोड़कर बाकी जातियां एकजुट होंगी। वहीं जीएस डामोर भाजपा के कद्दावर नेता रहे दिलीप सिंह भूरिया की कमी को पूरा कर सकते हैं। मौजूदा आदिवासी विधायक सुलोचना रावत बीमार चल रही हैं।

● राजेश बोरकर

प्रज्ञा देंगी नेता प्रतिपक्ष को चुनौती

भाजपा जिस रणनीति पर काम कर रही है, उसके अनुसार भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बाद अब भाजपा प्रज्ञा के जरिए नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को घेरने की तैयारी कर रही है। लहार ऐसी विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। इस बार भाजपा किसी भी तरह से लहार के सियासी किले में अपना परचम लहराना चाहती है। पार्टी ने इसके लिए भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को चुना है। पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी ने प्रज्ञा को लहार से उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी में इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। क्योंकि पार्टी प्रज्ञा को उतारने से पहले पूरा सियासी नफा-नुकसान देखना चाहती है। प्रज्ञा मूल रूप से भिंड जिले की रहने वाली हैं और लहार विधानसभा सीट भी भिंड में आती है। प्रज्ञा के जरिए पार्टी आक्रामक हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है। इसी रास्ते पर चलकर पार्टी ने प्रज्ञा को भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था और बड़ी जीत भी हासिल हुई थी। यह स्थिति तब थी, जब दिग्विजय के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के दिग्गज और ताकतवर नेता तैयार नहीं थे। दिग्विजय के बाद अब पार्टी प्रज्ञा के जरिए लहार सीट पर मप्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को भी घेरने की तैयारी है। पार्टी को उम्मीद है कि इस रास्ते पर चलकर लहार में जीत का परचम लहराया जा सकता है।

वाटर पॉलिटिक्स पर खर्च होंगे 3000 करोड़

मप्र में जलसंकट सबसे बड़ी समस्या है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले 17 साल में प्रदेश के शहर से लेकर गांवों तक पानी पहुंचाने की लगातार कोशिश की है। लेकिन आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में गर्मी आते ही जलसंकट विकराल रूप ले लेता है। ऐसे में जब भी चुनाव आते हैं जलसंकट मुद्दा बन जाता है। इस बार के चुनाव में भी जलसंकट मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने वाटर पॉलिटिक्स पर तकरीबन 3000 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है। ताकि विपक्ष को जलसंकट को चुनावी मुद्दा बनाने का अवसर न मिल पाए। यदि मप्र सरकार की कोई एक योजना जो कि सबसे बड़ी योजना है तो वह है जल जीवन मिशन चुनावी वर्ष में मिशन के कामों को जैसे पंख ही लग गए हैं।

गौरतलब है कि जन जीवन मिशन के तहत प्रदेश में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य हो रहा है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मप्र अन्य राज्यों से काफी आगे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा-निर्देश पर कार्य को गति देने के लिए प्रदेश में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन बनाए जाकर उसके अंतर्गत अपेक्स समिति एवं एग्जीक्यूटिव समितियों का गठन किया गया है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुरूप मिशन के लेन-देन के लिए सिंगल नोडल एकाउंट खोले गए हैं। साथ ही मिशन के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थाओं के एनपैनलमेंट की कार्रवाई भी की गई है।

शिवराज सरकार जल जीवन मिशन के कामों को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड पर है। सरकार ने इस योजना के लिए खजाना खोल दिया है। इसकी बागनी ये है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अकेले जून के लिए ही खर्च करने के लिए जो राशि मांगी तो वित्त विभाग ने पूरे 2947 करोड़ 45 लाख रुपए की अनुमति दे दी है। ऐसा संभवत: कम ही होता है कि किसी विभाग को एक साथ एक बार में ही खर्च करने के लिए इतनी बड़ी राशि मिलती हो। मप्र में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की गति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बुरहानपुर के बाद अब निवाड़ी प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला बन गया है, जिसके पास हर घर में नल के पानी का कनेक्शन है। बता दें, वर्ष 2019 में शुरू हुए मिशन में दिसंबर, 2024 तक सवा करोड़ की आबादी तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। हालांकि राज्य सरकार दिसंबर, 2023 तक ही इसे पूरा करना चाहती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार अब टुकड़ों में काम कर रही है। अब उन गांवों में सबसे पहले पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जहां से जलस्रोत की दूरी 30 किमी या उससे कम है। इसमें एक शर्त भी है कि यह जलस्रोत स्थायी होने चाहिए। इन गांवों में पानी पहुंचाने में करीब एक साल लगेंगे। रीवा, सतना, सीधी, अशोकनगर और देवास जिले के सात ब्लाकों में 100 किमी दूर से पानी लाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पर सरकार को अन्य परियोजनाओं से ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ रही है। इन्हें समूह परियोजनाओं के साथ ही जोड़ा गया है।

23 जिलों में योजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। इनमें 50 प्रतिशत घरों तक पानी पहुंच गया है। जबकि इंदौर, बुरहानपुर और निवाड़ी में 80 प्रतिशत से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन किए जा चुके हैं, लेकिन इन गांवों में 30 से 40 प्रतिशत कनेक्शन ही सत्यापित हो पाए हैं। वहीं 12 जिले योजना में पीछे हैं। इनमें 40 प्रतिशत से कम घरों में कनेक्शन हो पाए हैं। पन्ना, सतना, सिंगरौली, छतरपुर और भिंड जिले में 30 प्रतिशत घरों में भी पानी नहीं पहुंच पाया है। इनमें सभी घरों तक पानी पहुंचाने में करीब दो वर्ष लग जाएंगे। मप्र में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी पहुंचाने की योजना ने लगभग आधा सफर तय कर लिया है। प्रदेश में अब तक 51,548 गांवों में से 25,810 गांवों में नल से पानी पहुंचा दिया गया है। अब सरकार के सामने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा गांवों में नल से पानी पहुंचाने की चुनौती है, जिससे कि गांवों में सरकार की धमक और चमक बढ़ाई जा सके। कहते हैं बिन पानी सब सून। यदि किसी क्षेत्र में पानी की किल्लत है तो फिर सरकार की सभी उपलब्धियों पर लगभग पानी ही फिर जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए पानी सबसे बड़ी जरूरत है। सड़क, बिजली जैसी जरूरतों की बारी तो उसके बाद ही आती है। प्रदेश सरकार ये बात अच्छे से जानती है, इसलिए पानी के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों के बीच पहुंच बनाने की कोशिश में लगी हुई है।

● बृजेश साहू

कामों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग

प्रमुख सचिव पीएचई संजय शुक्ला का कहना है कि मप्र में जल जीवन मिशन के तहत 50 फीसदी से अधिक घरो में नल से पानी पहुंचा दिया गया है। प्रदेश में मिशन के काम तेजी से चल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों को नल से पानी उपलब्ध हो सके। मिशन के कामों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जा रही है। 19 जून तक की स्थिति में प्रदेश में 60 लाख 24 हजार 817 ग्रामीण घरों में सरकार ने नल से पानी पहुंचा दिया है। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 20 लाख ग्रामीण घरों में नल से पानी देने की योजना है। इस तरह सरकार ने आधी मंजिल तय कर ली है। ये योजना 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। तब वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। मप्र में जून 2020 से मिशन का काम शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अफसरों को टास्क दिया है, उसके तहत प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2023 तक कम से कम 80 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाने का प्लान तय किया गया है। इस तरह प्रदेश की बड़ी आबादी विधानसभा चुनाव तक नल से पानी की पहुंच के दायरे में शामिल हो जाएगी, वहीं बाकी बचे कामों को वर्ष 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि प्रदेश गुजरात के बाद नल से पानी उपलब्ध कराने के मामले में देश के बड़े राज्यों में कम से कम दूसरे नंबर पर रहे। पहले पर तो गुजरात बना हुआ है।

माननीयों की मांग सीएम राइज स्कूल

विधायकों की मांग पर 130 स्कूल

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सीएम राइज स्कूलों में हर दिन होती नई गतिविधियों ने बच्चों के अभिभावकों को आकर्षित किया है। यही वजह है कि सीट क्षमता से अधिक अनुपात में प्रवेश के लिए आवेदन आ रहे हैं। विद्यालयों में नवाचार, शिक्षकों और बच्चों के बीच बेहतर अनुशासन प्रेरणादायी बन रहे हैं। विद्यालयों की भव्य साज-सज्जा आधुनिक लैब, प्रयोगशाला और अध्यापन पैटर्न से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति हो रही है। यही कारण है कि हर विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्कूल चाह रहा है। विधायकों ने अपने पत्रों में क्षेत्रीय जनता की मंशाओं का जिक्र भी किया है। अधिकारियों के अनुसार इन विधायकों की मांग संख्या में 130 स्कूल आ रहे हैं। कई विधायकों ने ऐसी ही संस्थाओं को सीएम राइज करने की डिमांड की है, जिनमें वर्तमान में स्कूल लग रहे हैं। यहां लागत कम लगने की उम्मीद है। जबकि जहां से बिल्डिंग को तोड़कर पूरा भवन बनाया जाना है। वहां बजट की ज्यादा जरूरत है। मांग के अनुसार मैदानी सर्वे करवाकर विभाग ने अनुमानित बजट प्राप्त करने के लिए वित्त को प्रस्ताव भेजा है। ताकि विधानसभा चुनाव से पूर्व इन विद्यालयों को शुरू करने राशि प्राप्त हो सके।

सरकारी खर्चे पर आधुनिक क्लास में पढ़ने की लालसा को पूरा कर रहे सीएम राइज स्कूल आज मप्र में विकास का ऐसा मॉडल बन गए हैं कि हर सांसद और विधायक की कोशिश है कि उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक सीएम राइज स्कूल स्थापित हों। इसके लिए प्रदेश के विधायकों में होड़ मच गई है। विधायकों ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल खोलने की मांग की है। दरअसल, सीएम राइज स्कूलों में निजी स्कूलों की तरह सारी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। इससे छात्रों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी का कहना है कि मांग के अनुसार नवीन सीएम राइज स्कूल खोलने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग से जितनी स्वीकृति मिलेगी। उसी के अनुसार प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 अक्टूबर 2022 को इंदौर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 2519 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के 69 सीएम राइज स्कूल का भूमिपूजन किया था। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि थी। सीएम राइज स्कूलों में स्मार्ट माध्यम से शिक्षा दी जा रही है और आधुनिक प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय की सुविधा के साथ कला, संगीत, खेल-कूद और व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी इन स्कूलों में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दरअसल, राज्य शासन ने स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सीएम राइज स्कूल शुरू करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया है। ये स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाने के लिए खोले जा रहे हैं। सीएम राइज स्कूल में केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक शिक्षा दी जा रही है। प्रदेश में 2 चरण में 9 हजार 95 सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं। प्रथम चरण में वर्ष 2021-24 में प्रत्येक जिला एवं विकासखंड स्तर पर 360 स्कूल खोले जाएंगे। दूसरे चरण में वर्ष 2024 से 2031 तक प्रत्येक 10 से 15 किलोमीटर में एक सीएम राइज स्कूल शुरू होगा और 8 हजार 735 स्कूल खोले जाएंगे। सीएम राइज स्कूल का लक्ष्य छात्रों के सीखने के स्तर में उल्लेखनीय प्रगति लाना रहेगा।

जिन क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूल शुरू हो गए हैं वहां के छात्र और अभिभावक काफी खुश हैं। ऐसे में अब हर कोई चाहता है कि उनके क्षेत्र में कम से कम एक सीएम राइज स्कूल तो होना की चाहिए। इसलिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सीएम राइज स्कूल योजना अब विधायकों के बीच प्रतिस्पर्धा बन गई है। हर विधायक इस प्लान में अधिक से अधिक स्कूल अपने विधानसभा क्षेत्रों में चाह रहे हैं। विभाग में अफसरों के अनुसार शिक्षा विभाग में 50 विधायकों के पत्र आए हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में सवा सौ से अधिक स्कूल मांगे हैं। समय-सीमा में राशि मिले, इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षा विभाग ने प्रथम चरण के दौरान राज्य में 275 स्कूल खोले थे। शुरुआती दौर में लक्ष्य तो हर ब्लाक में एक-एक स्कूल खोलने का था। कई ब्लाकों में विधायक दो से लेकर तीन स्कूल खुलवाने में सफल रहे थे। इसके बाद सरकार ने इन विद्यालयों में वृद्धि करने के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया था। इन संस्थाओं में अलग हटकर प्रशासनिक और अकादमिक गतिविधियां हुई तो समाज में भी जबरदस्त आकर्षण बढ़ा है। यहां होते शिक्षा के गुणात्मक विकास को लेकर जन प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्कूल मांगे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों का कहना है हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्कूल चाह रहा है। कई विधायक तो ऐसे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में चार-चार स्कूलों की डिमांड की है। यह मांग करने वालों में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायक हैं। लोक शिक्षण संचालनालय में विधायकों ने जितने पत्र दिए हैं। वह विभाग को प्रेषित किए गए हैं।

सीएम राइज स्कूल की 10 प्रमुख विशेषता निर्धारित की गई हैं। इन स्कूलों में विश्व-स्तरीय अधो-संरचना, परिवहन सुविधा, नर्सरी एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल लर्निंग, शत-प्रतिशत स्टाफ एवं सहायक स्टाफ, स्टाफ की क्षमता वृद्धि, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, वाचनालय, पाठ्येत्तर सुविधाएं, 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप कौशल कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा और पालकों की सहभागिता रहेगी। सीएम राइज स्कूल का उद्देश्य ऐसे स्कूल समुदाय का निर्माण करना है, जो सभी विद्यार्थियों में कठिनाइयों से निपटने की क्षमता और उनके संपूर्ण विकास को बढ़ावा देगा। उन्हें समाज में योगदान देने और संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए सशक्त बनाएगा।

● जितेंद्र तिवारी

राहुल गांधी के टारगेट पर श्रीमंत

2018 में मप्र में कांग्रेस की सरकार बनाने में महती भूमिका निभाने वाले श्रीमंत यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आंख और कान माने जाते थे। लेकिन 2020 में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर सिंधिया ने जबसे भाजपा का दामन थामा है, तभी से वे कांग्रेस के दुश्मन नंबर वन हो गए हैं। अब विधानसभा चुनाव में भी वे मप्र कांग्रेस के नेताओं के साथ ही राहुल गांधी के टारगेट पर हैं। जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की रणनीति है कि श्रीमंत को उनके गढ़ में घेरकर रखा जाए, वहीं राहुल गांधी ने उनके गढ़ यानी ग्वालियर-चंबल से चुनाव का आगाज करने की तैयारी शुरू कर दी है। मप्र में राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा ग्वालियर से होगी। इसको लेकर कांग्रेस में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं।

गौरतलब है कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस हाईकमान का सबसे ज्यादा फोकस मप्र पर है। गांधी परिवार भी मप्र के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर चुकी हैं। जबलपुर में उन्होंने मां नर्मदा की पूजा कर जहां सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का संकेत दे गई हैं, वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मप्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पांच गारंटी का ऐलान भी कर गई। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बारी है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी जुलाई में मप्र के दौरे पर आएंगे। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के साथ आएंगे। गौरतलब है कि ग्वालियर व चंबल संभाग के 8 जिलों में कुल 34 सीटें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा को 7 सीटें मिली थीं और सीट बसपा के खाते में गई थी। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव की परफॉर्मेंस को बरकरार रखना चाहती है। कांग्रेस नेतृत्व ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह आदि को ग्वालियर चंबल अंचल में सक्रिय किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ग्वालियर, चंबल-अंचल में कांग्रेस का निश्चित वोट बेस है। वर्ष 2013 और 2008 के चुनावों में भी कांग्रेस को यहां अच्छा वोट शेयर मिला था।

मप्र में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच आमने-सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसका कारण यह है कि सत्ता में वापसी की कोशिश करने के लिए कांग्रेस के चुनावी अभियान की कमान राहुल के पास होगी। दूसरी ओर, सिंधिया को ग्वालियर-चंबल में अपना गढ़ बचाने के लिए अपने पुराने दोस्त से मुकाबला करना ही होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। इतने कि कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया, राहुल की कोर टीम के अहम सदस्य थे। प्रियंका गांधी भी उनसे अपने भाई की तरह व्यवहार करती थीं। दोनों परिवारों के बीच यह दोस्ती दो पीढ़ियों से चली आ रही थी। सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया और राहुल के पिता राजीव गांधी के बीच भी प्रगाढ़ दोस्ती थी। फिर आया मार्च, 2020 जब ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। बीते तीन साल में सियासत ने ऐसी करवट ली कि अब मप्र में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में राहुल और ज्योतिरादित्य के बीच आमने-सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। तीन साल पहले भाजपा में जाने के बाद भी सिंधिया आमतौर पर गांधी परिवार पर सीधा हमला करने से परहेज करते थे। राहुल के बयानों के बारे में पूछे जाने पर वे इसे कांग्रेस का आंतरिक मसला बताकर पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी कांग्रेस का सबसे ज्यादा ध्यान ग्वालियर-चंबल क्षेत्र पर है जो सिंधिया का गढ़ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस इलाके में लगातार सक्रिय हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी लगातार इस क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस की सारी रणनीति सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में पटकनी देने की है ताकि उनसे बदला लिया जा सके। ऐसे में सिंधिया के लिए अपना गढ़ बचाने की चुनौती है।

● **अरविंद नारद**

जुलाई में सिंधिया के गढ़ में हल्लाबोल

जानकारी के अनुसार जुलाई में ग्वालियर में राहुल गांधी की विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। इसके बाद महाकौशल में कांग्रेस को सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। यही वजह है कि महाकौशल के साथ ही कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर है। कांग्रेस ग्वालियर में राहुल गांधी की जनसभा के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करना चाहती है। दरअसल, मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वे अपने 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, जिससे कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उनके साथ बड़ी संख्या में ग्वालियर, चंबल अंचल के कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी भाजपा में चले गए थे सिंधिया समर्थक विधायकों और नेताओं को पार्टी में तवज्जो मिलने से भाजपा के पुराने नेता नाराज हैं। उनके बीच शुरुआत से ही पटरी नहीं बैठ रही है। अब जब चुनाव में टिकट बंटवारे का वक्त नजदीक आ गया है, तो उनके बीच खाई और बढ़ती जा रही है। पुराने भाजपाई सिंधिया समर्थकों को फिर से टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भाजपा में मची अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाना चाहती है। यही वजह है कि राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा ग्वालियर में रखने का निर्णय लिया गया। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के ग्वालियर आगमन पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।

नेता चले आदिवासी के द्वार

मप्र में भले ही आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में हैं, लेकिन चुनावी साल में उनकी ताकत सबसे अधिक बढ़ जाती है। यही कारण है कि मप्र में इस साल के चुनाव में भी आदिवासियों के भाव बढ़े हुए हैं। 27 जून का दौरा रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 1 जुलाई को शहडोल जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए दोनों पार्टियों के नेताओं ने आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दरअसल, कहा जाता है कि आदिवासी जिस ओर हो जाते हैं, प्रदेश में उस पार्टी की सरकार बन जाती है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों का फोकस आदिवासी क्षेत्रों पर है।

मप्र में आदिवासियों की आबादी भले ही 20-22 फीसदी है, लेकिन उनका राजनीतिक महत्व सबसे अधिक है। यही कारण है कि मप्र की राजनीतिक पार्टियों का सबसे अधिक फोकस आदिवासी क्षेत्रों पर रहता है। खासकर चुनावी समय में तो आदिवासी बहुल क्षेत्र राजनीति का ऐसा तीर्थ बन जाता है, जहां हर पार्टी और हर नेता जाने की कोशिश करता है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा और कांग्रेस का भी पूरा फोकस आदिवासी क्षेत्रों पर है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपना रूख आदिवासी बहुल क्षेत्रों की ओर कर लिया है। अब हर पार्टी के नेता आदिवासी के घर पहुंचने की तैयारी में जुट गए हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को शहडोल जाने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। मप्र में एक हफ्ते के भीतर गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों पर कुदरत का ग्रहण लग गया। मौसम की बेरुखी ने बालाघाट में गृहमंत्री अमित शाह और शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौपर को नहीं उतरने दिया। इससे इसी साल के अंत में होने वाले मप्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के डबल इंजन सरकार के अभियान को धक्का लगा है। पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं के कार्यक्रम से 30 विधानसभा सीटों का गणित जुड़ा हुआ था। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मप्र की इन 30 विधानसभा सीटों का भाजपा के लिए क्या महत्व है, यह इस बात से पता चलता है कि 27 जून को शहडोल में स्थगित प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 1 जुलाई को फिर तय कर लिया गया है। इसके पहले गृहमंत्री अमित शाह बालाघाट में 22 जून को चुनावी पैटर्न का रोड शो करने के अलावा पार्टी की गौरव यात्रा का भी श्रीगणेश करने वाले थे, जो 30 विधानसभा सीटों का भ्रमण करते हुए 27 जून को शहडोल पहुंचने वाली थी। लेकिन मौसम खराब होने कारण गृहमंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से उड़ान नहीं भर सका और अंत में उनका बालाघाट का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। यहां बताते चलें कि गृहमंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 जून को गौरव यात्रा को बालाघाट से रवाना किया। इन्हीं 30 सीटों के चुनावी गणित के हिसाब से वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस (24 जून) पर 22 जून से 27 जून तक 6 गौरव यात्रा निकाली गई। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहडोल दौरे के दौरान इन गौरव यात्राओं का समापन होना था। एक बार फिर इंद्रदेव भाजपा से नाराज दिखे और 48 घंटों से मप्र में लगातार हो रही वर्षा के कारण प्रधानमंत्री मोदी का शहडोल दौरा रद्द करना पड़ गया।

सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला

एक तरफ भाजपा विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने बेस को मजबूत कर रही है। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य शीर्ष नेता जातिगत समीकरणों का बैलेंस बनाने में भी जुटे हैं। इसके तहत एक तरफ एससी जातियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री खुद भाजपा के दलित आइकॉन्स के लिए समर्थन दिखाने में जुटे हैं। इसके अलावा दलितों के करीब आने की कोशिश के तहत उनके घर पहुंचने की मुहिम भी चलाई गई। भाजपा जिस सामाजिक समरसता के फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में अपनाने जा रही है उसका नगरीय निकाय चुनाव में सफल प्रयोग हो चुका है। थिंक टैंक कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है कि आने वाले समय में राजनीति को भ्रष्टाचार, अहंकार और जनता से दूरी बनाकर रहने वाले नेताओं से मुक्त कर समाज के लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। यही वजह है कि आने वाले चुनाव से भाजपा इस प्रयोग को करेगी।

आदिवासी गौरव पुनर्स्थापना के संदेश के साथ यह यात्रा जिन 30 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, उनमें 2018 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से 19 स्थानों पर भाजपा का कब्जा है। यही वजह है कि भाजपा के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने आनन-फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल का कार्यक्रम 1 जुलाई को फिर से तय कर लिया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। अब बात करते हैं, गौरव यात्रा को कवर करने वाली 30 विधानसभा सीटों की। बालाघाट जहां से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, वो सीट भाजपा के पास है। इसके अलावा जबेरा, जबलपुर केंट, मंडला, अनूपपुर, ब्योहारी, जयसिंह नगर, अजयगढ़ (पन्ना), पवई, विजयराघवगढ़, धौहनी, उमरिया (बांधवगढ़), मानपुर, जबेरा, मझौली, सिहोरा, केवलारी, सिवनी सीटें भाजपा के पास हैं। शहडोल में जिस स्थान पर यात्रा का समापन हुआ, वहां की जयसिंहनगर सीट भी भाजपा के पास ही है। वहीं, कांग्रेस के पास बालाघाट जिले की बैहर सहित निवास, शहपुरा, डिंडौरी, बड़वारा, बरगी, छिंदवाड़ा, चौरई, लखनादौन, कोतमा तथा पुष्पराजगढ़ की सीट हैं। अब भाजपा की निगाह अपनी 19 के साथ इन 11 सीटों पर भी है, जो 2018 में उसके हाथ नहीं आ सकी थी।

भाजपा और कांग्रेस आदिवासी वोटरों को साधने की हर कोशिश कर रही हैं। दोनों दलों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। इन्हें अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा हो या कांग्रेस, कोई कसर नहीं रहने देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेसा का नियम लागू करके इन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया है तो युवा अन्न दूत सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सतना में कोल महाकुंभ में भाग ले चुके हैं तो छिंदवाड़ा भी पहुंचे थे। मप्र में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) का जनाधार भी तेजी से बढ़ रहा है। संगठन ने युवाओं को आदिवासी प्रभाव वाली 80 सीटों पर चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए संगठन लगातार जमीनी स्तर पर काम करते आ रहा है। जयस का बढ़ता जनाधार भाजपा और कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रहा है। मप्र की 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 30 और भाजपा को 16 सीट पर जीत मिली थी। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इसके अलावा 30 सीटों पर आदिवासी वोटर प्रभाव रखता है। इसलिए कहा जाता है कि आदिवासी वोट जिधर गया, सिंहासन पर पहुंचा। अब भाजपा, कांग्रेस के अलावा दूसरी अन्य पार्टियां भी आदिवासी वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी ताकत लगा रहे हैं। सरकार ने आदिवासियों को साधने के लिए पेसा एक्ट से लेकर कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। वहीं, कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट आदिवासी वोटर को साधने के हिसाब से तय किया था। हाल ही में प्रियंका गांधी ने भी जबलपुर में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करने से पहले रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

2003 विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 41 सीटें रिजर्व थीं। इसमें से भाजपा ने 37 सीटें जीती थीं। जबकि कांग्रेस सिर्फ दो सीट पर सिमट गई थी। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दो सीट जीती थी। 2008 विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। इसमें भाजपा ने 29 सीटें जीतीं। वहीं, कांग्रेस की सीटें बढ़कर 17 पहुंच गई। 2013 विधानसभा चुनाव में 47 सीटों में से भाजपा ने 31 सीटें जीतीं। वहीं, कांग्रेस की सीटें बढ़कर 15 पहुंच गई। 2018 विधानसभा चुनाव में 47 आरक्षित सीटों में से कांग्रेस ने 30 सीटें जीती, भाजपा को सिर्फ 16 सीटें ही मिलीं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता।

उधर, कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है। आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जिलों में संपर्क कार्य प्रारंभ कर दिए हैं तो आदिवासी कांग्रेस बूथ स्तर पर टीम बना रही है। सामाजिक सम्मेलन करने के साथ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम शहडोल पहुंचे। यहां से उमरिया और फिर अनूपपुर गए। वहीं 24 जून को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ मंडला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जनसभा को संबोधित किया। टेकाम ने कहा कि आदिवासी बहुत समझदार हैं और सच्चाई को पहचानते हैं कि उनके हित में किसने क्या किया है। कमलनाथ सरकार में जो योजनाएं लागू की गई थीं, उन्हें भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। बेरोजगारी के कारण पलायन हो रहा है। पेसा नियम में कई कमियां हैं, जिन्हें कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे दूर कर नए सिरे से लागू किया जाएगा।

मप्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग ने जब-जब भाजपा को समर्थन दिया है प्रदेश में पार्टी की सरकार बनी है। इसको देखते हुए सत्ता, संगठन और संघ का फोकस इन पर रहता है। 2018 में दलितों और आदिवासियों का समर्थन नहीं मिलने के कारण भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी। हालांकि पार्टी ने 2020 के बाद इन दोनों समुदायों में वापसी की। इसी वजह से 2020 के बाद होने वाले 31 विधानसभा और एक लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

● कुमार विनोद

संघ की गहरी पैठ

भाजपा के लिए सबसे बड़ा प्लस प्वाइंट यह है कि संघ की दलित और आदिवासियों के बीच गहरी पैठ है। संघ परिवार के देशभर में एक लाख से अधिक सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। इन सेवा प्रकल्पों के कारण दलितों और आदिवासियों में भाजपा का प्रभाव जबरदस्त रूप से बढ़ा है। संघ के अनुषांगिक संगठन लगातार इनके बीच सक्रिय रहते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर के केशव विद्यापीठ में संपन्न हुई। इसमें संघ के चारों प्रांतों के शीर्ष पदाधिकारियों के अलावा भाजपा के कतिपय शीर्ष संगठन पुरुषों ने हिस्सा लिया। संघ ने जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से धर्मांतरित ईसाइयों को आरक्षण देने के खिलाफ डीलिस्टिंग आंदोलन चला रखा है।

मप्र में लागू होगी नई आईटी पॉलिसी

10 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य

नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रोत्साहन प्रदान कर और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। यह नीति व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है। सखलेचा ने बताया कि नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मप्र में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर 2 लाख नई नौकरियां सृजित करना है। इसमें 10 मिलियन वर्गफुट आईटी, ईएसडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का निर्माण, राज्यभर में अत्याधुनिक आईटी पार्क, भवन, प्लग एंड प्ले स्पेस को आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम के लिए प्लग एंड प्ले और रेडी टू बिल्ड फैक्टरियां शामिल कर बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर जोर दिया गया है। नीति में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और पूंजी सब्सिडी कैपिंग को बढ़ाकर उनका समर्थन किया गया है। प्रारूप नीति में ईएसडीएम इकाइयों में निवेश आकर्षित करना, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना शामिल है। ड्राफ्ट नीति विविध औद्योगिक परिदृश्य और समावेशिता के महत्व को प्रदर्शित करती है। यह नीति वृहद् और एमएसएमई दोनों प्रकार के उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करती है। यह समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है, जिससे सभी प्रकार की इकाइयां नीति का लाभ उठा सकें और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।

आत्मनिर्भर मप्र की दिशा में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार अपनी नई आईटी पॉलिसी ला रही है। इस नीति का लक्ष्य सभी कारकों का समावेश कर आईटी क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक जीवंत तथा समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर मप्र को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। निवेश, रोजगार, नवाचार और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बताया कि 2023 के लिए मप्र की आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम नीति उद्योग जगत से विचार-विमर्श के विभिन्न सत्रों और विभिन्न राज्य की नीतियों की बेंचमार्किंग के पश्चात बनाई गई है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में आईटी क्षेत्र में अगले पांच साल दस हजार करोड़ का निवेश लाने और दो लाख से अधिक नई नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से नई आईटी पॉलिसी लाई जा रही है। पॉलिसी का नाम मप्र आईटी-आईटीईएस और ईएसडीएम है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य निवेश, रोजगार, नवाचार और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। इसमें 10 मिलियन वर्ग फुट आईटी, ईएसडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का निर्माण और राज्यभर में अत्याधुनिक आईटी पार्क भवन उपलब्ध कराना है। राज्य में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना भी नीति का अहम हिस्सा है। ड्राफ्ट नीति नवीन विशेषताएं प्रस्तुत करती है, जो उद्योग के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान भी सुझाएगी। ड्राफ्ट नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए सीएपीईएक्स सहायता का विशेष प्रावधान प्रदान करके विश्व स्तरीय आईटी बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रावधान शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बताया कि नई नीति बनाने के पहले मप्र की आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के साथ कई दौर में चर्चा की गई। यह नीति व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है। नीति व्यवसायों को अपना संचालन स्थापित करने में मदद करने के लिए किराए में सहायता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन सहायता प्रदान करती है। यह नीति टेस्टिंग, कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंटिंग और स्टैंडअलोन शोध और विकास इकाइयों का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से प्रतिष्ठानों को सहायता प्रदान करके अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। ड्राफ्ट नीति राज्य में विभिन्न प्रकार के डेटा सेंटर्स को आकर्षित करने पर जोर देती है। नीति में डेटा सेंटर इकाइयों के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रावधान विशेष रूप से तैयार किए गए हैं।

नीति का लक्ष्य आईटी-ईएसडीएम क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक जीवंत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे मप्र को आईटी के लिए एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। नीति में अनुकूलित पैकेज के माध्यम से क्षेत्र में मेगा परियोजनाओं का समर्थन करने का भी प्रावधान है। आईटी सेक्टर में पीपीपी मॉडल की शुरुआत भोपाल और जबलपुर से होगी, क्योंकि यहां क्रमश: 25 और 20 एकड़ जमीनें हैं। नीति में आईटी सेक्टर में निवेश पर मिलने वाली 12 तरह की सब्सिडी को भी ऑनलाइन पोर्टल पर लाया जाएगा। टीएंडसीपी, एफएआर, बिल्डिंग परमिशन जैसी क्लीयरेंस भी सिंगल विंडो पर लाई जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन करने पर रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें 12 तरह की सब्सिडी मिलती है। इसमें पूंजीगत, ब्याज, आईटी इनवेस्टमेंट प्रोमोशन असिस्टेंस, एंट्री टैक्स एग्जम्पशन, स्टॉम्प ड्यूटी समायोजन और पेटेंट असिस्टेंस समेत अन्य शामिल हैं।

भोपाल के आईटी पार्क में अमेरिका की सदरलैंड ने भी रूचि ली है। कई बड़ी कंपनियां भी आने की तैयारी में हैं। हाल ही में आईटी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और विभाग के अधिकारी बेंगलुरू गए थे, जहां से अच्छा रिस्पांस मिला है। टीसीएस भी अपना एक विंग भोपाल के पार्क में खोलेगी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर के आईटी पार्क में कुल 278 प्लॉट आईटी कंपनियों व बीपीओ के लिए रखे गए थे, लेकिन पांच साल में आधे ही भर पाए थे। तीनों शहरों के आईटी पार्क फुल हो गए हैं।

● **प्रवीण सक्सेना**

मप्र की विकास दर सबसे अधिक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की विकास योजनाओं का असर यह हुआ है कि आज मप्र देश में सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बन गया है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन और चौतरफा विकास से आज प्रदेश की विकास दर 19.7 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्यवस्था में मप्र 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मप्र की आर्थिक वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2001-02 में 4.43 प्रतिशत की दर आज बढ़ कर 16.43 प्रतिशत हो गई है प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 71 हजार 594 करोड़ रुपए से बढ़कर 13 लाख 22 हजार 821 रुपए हो गया है। वर्ष 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार 718 रुपए थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर एक लाख 40 हजार 583 रुपए हो गई है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर विगत एक दशक में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है।

देश के हृदय स्थल मप्र ने पिछले डेढ़ दशक में विकास के नए आयाम स्थापित कर विकसित राज्य की पहचान बना ली है। मप्र की सुशासन और विकास रिपोर्ट-2022 के अनुसार राज्य में आए बदलाव से मप्र बीमारू से विकसित प्रदेशों की पंक्ति में उदाहरण बनकर खड़ा हुआ है। इस महती उपलब्धि में प्रदेश में जन-भागीदारी से विकास के मॉडल ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मप्र को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बना दिया है। इस अरसे में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, पर्यटन, जल-संवर्धन, सिंचाई, निवेश, स्व-रोजगार और अधोसंरचना विकास के साथ उन सभी पहलुओं पर सुविचारित एवं सर्वांगीण विकास की नवीन गाथा लिखी गई जो जन-कल्याण के साथ विकास के लिए जरूरी हैं।

कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले मप्र को अब विकास के पंख लग चुके हैं। प्रदेश आए दिन उपलब्धियों के कीर्तिमान बना रहा है। 2002-03 में प्रदेश की औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक थी जो अब 24 प्रतिशत पर पहुंच गई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि के आधार पर इसकी गणना की जाती है। विकास प्रक्रिया में अधोसंरचना के महत्व के मद्देनजर मप्र में निरंतर अधोसंरचना विकास हो रहा है। अधोसंरचना बजट जो वर्ष 2002-03 में 3873 करोड़ रुपए था, वह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 56 हजार 256 करोड़ रुपए हो गया है। एक समय था जब बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी। आज प्रदेश बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है। वर्ष 2003 में ऊर्जा क्षमता 5173 मेगावाट थी, जो बढ़कर 28 हजार मेगावाट हो गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी मप्र अग्रणी है। ओंकारेश्वर में लगभग 3500 करोड़ के निवेश से 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर सोलर पॉवर प्लांट का कार्य प्रारंभ हो गया है। किसानों के खेतों में 50 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है। विश्व धरोहर सांची बहुत जल्द सोलर सिटी के रूप में विकसित होकर देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। अच्छी सड़कें विकास की धुरी होती है। एक समय था, तब यह पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। अब गांव-गांव, शहर-शहर अच्छी गुणवत्तायुक्त सड़कों का जाल बिछाया गया हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2001-02 में 44 हजार किलोमीटर सड़कें थीं, अब 4 लाख 10 हजार किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई के 40 हजार करोड़ की लागत के 35 कार्य स्वीकृत हैं। अटल, नर्मदा और विंध्य प्रगति पथ के साथ मालवा, बुंदेलखंड और मध्य विकास पथ निर्मित किए जा रहे हैं।

प्रदेश में सभी रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने के लिए 105 रेलवे ओवर ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण हो रहा है। साथ ही 86 हजार करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं। वर्ष 2009 से 2014 के बीच जहां प्रदेश को औसतन 632 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मिलता था, वहीं वर्ष 2022-23 में 13 हजार 607 करोड़ का रेलवे बजट प्रावधान मिला है, जो इक्कीस गुना अधिक है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। अत्याधुनिक रानी कमलापति स्टेशन देश में एक मॉडल बना है। एक वंदे भारत ट्रेन पहले प्रारंभ हो चुकी है और 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मप्र को 2 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार भी निरंतर हो रहा है।

प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए सिंचाई क्षमताओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। वर्ष 2003 में सिंचाई क्षमता केवल 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर किए जाने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। हर घर जल से नल योजना पर तेज गति से कार्य हो रहा है, अभी तक लगभग 50 प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। आजादी के अमृत काल में प्रदेश में अब तक 5936 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में बांध, लिंक नहर तथा पॉवर हाउस का निर्माण कार्य इस वर्ष प्रारंभ होगा। अटल भू-जल योजना में भी लगभग 700 ग्राम पंचायतों में वॉटर सिक्युरिटी प्लान बनाए गए हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

गेहूं उपार्जन में मप्र अव्वल

अधोसंरचना विकास और बेहतर वित्त प्रबंधन के साथ कृषि प्रधान होने की वजह से प्रदेश में तेज गति से कृषि विकास और किसान-कल्याण के कार्य भी किए जा रहे हैं। लगातार 7 बार प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाले मप्र ने गेहूं उपार्जन में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश का सोने जैसे दानों वाला गेहूं अमेरिका सहित अनेक देशों में निर्यात होता है। अब इसके निर्यात के लिए प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है। कृषि विकास दर जो वर्ष 2002-03 में 3 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2020-21 में बढ़कर 18.89 प्रतिशत हो गई है। खेती और एलाइड सेक्टर का बजट भी 600 करोड़ से बढ़कर 53 हजार 964 करोड़ हो गया। खाद्य उत्पादन भी इस अवधि में 159 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

5 साल से खाली मंडी की कुर्सी

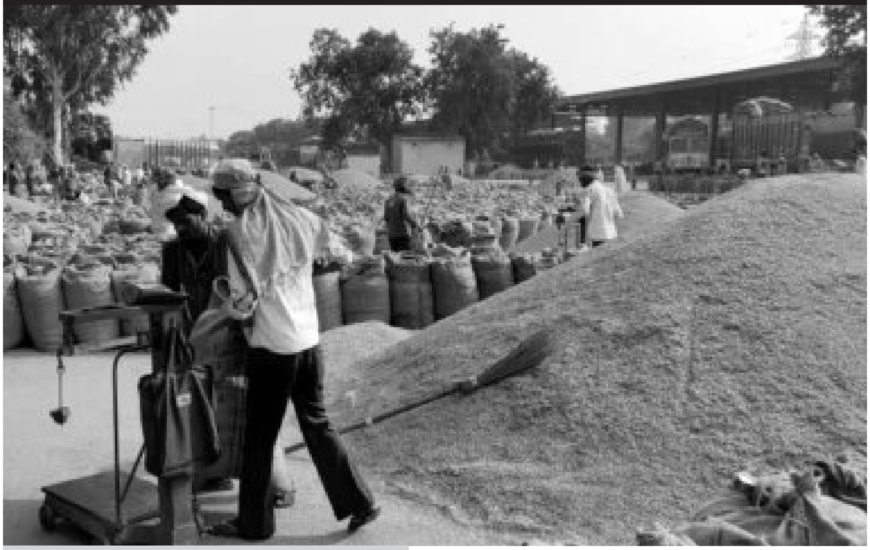

किसानों को उपज का उचित दाम व शासन की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रदेश में मंडी समितियों की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन मंडी की इन समितियों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हुए करीब 5 साल का समय हो चुका है, लेकिन अब तक इनके निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दावा किया है कि मंडियों में चुनाव की प्रक्रिया दो सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगी।

मप्र में कृषि उपज मंडी का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी नए चुनाव नहीं करवाए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ को बताया गया कि वोटर लिस्ट बनाने की प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है। दो सप्ताह में मंडी चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की है। बता दें कि याचिकाकर्ता मनीष शर्मा, नरसिंहपुर निवासी पवन कौरव, जबलपुर निवासी राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मंडी चुनाव वर्ष 2012 में हुए थे।

मंडियों के चुनाव नहीं होने की स्थिति में इसका भार प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे हो गया। जानकारी के अनुसार मंडी चुनाव के समय से अधिक होने के चलते कृषि उपज मंडियों में बनी समितियां 6 जनवरी 2019 को भंग हो गई हैं। वहीं 7 जनवरी 2019 से मंडियों का कार्यभार प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ गया है। 2012 में मंडी चुनाव हुए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो 5 साल बाद 2017 में चुनाव होने थे। इसमें मंडी समिति का कार्यकाल 6-6 माह की अवधि के लिए दो बार बढ़ा दिया गया था। कार्यकाल के एक साल बढ़ने के बाद 2018 में मंडी चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे थे। तय समय से अधिक होने के चलते 6 जनवरी 2019 को मंडियों में बनी समितियां भंग हो गईं। वहीं मंडी का कार्यभार जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ गया। अब उनकी निगरानी और देखरेख में ही मंडी से जुड़े निर्णय और कामकाज हो रहे हैं।

मंडी बोर्ड अधिनियम में प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यानी 5 साल से पहले नए चुनाव होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आवेदकों का कहना है कि सिर्फ विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल को तीन साल या फिर साढ़े तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चार साल से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी चुनावी प्रकिया प्रारंभ नहीं की गई, जो अवैधानिक है। चुनाव न कराना मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी। याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से उक्त जानकारी पेश की गई। सरकार की तरफ से मंडी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान करने का आग्रह किया गया था। युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की।

मंडी में बनी समितियों का प्रमुख काम समिति की बैठक कर उचित निर्णय लेना है। इसी के साथ व्यापारियों के किसी तरह की गड़बड़ी करने की जानकारी सामने आती है तो उन पर कार्रवाई कराते हुए किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संसाधन जुटाए जाना होता है। मंडी की व्यवस्था के अन्य काम भी समिति से जुड़े हुए हैं। चार साल से चुनाव नहीं होने के कारण इन पदों पर प्रशासक बैठे हैं। इससे कई आवश्यक कार्यों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब इन संस्थाओं के चुनाव होने की उम्मीद की जा रही थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संस्थाओं में चुनाव होना आवश्यक होता है। इसमें कई संस्थाएं पीछे हैं। इनमें कृषि उपज मंडी भी प्रमुख है। लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के चार साल बाद भी नई बॉडी का निर्वाचन नहीं हुआ है।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

प्रभावित हो रहे कामकाज

जानकारी के अनुसार मंडियों के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6-6 माह के लिए तीन बार बढ़ाया गया। वर्ष 2019 में अध्यक्ष की जगह प्रशासक की नियुक्ति की गई, तब से अभी तक अलग-अलग प्रशासक मंडी की कमान संभाल रहे हैं। लंबा वक्त होने के कारण प्रशासक भी इन संस्थाओं को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। 12 सदस्यीय कार्यकारिणी मंडी चुनाव भी अन्य निकाय चुनावों की तरह होते हैं। इनकी अपनी मतदाता सूची होती है। परिसीमन भी होता है। एक मंडी में 10 वार्ड होते हैं। इन्हीं वार्डों से किसान प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। दो प्रत्याशियों का चुनाव हम्माल और व्यापारी करते हैं। कार्यकारिणी से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। कृषि उपज मंडी में समय पर चुनाव होना आवश्यक है। निर्वाचित कार्यकारिणी कई तरह के निर्णय लेने में सक्षम होती है। इसके अभाव में मंडी की कई कमियां दूर नहीं हो पा रही हैं। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कार्यकाल बीत जाने के बाद भी चुनाव ना करवाए जाने पर किसान काफी परेशान हैं। बता दें कि 2018 में प्रदेश की सभी मंडियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए हैं। ऐसे में किसानों की समस्याओं को देखते हुए चुनाव आयोग को कलेक्शन करवा लेना चाहिए था, जबकि विशेष हालातों में सिर्फ 3.5 वर्ष ही कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, पर मंडी समितियों का कार्यकाल खत्म हुए साढ़े चार साल बीत चुके हैं।

एससी-एसटी वर्ग के खिलाफ अपराधों में आई कमी

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में चिन्हित किए गए हॉट स्पॉट में कमी आई है। पुलिस मुख्यालय की अजाक शाखा ने वर्ष 2016 से वर्ष 2021 यानी पांच साल में एससी-एसटी वर्ग के खिलाफ हुए अपराधों के आधार पर ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए थे, जहां पांच साल में पांच अपराध दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा उन क्षेत्रों की भी पहचान की थी, जहां पांच साल में दस या इससे अधिक अपराध हुए हैं।

प्रदेशभर में ऐसे 906 हॉट स्पॉट चिन्हित हुए थे, इनमें 64 एक्सट्रीम हॉट स्पॉट थे। हॉट स्पॉट पर जनचेतना शिविर, साक्षी संरक्षण योजना के क्रियान्वयन समेत जागरूकता अभियान से अपराधों में कमी आई है। नतीजतन 906 हॉट स्पॉट में से 473 क्षेत्र इस सूची से बाहर हुए हैं। हालांकि 133 नए हॉट स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं। हॉट स्पॉट में 37 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इसी तरह एक्सट्रीम हॉट स्पॉट में भी 9 फीसदी की कमी हुई है। पहले ये 64 थे, जो अब 58 बचे हैं। इधर, अजाक शाखा ने हॉट स्पॉट का दायरा बढ़ाया है। अब हॉट स्पॉट चिन्हित करने के लिए सात साल का समय निर्धारित किया है। इसके मुताबिक यदि सात साल में सात या इससे अधिक केस यानी औसतन हर साल एक केस दर्ज होता है तो उसे हॉट स्पॉट बनाया जाएगा।

दलित उत्पीड़न या कहें कि एससी-एसटी वर्ग के खिलाफ अपराधों के मामलों में मप्र का ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड सबसे अधिक कुख्यात बना हुआ है। ग्वालियर में सबसे अधिक 69 हॉट स्पॉट हैं। इनमें से 13 एक्सट्रीम स्तर के हैं। ग्वालियर-चंबल के गुना, मुरैना हॉट स्पॉट की टॉप 10 की सूची में शामिल हैं। इधर, बुंदेलखंड का सागर इस सूची में तीसरे नंबर पर है। यहां 49 हॉट स्पॉट तो 11 एक्सट्रीम हॉट स्पॉट हैं। इसके अलावा छतरपुर, कटनी और दमोह भी अधिक हॉट स्पॉट की सूची में शामिल हैं। जबलपुर में 21 हॉट स्पॉट हैं। बता दें, पहले 46 जिलों में हॉट स्पॉट थे, जो अब 42 जिलों तक सीमित हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 387 वार्डों में से 294 में तो 350 थाना क्षेत्रों में से 272 में हॉट स्पॉट रह गए हैं।

मप्र में वर्ष 2021 में 906 हॉट स्पॉट में प्रतिमाह औसतन 96 अपराध दर्ज किए जाते थे। अब हॉट स्पॉट पर अपराध का आंकड़ा 65 अपराध प्रतिमाह बचा है। पहले हॉट स्पॉट पर कुल एससी-एसटी के खिलाफ होने वाले अपराध कुल अपराधों का 14.7 फीसदी थे, जो अब कम होकर 9 फीसदी बचे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में जातिगत भेदभाव के मामले बहुत अधिक नहीं हैं। हालांकि अन्य विवादों की वजह से एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है।

मप्र में वर्ष 2022 में एससी-एसटी वर्ग के खिलाफ हुए अपराधों की संख्या 11380 थी। इस साल मई महीने तक कुल 4593 अपराध दर्ज हुए हैं, इनमें 0.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पहले ये औसतन 14 फीसदी की दर से बढ़ते थे। इस साल शुरुआती पांच महीने में अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराधों में 2.2 फीसदी की कमी हुई है, वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ अपराधों में 1.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हॉट स्पॉट में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पुलिस अफसरों समेत अन्य सरकारी महकमों के अधिकारियों की मौजूदगी में जनसंवेदना शिविर आयोजित किए गए। स्थानीय विवाद आपसी बातचीत से हल कराए गए। इससे सामाजिक समरसता बनी रही। उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों के लिए शुरू की गई साक्षी संरक्षण योजना से आरोपियों को सजा दिलाने में मदद मिली। इससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सका। हॉट स्पॉट पर पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। कानूनी मदद के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता शिविर लगाए गए। इससे लोगों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी मिली। साथ ही समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे आपसी सद्भाव व विश्वास और अधिक मजबूत हुआ।

● **राकेश ग्रोवर**

जल्दबाजी और रफ्तार के कारण जान गंवा रहे लोग

मप्र की सड़कों पर रोज 164 दुर्घटनाएं हो रही हैं। हादसों में प्रतिदिन 38 लोग दम तोड़ रहे हैं। जल्दबाजी और रफ्तार हादसों की सबसे बड़ी वजह है। ट्रैफिक पुलिस और यातायात विभाग के तमाम दावों के बावजूद सड़क हादसों का आंकड़ा कम होने के बजाय बढ़ा है। इस साल के शुरुआती तीन महीनों में 14752 सड़क हादसों में 3468 लोगों ने जान गंवाई है। 15223 लोग घायल हुए हैं। इस साल सड़क हादसों में 3.4 फीसदी तो मृतकों की संख्या में 4.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जबकि 2022 में जनवरी, फरवरी और मार्च में 14269 हादसे हुए थे। 3319 लोगों की मौत हुई थी जबकि 15010 लोग घायल हुए थे। पूरे साल की बात करें तो 54432 सड़क हादसों में 13432 लोगों की मौत हुई थी जबकि 68595 लोग घायल हुए थे। गंभीर घायलों की संख्या 6948 थी। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोध के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक सड़क हादसे नगरीय निकायों और ग्रामीण सड़कों पर हुए हैं। सड़कों पर 28743 हादसों में 6245 लोगों की मौत हुई जबकि नेशनल हाईवे पर 13860 हादसों में 4025 लोगों की मौत हुई। एक साल में स्टेट हाईवे पर 11829 हादसों में 3157 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वाहनों की सीधी टक्कर के 10798 मामलों में 2668 लोगों ने जान गंवाई। हिट एंड रन के सबसे अधिक मामले सामने आए। वर्ष 2022 में 12250 हिट एंड रन हादसों में 3509 लोगों की मौत हुई। 12709 घायल हुए। वहीं वाहनों की सीधी टक्कर के 10798 मामलों में 2668 लोगों ने जान गंवाई और 10666 घायल हुए। वाहनों को पीछे से टक्कर मारने के 9931 हादसे हुए। 2289 लोगों की मौत हुई और 9153 घायल हुए। सबसे कम हादसे सुबह तीन से छह बजे के बीच हुए। शाम छह से रात 9 बजे के बीच वर्ष 2022 में 11237 सड़क हादसे हुए। 3095 लोगों की मौत हुई जबकि 10889 लोग घायल हुए। दोपहर तीन से शाम छह बजे के बीच हुए 10389 सड़क हादसों में 2403 लोगों की सांसें थमीं और 10271 लोग घायल हुए। रात 9 से 12 बजे के बीच एक्सीडेंट में 1951 लोगों की मौत हुई और 6954 लोग घायल हुए। सबसे कम हादसे सुबह तीन से छह बजे के बीच दर्ज किए गए। इस दरमियान 500 की मौत हुई। 2060 लोग घायल हुए।

बक्सवाहा हीरा प्रोजेक्ट को झटका

छतरपुर जिले के बकस्वाहा में प्रस्तावित बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। इस प्रोजेक्ट के लिए मप्र शासन के 382.131 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। राज्य शासन ने इस वन भूमि को बिड़ला समूह की खनन कंपनी मैसर्स एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड के पक्ष में डायवर्ट करने की मंजूरी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को वर्ष 2020 में भेजा था। इसके बाद आखिरी बार नवंबर 2022 में राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए केंद्र को पत्र लिखा था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट की ओर से मप्र वन विभाग के एसीएस को भेजे पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर 27 दिसंबर 2022 को फॉरेस्ट एडवायजरी कमेटी (एफएसी) की बैठक में विचार किया गया था। इसमें एफएसी ने कहा था कि केन-बेतवा प्रोजेक्ट के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है।

भविष्य में टाइगर दूसरे इलाकों में अपना घर तलाशेंगे। इस प्रोजेक्ट से भी उसी इलाके का लैंडस्केप प्रभावित होगा। इसलिए जब केन-बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट पूरी तरह आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, तब तक बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के लिए वन भूमि हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एनटीसीए की सिफारिशों पर पन्ना टाइगर रिजर्व के विस्तार के लिए दूसरी वन भूमि की तलाश की जा रही है। हाईकोर्ट और एनजीटी में भी इस प्रोजेक्ट के विरूद्ध याचिकाएं लंबित हैं, इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में हीरा खनन के लिए वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के विरोध में जबलपुर के डॉ. पीजी नाजपांडे ने एनजीटी और रमित बासु ने जबलपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर रखी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 4 लाख हरे-भरे पेड़ काटने पड़ेंगे। बक्सवाहा जंगल में 25 हजार वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग को भी इससे नुकसान होना बताया गया है।

बंदर डायमंड ब्लॉक एक ग्रीनफील्ड माइनिंग प्रोजेक्ट है। इससे लगभग 30 लाख कैरेट कच्चे हीरे का उत्पादन होने का अनुमान है। टेंडर के मुताबिक, ब्लॉक को 30.05 प्रतिशत के रेवेन्यू शेयर पर राज्य सरकार ने नीलाम किया था। यदि प्रोजेक्ट शुरू हो सका तो राज्य सरकार को कुल 28 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट से 1,000 से 1,500 लोगों को रोजगार मिलने का भी दावा किया था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आईबीएम) ने इस खदान से 55 हजार करोड़ रुपए के हीरे निकलने का अनुमान लगाया था। 2012 में मल्टीनेशनल खनन कंपनी रियो टिंटो ने 954 हेक्टेयर क्षेत्र में राज्य सरकार से माइनिंग लीज पर ली थी। कंपनी ने यहां हीरे के भंडार का पता लगाया। लेकिन 2017 में रियो टिंटो ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया था। 2019 में मप्र सरकार ने फिर से हीरा भंडारण ब्लॉक की नीलामी कर यह प्रोजेक्ट एस्सेल माइनिंग को अलॉट किया था।

बिड़ला समूह ने हासिल किया था सबसे बड़ा ठेका

हीरा खदान की नीलामी में शुरुआत में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें वेदांता, रुंगटा माइंस, भारत सरकार की नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के साथ अडानी और बिड़ला ग्रुप शामिल हुए और अंत में बिड़ला ग्रुप ने बाजी मारी। दरअसल हीरा खदान की मंजूरी रोकने के लिए पर्यावरणविदों ने भी एनजीटी से लेकर हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दायर कीं। दरअसल 4 लाख हरे-भरे पेड़ खनन के चलते काटना पड़ते और पन्ना क्षेत्र में टाइगर हलचल भी इससे प्रभावित होती। यही कारण है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हीरा खनन के लिए वन भूमि का डायवर्जन प्रस्ताव खारिज कर दिया।

एक तरफ रेवड़ी योजनाओं की धड़ाधड़ घोषणाओं के चलते मप्र सरकार का खजाना खाली है और लाखों करोड़ के लोन लेकर काम चल रहा है। दूसरी तरफ 30 हजार करोड़ रुपए की होने वाली राजस्व कमाई का भी नुकसान हो गया और देश की सबसे बड़ी मप्र में मौजूद हीरा खदान के खनन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अभी केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के आवेदन को मंजूरी नहीं दी। दरअसल पिछले दिनों हीरा खदान में खनन कर हीरे निकालने का ठेका बिड़ला समूह को देना तय किया था। 55 हजार करोड़ रुपए से इसकी नीलामी बोली शुरू हुई, जो 80 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। यानी छतरपुर जिले के बक्सवाहा में मौजूद बंदर हीरा खदान में 80 हजार करोड़ रुपए मूल्य से अधिक के लगभग 400 लाख कैरेट हीरे दबे पड़े हैं, जो फिलहाल वैसे ही रहेंगे।

एक हजार एकड़ वन भूमि को हीरा खनन के लिए परिवर्तित करने का प्रस्ताव शिवराज सरकार ने केंद्र को भेजा था। इसे फिलहाल खारिज कर दिया, जिसके चलते हीरा खदान प्रोजेक्ट एक बार फिर अधर में लटक गया है। दरअसल तीन साल पहले शिवराज सरकार ने हीरा खदान की नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी। विशेषज्ञों के मुताबिक देश की सबसे बड़ी बंदर हीरा खदान में 400 लाख कैरेट तक हीरे दबे होने की जानकारी सामने आई है, जिसके चलते 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक उसका मूल्य आंका गया और उसी आधार पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रदेश सरकार ने इस हीरा खदान पर ऑफसेट प्राइज जब 55 हजार करोड़ तय की तो कई कंपनियों के बीच इसका ठेका लेने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और साढ़े 11 प्रतिशत से अधिक के प्रस्ताव शुरुआत में ही आ गए, जिसके चलते ऑफसेट प्राइज साढ़े 22 फीसदी से अधिक पहुंच गई। यानी 80 हजार करोड़ रुपए तक की नीलामी की राशि हो गई। पूर्व में इस खदान का ठेका तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने रियो टिंटो कंपनी को दिया था, मगर विवादों के बाद कंपनी ने यह ठेका छोड़ दिया और तब से ही यह बंदर हीरा खदान अनुपयोगी पड़ी है। इससे शिवराज सरकार को लगभग 30 हजार करोड़ रुपए का राजस्व आने वाले कई वर्षों में मिलता। मगर फिलहाल उसका भी नुकसान हो गया है। चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, लिहाजा शिवराज सरकार इस निर्णय का अधिक विरोध भी नहीं कर सकती।

● सिद्धार्थ पांडे

ई-टेंडर घोटाले की जांच होगी बंद

करीब पांच साल पहले मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में तहलका मचाने वाले 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के बहुचर्चित ई-टेंडर घोटाले में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए करीब तीन हजार करोड़ रुपए के ई-टेंडर कथित घोटाले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा को इस मामले में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं मिली है। वहीं सात महीने पहले इसके सभी छह आरोपी भी न्यायालय से दोष मुक्त हो चुके हैं। बड़ी बात ये है कि हार्ड डिस्क में टेम्परिंग की पुष्टि होने के बाद भी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू यह पता नहीं कर सकी कि आखिर टेंडर में छेड़छाड़ किसने की थी। इसीलिए इसकी जांच ठंडे बस्ते में चली गई।

गौरतलब है कि जल संसाधन, सड़क विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय प्रशासन, नगर निगम स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, जल निगम, एनेक्सी भवन सहित निर्माण कार्य करने वाले विभाग इस घोटाले में शामिल हैं। इन टेंडर्स में ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन और एंटेरस सिस्टम कंपनी के पदाधिकारियों के माध्यम से निविदा में टेंपरिंग किए जाने तथा इसमें कई दलालों, विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों और राजनेताओं के शामिल होने का आरोप था। हालांकि इस कथित घोटाले के पीछे कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों के आपसी झगड़े को भी कारण माना गया था।

गौरतलब है कि ई-टेंडर घोटाला सामने आने के बाद कई विभागों के अधिकारी शक के दायरे में आ गए थे। प्रदेश की जांच एजेंसियों के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं। कई जगह छापामारी की गई। दावा किया गया कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। लेकिन ईओडब्ल्यू को भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) से मिली निविदा हैगिंग और फिशिंग परीक्षण रिपोर्ट में ई-निविदा में हेरफेर को लेकर कोई साक्ष्य नहीं मिला था। अब इस मामले की फाइल बंद करने से पहले ईओडब्ल्यू ने इस मामले में सीईआरटी-इन से अनियमितता को लेकर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है। सीईआरटी-इन की रिपोर्ट में इस बार भी अगर अपराध स्पष्ट नहीं होता है तो आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस कथित घोटाले की जांच में खात्मा लगाकर इसकी फाइल को बंद कर सकती है। आर्थिक अपराध शाखा के महानिदेशक अजय कुमार शर्मा का कहना है कि ई-टेंडर मामले में सीईआरटी-इन की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं थी। इस कारण निविदा में किसी भी तरह के हेरफेर के प्रमाण स्पष्ट नहीं हो सके थे। सीईआरटी-इन को एक बार फिर से स्पष्ट रिपोर्ट भेजने के लिए पत्र लिखा गया है। स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस प्रकरण में कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर जून 2019 के मध्य से जांच शुरू हुई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव बीपी सिंह ने ईओडब्ल्यू को एमपीएसईडीसी के पूर्व निदेशक मनीष रस्तोगी द्वारा नौ निविदाओं को रद्द करने के बाद प्रस्तुत एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू करने के लिए कहा था। सूत्रों का कहना था कि ई-टेंडर मामले को गैर-सबूत तकनीकी साक्ष्य पर कुछ स्तरों पर अनिच्छा के बावजूद, एजेंसी ने अब तक की सबसे बड़ी जांच को माना है। यह कथित तौर पर सीनियर नौकरशाहों के एक झगड़े के रूप में उभरकर आया। ईओडब्ल्यू ने मामले में सात निजी कंपनियों के निदेशकों, अज्ञात नौकरशाहों और राजनेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक दिन बाद, तीन सॉफ्टवेयर पेशेवरों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही एक कंपनी पर कार्रवाई की गई, जो कथित तौर पर सरकारी पोर्टलों को हैक कर दस्तावेजों से छेड़छाड़ की थी। विनय चौधरी के अनुसार उनकी कंपनी, जिसके पास लाइसेंस लोड रनर है, को ई-टेंडर पोर्टल का प्रदर्शन परीक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था। साथ ही दो दिनों में ही काम को रद्द कर दिया गया था। इस केस की एफआईआर और चार्जशीट कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। वहीं, ईओडब्ल्यू एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से डेटा की रिकवरी और जांच के लिए सीईआरटी-इन पर निर्भर थी। इस मामले में छह आरोपियों के अलावा गुजरात की एक फर्म के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया था, जबकि बाकी के खिलाफ जांच जारी थी।

जानकारी के अनुसार, ई-टेंडर घोटाले में 18 मई 2018 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। प्राथमिकी जांच के बाद 10 अप्रैल 2019 को एफआईआर दर्ज की गई। प्रारंभिक चरण में इसे करीब 3 हजार करोड़ का घोटाला माना गया। जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू का मानना था कि प्रिक्योरमेंट पोर्टल में छेड़छाड़ कर कुल 9 टेंडर से छेड़छाड़ की गई। इसमें जल निगम के 3, पीडब्ल्यूडी के 2, पीएचई के 2, एमपीआरडीसी का एक और पीडब्ल्यूडी का एक टेंडर शामिल था।

● श्याम सिंह सिकरवार

ईओडब्ल्यू नहीं दे पाई सबूत

नवंबर 2020 में लोकायुक्त की एक विशेष अदालत ने ईओडब्ल्यू की तरफ से दर्ज कथित ई-टेंडर मामले में सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल ईओडब्ल्यू कोई सबूत नहीं दे पाई। मामले में विनय चौधरी, वरुण चतुर्वेदी और सुमित गोलवरकर आरोपी थे, जिनकी संयुक्त उद्यम कंपनी ओस्मो आईटी सॉल्यूशंस की तलाशी कम्प्यूटर और लैपटॉप की जब्ती के लिए की गई थी। कंपनी के मालिक चौधरी ने ईओडब्ल्यू को दिए अपने बयान में एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेपलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किसी भी निविदा में अपनी भूमिका से इनकार किया था। आरोप था कि निविदा के दस्तावेजों के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की थी। ईओडब्ल्यू का कहना है कि जांच जारी है, पिछले महीने ही बीपीएन डेटा और बैकअप फाइल कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सर्ट-इन) को भेजी हैं। हालांकि मामले में छह आरोपियों को विशेष अदालत सात महीने पहले सबूतों के अभाव में बरी कर चुकी है, क्योंकि जांच एजेंसी कोर्ट में यह साबित करने में नाकाम रही कि आखिर टेंडर में छेड़छाड़ किसने की। ईओडब्ल्यू ने जांच के दौरान 40 से 50 हार्ट डिस्क जब्त की थीं। इन्हें जांच के लिए सर्ट-इन भेजा है। इसके पूर्व जो हार्ड डिस्क भेजी गईं थी, उनकी रिपोर्ट सितंबर 2021 में आईं थी, जिसमें टेम्परिंग की पुष्टि हुई थी, लेकिन सर्ट-इन यह स्पष्ट नहीं कर सकी थी कि टेम्परिंग किसने की। जांच एजेंसी भी अब तक उन आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी, जिनके द्वारा टेंडर में टेम्परिंग की थी। जांच एजेंसी का कहना है कि धारा 173 (8) के तहत जांच जारी है।

सतपुड़ा की आग लगा गई दाग !

आग ने खोली मप्र में फायर सेफ्टी और फायर फाइटर की पोल

अग्निकांड से सबक लेते हुए सरकार ने शुरू कराया सेफ्टी ऑडिट

कभी-कभी एक गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि बरसों की मेहनत पर दाग लग जाता है। ऐसा ही दाग मप्र की सरकार पर सतपुड़ा भवन की आग से लगा है। वैसे तो यह बिल्डिंग जिस समय बनी थी उस समय फायर सेफ्टी का कोई प्रावधान नहीं था। समय के साथ-साथ इस बिल्डिंग में मैन पावर बढ़ता गया और एसी, कूलर, कम्प्यूटर, फाइलों का बोझ बढ़ता गया, लेकिन सरकार कई बार की आग के बाद भी नहीं चेती और परिणाम यह हुआ कि सतपुड़ा भवन की ऊपरी तीन मंजिलें आग से तबाह हो गईं।

● राजेंद्र आगाल

मप्र के दूसरे सबसे बड़े सरकारी दफ्तर सतपुड़ा भवन में लगी आग से करीब 25 करोड़ का फर्नीचर और 12 हजार से ज्यादा अहम फाइलें स्वाहा हो गईं हैं। मतलब राज्य निदेशालय के लगभग 80 फीसदी दस्तावेज खाक हो गए। आग लगने के समय भवन के अंदर एक हजार से ज्यादा लोग थे, लेकिन उन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सतपुड़ा की यह आग सरकार पर बड़ा दाग लगा गई है। विपक्ष जहां इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहा है, वहीं फायर सेफ्टी विशेषज्ञ इसे सरकार की बड़ी गलती मान रहे हैं। वहीं इस आग ने मप्र में फायर सेफ्टी और फायर ब्रिगेड की पोल खोलकर रख दी है। भोपाल की फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक आग तीसरी मंजिल से चौथी, पांचवीं और छठवीं मंजिल तक पहुंच चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि सतपुड़ा भवन से कुछ ही दूरी पर फायर ब्रिगेड होने के बाद भी गाड़ियां 45 मिनट बाद पहुंची, जिससे आग विकराल हो गई।

देश में जब भी कोई बड़ा अग्निकांड होता है, मप्र में सरकार तत्काल फायर सेफ्टी ऑडिट का फरमान जारी कर देती है, लेकिन विडंबना यह है कि मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग हो या सतपुड़ा और विंध्याचल भवन, कहीं भी आग बुझाने के पर्याप्त और आधुनिक साधन नहीं हैं। यही कारण है कि 6 मंजिला सतपुड़ा भवन में लगी आग के विकराल रूप को देखते हुए दमकल और प्रशासन की सांसें फूल गईं। उधर, आग बुझाने में इस्तेमाल की जाने वाली नगर निगम की विशेष फायर हाइड्रोलिक गाड़ियों के प्लेटफार्म को खुलने में ही करीब 45 मिनट लग गए। लापरवाही इतनी थी कि इस सरकारी इमारत का फायर ऑडिट तक नहीं किया गया था। इसी के चलते आग को बुझाने में इतनी देरी हो गई। बता दें कि सतपुड़ा भवन के मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी का सीपीए विभाग कर रहा है। पीडब्ल्यूडी ने फायर ऑडिट की जिम्मेदारी आरपीएम फायर सर्विसेज नामक कंपनी को दी है। इसके लिए टेंडर जारी किया गया और वर्कऑर्डर मिलने के बाद कंपनी ने फायर ऑडिट शुरू कर दिया है।

खुल रहीं लापरवाही की परतें

सतपुड़ा भवन में लगी आग की राख के साथ लापरवाही की परतें भी खुलती ही चली जा रही हैं। अब इस बिल्डिंग के फायर ऑडिट में सामने आया है कि जिस कमरे में सबसे पहले आग लगी, वहां लगे कांच तक पिघल गए थे। ऐसा तब होगा जब कमरे में 1700 डिग्री तक टेंपरेचर हो गया हो। इतने टेंपरेचर में आसपास का तापमान भी इतना ज्यादा रहता है कि कागज और फर्नीचर के लिए ऑटो इग्नीशन टेंपरेचर डेवलप कर दे। कागज के लिए 250 डिग्री ऑटो इग्नीशन टेंपरेचर होता है, यानी इतने तापमान में कागज खुद ही आग पकड़ लेगा। लापरवाही की इंतेहा ये भी थी कि बगैर किसी प्लानिंग के यहां लॉबी और कमरों के बाहर भी ढेरों फाइलें रखी थीं। इन्हीं फाइलों ने ऑटो फ्यूल का काम किया और आग ने इतना बड़ा रूप ले लिया। सतपुड़ा भवन के बड़े-बड़े केबिन्स में बैठने वाले अफसर चाहते तो ये फाइलें तरतीब के साथ रखी जा सकती थीं। बगैर प्लानिंग के 40 साल का रिकॉर्ड पूरी बिल्डिंग में रखा था। छठवीं मंजिल

प्रमुख भवनों के संधारण का काम देखेगा पीडब्ल्यूडी

सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना के बाद सरकार ने अब यह निर्धारित किया है कि सभी प्रमुख सरकारी भवनों के संधारण का काम लोक निर्माण विभाग ही करेगा। यदि किसी विभाग को बिजली या निर्माण से संबंधित कोई कार्य कराना है तो उसके लिए एजेंसी लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई ही होगी। यह निर्णय मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना की जांच में बड़ा कारण विभागों द्वारा मनमर्जी से काम कराना पाया गया है। विभागों ने अपने स्तर से एजेंसी निर्धारित की और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर निर्माण कार्य कराए। जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है कि आग जैसी घटना को रोकने की कोई तैयारी नहीं थी। बिजली के उपयोग को लेकर भी निर्धारित मापदंड का उपयोग नहीं किया गया। समिति की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने लोक निर्माण, नगरीय विकास एवं आवास, गृह और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख सरकारी भवनों के संधारण का काम लोक निर्माण विभाग ही देखेगा। किसी भी विभाग को कोई काम कराना है तो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर देना होगा और विभाग अपनी देखरेख में काम कराएगा। इसके लिए वित्त विभाग के उस आदेश को भी संशोधित किया जाएगा, जिसमें विभागों को अपने स्तर से काम कराने की छूट दी गई थी।

तस्वीरों में सतपुड़ा भवन की आग

सतपुड़ा भवन की आग में 24 करोड़ का नुकसान

सतपुड़ा भवन में 12 जून को लगी आग की जांच रिपोर्ट कमेटी ने सरकार को सौंप दी है। सरकार को सौंपी गई 287 पन्नों की जांच रिपोर्ट में दोषी किसी को नहीं ठहराया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आग लगने से 24 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। आग लगने का कारण एसी के टॉप-बॉटम पॉवर प्लग में लूज कनेक्शन होना बताया है। आग तीसरे तल पर स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के उपसंचालक के बंद एसी में हुए ब्लास्ट से फैली थी। सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना के बाद शासन ने जांच समिति गठित कर दी थी। जांच कमेटी को तीन दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपना थी। जांच पूरी नहीं होने के चलते कमेटी ने दो दिन का अतिरिक्त समय लिया था। शासन द्वारा गठित कमेटी ने जांच के दौरान सतपुड़ा भवन के तीन स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान 32 अधिकारी, कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। अपनी जांच में कमेटी ने एफएसएल रिपोर्ट, चीफ इलेक्ट्रिसिटी इन्स्पेक्टर और उनके जांच दल की तकनीकी रिपोर्ट को शामिल किया है। इसके अलावा नुकसान के आंकलन के लिए बनी पीडब्ल्यूडी की 2 उप समितियों के प्रतिवेदन को शामिल करते हुए कुल 287 पन्नों का जांच प्रतिवेदन राज्य शासन को सौंपा है। कमेटी में एसीएस होम राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव नगरीय विकास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग सुखबीर सिंह और एडीजी फायर आशुतोष राय को शामिल किया गया था, जिन्होंने अपनी जांच पूरी कर सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि आग 12 जून को सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल से शुरू हुई थी। यहां आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त वीरेंद्र सिंह के कक्ष में एसी में हुए ब्लास्ट से शाम 4 बजे आग भड़की। कमेटी ने अपनी जांच में बताया है कि जिस एसी से आग भड़की थी, उसे लकड़ी के फ्रेम पर प्लाई बुड लगाकर कसा गया था। इसके बार-बार उपयोग से वायरिंग लूज हो गई। लूज कनेक्शन से टॉप-बॉटम की वायरिंग में स्पार्किंग होती रही और शार्ट सर्किट हो गया। इसके बाद आग की चिंगारी सोफे पर पड़ी। यहां से आग आसपास रखे फर्नीचर और फाइलों में लग गई। इसके बाद आग फैल गई। बंद एसी से लगी आग के संबंध में जांच कमेटी ने मुख्य विद्युत निरीक्षण की 7 सदस्यीय टीम का जांच प्रतिवेदन लिया।

15 जुलाई तक खाली करना होगा सतपुड़ा भवन

अग्निकांड के बाद सतपुड़ा भवन को खाली करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले वन विभाग यहां से अपना सामान समेटने जा रहा है। वन विभाग ने सभी शाखाओं को अपनी नस्तियां बांधने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 जुलाई तक शिफ्टिंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गौरतलब है कि सतपुड़ा भवन के ए-ब्लॉक में सबसे बड़ा स्पेस वन विभाग के पास ही है। वन विभाग के पीसीसीएफ (भू-प्रबंध) सुनील अग्रवाल ने सभी शाखाओं को अपना रिकॉर्ड, नस्तियां बांधना शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग की सभी शाखाओं और अधिकारियों को कक्ष और कार्यस्थल आवंटित कर दिए गए हैं, सभी को शिफ्टिंग से पहले 29 जून को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के आवंटित कक्ष और स्थान का निरीक्षण करने को कहा गया था। सतपुड़ा के साथ ही वन विभाग की अलग-अलग शाखाओं और फेडरेशन द्वारा किराए के पांच और भवन खाली किए जाने की तैयारी है।

पर काम जारी था और पांचवीं मंजिल भी तोड़ी जा रही थी। इन मंजिलों पर रखा सामान सीढ़ी और लॉबी में बेतरतीब रख दिया गया।

फायर एक्सपर्ट और गवर्नमेंट फायर कंसल्टेंट रोहिताश्व पांडे के अनुसार सतपुड़ा भवन में बहुत ज्यादा तादात में 40 साल पुरानी भी फाइलें रखीं थीं, जो क्लास-ए फायर कैटेगरी होती हैं। सतपुड़ा भवन में आग फैलने की सबसे बड़ी वजह यही फाइलें रहीं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, यदि होती तो उसके लिए पुरानी फाइलें-फर्नीचर जिम्मेदार होते। क्योंकि 99 प्रतिशत मौतें स्मोक इन्हेलेशन से होती हैं। पांडे के अनुसार सतपुड़ा भवन में पुराने पैटर्न के अग्नि सुरक्षा उपकरण लगे थे, जो चालू नहीं थे। पाइप खराब हो चुके थे और मोटर भी जाम थी। वहीं कर्मचारियों को बेसिक प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था। आग लगने के बाद 3 पोर्टेबल इंस्टीग्यूशर चलाए, लेकिन एसी के केपेसीटर फटने लगे तो लोग डरकर भागे। गोल्डन 1 मिनट में आग काबू नहीं हुई। इसकी वजह से आग भयानक हो गई।

फायर अलार्म सिस्टम नहीं

हर दिन की तरह सतपुड़ा भवन में काम-काज चल रहा था। अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने काम में लगे हुए थे। दफ्तर से छूटने का भी समय होता जा रहा था कि अचानक शाम 4 बजे के आसपास भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित जनजातीय कार्य विभाग में आग धधक उठी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही लपटों ने फर्नीचर समेत दस्तावेजों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही बिल्डिंग में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। आग की वजह एयरकंडीशनर में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। लापरवाही इतनी थी कि इस सरकारी इमारत में फायर अलार्म सिस्टम तक नहीं था और न ही इसका फायर ऑडिट किया गया था। 6 मंजिला भवन में लगी आग के विकराल रूप को देखते हुए दमकल और प्रशासन की सांसें फूल गईं। उधर, आग बुझाने में इस्तेमाल की जाने वाली नगर निगम की विशेष फायर हाइड्रोलिक गाड़ियों के प्लेटफार्म को खुलने में ही करीब 45 मिनट लग गए। भोपाल की फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक आग तीसरी मंजिल से चौथी, पांचवीं और छठवीं मंजिल तक पहुंच चुकी थी। भीषण आग को देखते हुए भोपाल समेत बीएचईएल, एयरपोर्ट, मंडीदीप, सीहोर, रायसेन और विदिशा तक से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। मगर पानी की बौछारें आग को ठंडी नहीं कर पाईं। राज्य प्रशासन का फायर फाइटिंग अमला आग बुझाने की कोशिश में लगा हुआ था। इसके बाद सेना के जवान भी मौके पर

पहुंचे। लेकिन आग पर काबू पाने में करीब 17 घंटे लग गए।

अग्निशमन अमले की पोल खुली

सतपुड़ा भवन में लगी आग ने नगर निगम के अग्निशमन अमले की पोल खोल दी। कुशल ऑपरेटर नहीं होने से 5 करोड़ रुपए से खरीदी 170 फीट ऊंचाई तक काम बुझाने में सक्षम हाइड्रोलिक मशीन घटना स्थल पर शोपीस बनकर खड़ी रही। यदि प्रशिक्षित कर्मचारी होते तो इस मशीन की मदद से महज 80 फीट ऊंचे सतपुड़ा भवन में लगी आग पर शुरुआत में ही काबू पाया जा सकता था। आग दोपहर करीब 3.30 बजे सतपुड़ा भवन के तीसरी मंजिल पर स्थित ट्राइबल विभाग के कार्यालय में लगी थी। इसकी सूचना सबसे पहले पुलिस फायर कंट्रोल रूम को दी गई। जब दमकलें पहुंचीं तब तक आग ने चौथी मंजिल पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय को भी अपनी चपेट में ले लिया। तब तक नगर निगम का अग्निशमन विभाग भी पहुंच गया लेकिन इमारत की ऊंचाई अधिक होने और हवा के विपरीत होने से पानी की बौछार भी अंदर आग तक नहीं पहुंच पा रही थीं। ऐसे में नगर निगम के 170 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक प्लेटफार्म को बुलाया गया। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए कुशल ऑपरेटर नहीं होने से इसका उपयोग नहीं किया जा सका। इस हाइड्रोलिक प्लेटफार्म से 18वीं मंजिल तक की आग आसानी से बुझाई जा सकती है।

सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद खुलासा हुआ कि करीब 60 वर्ष पुरानी इस इमारत में फायर सेफ्टी के उपकरण भी नहीं लगे हैं। यदि यहां फायर अलार्म सिस्टम होता तो आग लगने की सूचना समय पर मिल जाती। इस इमारत का अब तक ना तो फायर ऑडिट कराया गया और ना ही एनओसी है। इस सात मंजिला इमारत में वाटर हाइड्रेंट तक नहीं लगा था। जिससे दमकलों को पानी की कमी का सामना भी करना पड़ा और आग बुझाने में देरी हुई। सतपुड़ा भवन के संधारण और मरम्मत की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के पास है। हाल में ही यहां स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में करोड़ो रुपए से रेनोवेशन कराया है। महज हजार रुपए में आने वाला फायर अलार्म भी नहीं लगा पाए। अग्नि सुरक्षा को लेकर इस इमारत में कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकारी विभागों में फायर ऑडिट करना और एनओसी देने की जिम्मेदारी पुलिस के अग्निशमन विभाग की है। लेकिन मुख्यालय से महज 100 मीटर दूर स्थित सतपुड़ा भवन का ना तो फायर ऑडिट किया गया और ना ही एनओसी चेक की गई। इधर आग लगने की सूचना मिलने के बाद भी मौके पर दमकलें देरी से पहुंची। शहर में अग्नि दुर्घटना से राहत और बचाव की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। बढ़ती बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए 52 मीटर ऊंची मशीन खरीदी। दावा किया गया कि 18वीं मंजिल तक आग बुझाने में आसानी होगी। छह माह बाद भी कुशल ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं कर पाए। जिससे मौके पर पहुंचने के बाद भी यह मशीन खड़ी रही।

फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई

सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना के बाद नगरीय प्रशासन विभाग जाग गया है। अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नगरीय निकायों दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। फायर सेफ्टी प्लान और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेकर अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस देने के बाद भी अगर लापरवाही बरती तो कलेक्टर को सूचना देकर भवन में संचालित गतिविधियों को बंद कराया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देशानुसार दुर्घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में समस्त नगरीय निकायों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निकायों को हिदायत दी गई है कि ऐसे सभी भवन, जिनके भवन स्वामियों द्वारा फायर सेफ्टी प्लान और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त कर अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं किए हैं, उनको नियमानुसार नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाए। नोटिस देने के बाद भी यदि भवन स्वामी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जिला कलेक्टर को सूचना देकर भवन में संचालित गतिविधियों को बंद कराने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

अग्निकांड के बाद सबक

मप्र की राजधानी भोपाल में सतपुड़ा अग्निकांड के बाद सरकार ने बड़ा सबक लिया है। इस अग्निकांड से सबक लेते हुए अब सभी सरकारी भवनों में विद्युत उपकरणों की जांच होगी। भवनों में उपकरणों की कितनी आवश्यकता है और कितने लगाए गए इसकी गिनती होगी। इसकी शुरुआत विंध्याचल और सतपुड़ा भवन से होगी। लोक निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू की है। सतपुड़ा भवन की आग में पाया गया कि एसी के कारण ज्यादा तेजी से आग भड़की और छठवीं मंजिल तक पहुंच गई। लोक निर्माण विभाग की जांच में यह बड़ी बात सामने आई है कि आवश्यकता से अधिक उपकरणों और अनियंत्रित विद्युत लोड के कारण आग ज्यादा तेजी से फैली। पीडब्ल्यूडी ने सतपुड़ा और विंध्याचल में दो टीमों का गठन किया है। इन दलों में कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, विद्युत शाखा सहायक यंत्री, उपयंत्री को रखा गया है। ये दल बैठक क्षमता, वर्तमान उपस्थिति उपकरणों की संख्या, विद्युत आपूर्ति साथ ही उपकरणों की आवश्यकता की रिपोर्ट बनाएंगे।

पश्चिमी विंग पूरी तरह बर्बाद

सतपुड़ा भवन की आग ने पश्चिमी विंग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। आलम अब यह है कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के स्टेंडर्ड मापदंडों के हिसाब से प्रभावित पश्चिमी विंग वापस इस्तेमाल लायक नहीं रही। अभी सात सदस्यीय विशेष टीम इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल हेल्थ ऑडिट कर रही है। यह ऑडिट इन्हीं मापदंडों के आधार होगा। वहीं आग ने नेशनल इनफॉर्मेशन सेंटर (एनआईसी) यानी सरकारी सर्वर को भी ठप कर दिया है। इससे स्कॉलरशिप, पेंशन और अनाज खरीदी जैसे काम 9 दिन से ठप हैं। सतपुड़ा भवन में जब तक बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही, तब तक इसके बहाल होने की संभावना भी नहीं है। एनआईसी का दफ्तर सतपुड़ा की पश्चिमी विंग में ही है। नेशनल बिल्डिंग एक्ट 2016 के अनुसार सामान्यत: 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक आग लगने वाली बिल्डिंग को वापस उपयोग लायक नहीं माना जाता। वजह ये कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक आग पहुंचने पर लोहा तक पिघल जाता है। सतपुड़ा भवन की आग तो 1700 डिग्री सेल्सियस पार तक पहुंची है। इसलिए स्टेंडर्ड नियमों के हिसाब से इसका उपयोग अब मुश्किल है। हालांकि अभी इस पर फैसला लिया जाना बाकी है। लोक निर्माण विभाग की सात सदस्यीय विशेष टीम बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल हेल्थ ऑडिट कर रही है। इसमें बिल्डिंग के उपयोग को लेकर हर पहलु देखा जा रहा है। इसके तहत कितने टेम्प्रेचर तक आग पहुंची और अब बिल्डिंग उपयोग लायक है या नहीं इसे देखा जाना है। यह कमेटी 10 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगी।

स्ट्रक्चर का होगा हेल्थ ऑडिट

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने उच्च स्तर की बैठक में तय कर दिया कि आग से क्षतिग्रस्त हुए सतपुड़ा भवन के पश्चिमी विंग के स्ट्रक्चर का अलग से हेल्थ ऑडिट होगा। नेशनल बिल्डिंग संहिता (एनबीसी) कहती है कि यदि किसी भवन में आग की वजह से तापमान 800 डिग्री तक चला जाए तो नुकसान भविष्य में भी हो सकता है। गौरतलब है कि हाईपॉवर कमेटी के प्रमुख गृह विभाग के एसीएस डॉ. राजेश राजौरा की रिपोर्ट में पश्चिमी विंग में आग से 2542 वर्गमीटर हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हुआ है, जबकि 1671 वर्ग मीटर क्षेत्र आंशिक रूप से बर्बाद हुआ है। जबकि, आग 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी, जिससे छत के लोहे तक कई जगह पिघले हैं। सामान्यत: ये माना जाता है कि दीवार के अंदर की वायरिंग, पाइल लाइन और लोहे की पतली छड़े पिघली हो सकती हैं। इसलिए इसे लेकर स्टेंडर्ड मापदंडों को देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान छठवीं और चौथी मंजिल पर हुआ है। छठवीं मंजिल पर 878.36 और चौथी मंजिल पर 827 वर्गमीटर हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हुआ है। बाकी तीसरी, पांचवीं व छठवीं मंजिल पर भी आग से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर, प्रथम व द्वितीय मंजिल पर आग नहीं थी। इसलिए इस हिस्से को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऊपर की मंजिलों को उपयोग में लाना मुश्किल है। ऐसे में इन्हें वापस बनाने की भी जरूरत लग सकती है या फिर भारी पैमाने पर पुनर्निर्माण करना होगा। सरकार ने तय किया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एसडीआरएफ की टीम बनेगी। यह सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग के रखरखाव को ही देखेंगे। लोक निर्माण विभाग की सात सदस्यीय विशेष टीम बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल हेल्थ ऑडिट कर रही है। इसमें बिल्डिंग के उपयोग को लेकर हर पहलु देखा जा रहा है। इसके तहत कितने टेम्प्रेचर तक आग पहुंची और अब बिल्डिंग उपयोग लायक है या नहीं इसे देखा जाना है। यह कमेटी 10 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगी।

1700 डिग्री सेल्सियस थी सतपुड़ा की आग

जानकारों के अनुसार सतपुड़ा भवन में जो आग लगी थी उसकी तपिश 1700 डिग्री सेल्सियस थी। इसमें कुछ भी पिघल जाता है। जानकारी के अनुसार लोहा 1510 डिग्री सेल्सियस, स्टील 1370 डिग्री सेल्सियस, कांच 700 से 1500 डिग्री सेल्सियस, प्लास्टिक 130 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। वहीं सीमेंट की पकड़ 500 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा पर कमजोर हो जाती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सतपुड़ा भवन में कितना नुकसान हुआ होगा। आईएएस डॉ. राजेश राजौरा की जांच कमेटी ने पाया था कि तापमान 1200 से 1500 डिग्री तक चला गया था। इससे 2542.44 वर्गमीटर पूर्णत क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं 1671.00 वर्गमीटर क्षेत्र आंशिक क्षतिग्रस्त, तीसरी मंजिल पर 634.52 वर्गमीटर क्षेत्र पूर्णतः क्षतिग्रस्त, चौथी मंजिल पर 827.06 वर्गमीटर पूर्णतः क्षतिग्रस्त, पांचवीं मंजिल पर 202.50 वर्गमीटर पूर्णत क्षतिग्रस्त, छठवीं मंजिल पर 878.36 वर्गमीटर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुआ है।

आग का चुनावी संयोग तो नहीं

यह दूसरी बार है जब सतपुड़ा भवन में आग लगी है। इससे पहले भी साल 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद और साल 2012 में चुनाव के पहले इसी भवन की तीसरी मंजिल धधक उठी थी। अब फिर चुनाव से 4 माह पहले लगी आग को विपक्षी दल कांग्रेस ने साजिश करार दिया है, जबकि सूबे के सत्तारूढ़ दल भाजपा ने कहा है कि इस कार्यालय में कोई संवेदनशील दस्तावेज नहीं थे। सतपुड़ा भवन की 6 मंजिलों में जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य, वन, मुख्यमंत्री मॉनीटरिंग प्रकरण, जन शिकायत, नेशनल इनफॉर्मेशन सिस्टम जैसे विभाग संचालित होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग से भवन की 4 मंजिलों में कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड, शिकायती दस्तावेज, बजट लेखा-जोखा से दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की शिकायत शाखा में दर्ज शिकायतों की फाइलें और कोरोनाकाल में अस्पतालों को किए गए भुगतान संबंधी दस्तावेज भी जल गए हैं। राज्य सरकार की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि सतपुड़ा भवन में आग के फैलाव से संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना, नर्सिंग, शिकायत, लेखा और आयोग शाखा एवं विधानसभा प्रश्न से संबंधित दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा है।

टीम मोदी में बढ़ेगा मप्र का दबदबा

नई दिल्ली में दो दिनों के मंथन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन जुलाई को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। इसी के साथ ही एक बार फिर से मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलें तेज हो गईं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीम मोदी में मप्र का दबदबा बढ़ सकता है। गौरतलब है कि इसी साल के अंत में मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं और इन सभी राज्यों के किसी न किसी सांसद को मंत्रिमंडल में रखा गया है। मप्र से पांच, राजस्थान से चार, तेलंगाना से एक और छत्तीसगढ़ से एक मंत्री मोदी सरकार में हैं।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में चुनावी राज्यों से और चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई पार्टी पदाधिकारियों के बीच चर्चा हो चुकी है। इस बैठक में जेपी नड्डा की भागीदारी के साथ ही अटकलें तेज हो गईं कि राज्य स्तर सहित सरकार और भाजपा संगठन में कई बदलाव हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से अमित शाह, जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर कई दौर की चर्चा की है।

गौरतलब है कि भाजपा के मिशन 2024 में मप्र की बड़ी भूमिका होगी। इसलिए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा मप्र में बड़ी जीत चाहती है। इसके लिए भाजपा हर वर्ग को साधने में जुटी है। इसी बीच, केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच मप्र से कुछ नेताओं को जगह मिलने और कुछ को वापस भेजकर संगठन की जिम्मेदारी देने की चर्चा तेज हो गई है। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को बनाए रखने की कोशिश होगी। प्रदेश से अभी केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक ये पांच मंत्री हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एल. मुरुगन भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन वे यहां के रहने वाले नहीं हैं। इनको मिलने पर मप्र से केंद्र में मंत्रियों की संख्या सात है। प्रदेश के ग्वालियर-चंबल से दो मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वहीं, बुंदेलखड से प्रहलाद पटेल और वीरेंद्र खटीक मंत्री हैं। इसके अलावा महाकौशल से फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री हैं। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के साथ प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधकर प्रदेश से दो नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं, एक मंत्री को संगठन के काम में लगाने के लिए हटाया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि चुनावी रणनीति के तहत केंद्रीय संगठन के साथ ही राज्यों के संगठन में भी बदलाव किया जाएगा।

आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मिशन मोड में जुटी भाजपा केंद्रीय संगठन, सरकार और राज्यों में व्यापक बदलाव करेगी। चौतरफा बदलाव के लिए भाजपा में शीर्ष स्तर पर कई बैठकें हुई हैं। इस महीने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष और गृहमंत्री की सात दौर की बैठक के बाद इन तीनों नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मंथन किया था। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में चौतरफा बदलावों की रूपरेखा तय कर ली गई है। जुलाई के पहले हफ्ते से बदलाव का दौर शुरू होगा। लंबे समय तक महासचिव और उपाध्यक्ष पद पर जमे नेताओं की छुट्टी की जाएगी। इसके बाद नए सिरे से राज्यों के प्रभारी भी तय किए जाएंगे। पार्टी की योजना पहले की तरह मंत्रियों से भी संगठन का काम लेने की है। चुनावी तैयारी के लिए पार्टी ने राज्यों को तीन क्षेत्रों में विभाजित कर हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार करने की योजना बनाई है। बताया जाता है कि मप्र, कर्नाटक, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव किया जाएगा। उप्र का सियासी समीकरण साधने के लिए राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ओम प्रकाश राजभर को फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। मप्र और कर्नाटक के संगठन में भी कुछ बदलाव किए जाने की संभावना बनने लगी है।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

समीकरणों को साधने पर फोकस

भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय, जातीय समीकरणों के साथ ही वर्तमान स्थिति का आंकलन कर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि भाजपा महाकौशल में कमजोर है। वहीं, विंध्य की अनदेखी करने से जनता नाराज है। इसके लिए प्रदेश के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व विंध्य और महाकौशल में जोर लगा रहा है। ऐसे में चर्चा है कि प्रदेश में बुंदेलखंड से मंत्री ओबीसी सांसद प्रहलाद पटेल, अनुसूचित जाति सांसद वीरेंद्र खटीक में से किसी एक को हटाया जा सकता है। यदि प्रहलाद पटेल को हटाया जाता है तो उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनकी जगह पर विंध्य से सांसद गणेश सिंह या देवास से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को संगठन में लिया जा सकता है। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि महाकौशल से राकेश सिंह को भी केंद्र में जगह मिल सकती है। हालांकि, यहां से अभी फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हैं। इसके अलावा मप्र से राज्यसभा सांसद धर्मेंद्र प्रधान को भी वापस भेजने की चर्चा है। जानकारी के अनुसार, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व महाकौशल में बिगड़े समीकरण को साधने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि हाल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए। इसके बाद उनका बालाघाट दौरा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। यहां पर पार्टी आदिवासी वोट बैंक को साधने पर जोर लगा रही है। यहां पर पार्टी नगर निगम का चुनाव हार गई है। वहीं, क्षेत्र को प्रदेश सरकार में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से जनता नाराज है। विंध्य में पार्टी को भले ही पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली हों, लेकिन अब भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने महापौर का चुनाव जीत लिया। भाजपा के सर्वे में भी यहां पर रिपोर्ट अच्छी नहीं मिली थी। यही वजह है कि पार्टी का फोकस अब क्षेत्र के मतदाताओं को साधने पर है।

वोट के बदले मुफ्त के वादे की शुरुआत करने का श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। उसने पहले दिल्ली और बाद में पंजाब के विधानसभा चुनावों में ऐसा किया और जीत दर्ज की। लेकिन पंजाब में उसकी सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। इस साल के आखिर में देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सियासी दल राज्यों के वोटरों को लुभाने के लिए लोकलुभावने वादे करेंगे। नेता चुनावी मंचों से और राजनीतिक दल अपने मेनिफेस्टो में मुफ्त बिजली और राशन जैसी स्कीमों की पेशकश वोटरों को आकर्षित करने के लिए करेंगे। हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले समझ लेते हैं कि मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की वित्तीय स्थिति कैसी है।

मुफ्तखोरी का जाल

मप्र सहित 4 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी हैं। मुफ्त बिजली और सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के वादे ने कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता तक पहुंचा दिया, लेकिन मुफ्तखोरी के साइड इफेक्ट से कर्नाटक अभी से दो-चार होने लगा है। कुछ दिन पहले तक बिजली बिल वसूलने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को बिल की राशि अदा करने और सरकारी बसों में महिलाओं द्वारा टिकट लेने से इनकार की घटनाएं कर्नाटक में रोजाना की बात हो गई थीं।

मुफ्त मिलने की आस में वोटों से कांग्रेस को मालामाल करने वाली जनता को चूंकि वैधानिक तौर पर अभी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, ऐसे में रोष बढ़ना स्वाभाविक है। शुक्र है कि अभी बेरोजगारों ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई है, जिन्हें तीन और डेढ़ हजार मासिक देने का वादा किया गया है। अव्वल तो कर्नाटक से सीख लेने की जरूरत थी, लेकिन राजनीतिक दल किसी घटना से भला कहां सीख लेते हैं? वे घटनाओं की अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी...कहावत चरितार्थ करने में राजनीतिक दल माहिर होते हैं।

इस साल के अंत में राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन राज्यों में भी कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर मुफ्त देने के वादों से मतदाताओं की झोली भर दी है। राजस्थान में 5 साल तक मुफ्त बिजली देने की चाहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं हुई। गर्मी में राज्य की बिजली आपूर्ति लचर हो गई है, लेकिन इसे सुधारने के बजाय उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने लगे हैं। मप्र में भी एक बार फिर सत्ता संभालने का सपना पाले कमलनाथ पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, नारी सम्मान योजना के तहत हर महिला को डेढ़ हजार रुपए मासिक और हर घर को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर चुके हैं। वोट के बदले मुफ्त के वादे की शुरुआत करने का श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। उसने पहले दिल्ली और बाद में पंजाब के विधानसभा चुनावों में ऐसा किया और जीत दर्ज की। दिल्ली नगर राज्य है। यहां की स्थिति को देखते हुए तो इस योजना को लागू करने में आम आदमी पार्टी को खास दिक्कत नहीं आई, लेकिन पंजाब में उसकी सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। अब उसने पेट्रोल-डीजल को महंगा कर दिया है। पंजाब राज्य परिवहन निगम को महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने के बदले सरकार से बतौर मदद रकम मिलनी बंद हो गई है। निगम का सरकार पर करीब 170 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। इसकी वजह से परिवहन निगम हांफने लगा है। वहीं पुरानी पेंशन योजना लागू करने

तेलंगाना सबसे अमीर

प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी की तुलना में राज्य के वेल्थ का बेहतर संकेत देती है। वित्त वर्ष 2023 में आय के मामले में तेलंगाना 3.17 लाख रुपए के साथ इस सूची में सबसे अमीर राज्य है। इसके बाद राजस्थान 1.56 लाख रुपए, मप्र 1.41 लाख रुपए और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1.34 लाख रुपए रही है। इन चारों राज्यों में रेवेन्यू के मोर्चे पर 1,95,179 करोड़ रुपए के साथ मप्र टॉप पर है। इसके बाद तेलंगाना 1,93,029 करोड़ रुपए, राजस्थान 1,83,920 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ ने 89,073 करोड़ रुपए का राजस्व वित्त वर्ष 2023 में प्राप्त किए। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में छत्तीसगढ़ पर सबसे कम कर्ज है। छत्तीसगढ़ पर जीएसडीपी के अनुपात में 17.9 फीसदी कर्ज है। इसके बाद तेलंगाना (24.7 प्रतिशत), मप्र (26.3 प्रतिशत) और राजस्थान पर जीएसडीपी के अनुपात में 38 फीसदी कर्ज है। जीएसडीपी के अनुपात में अधिक कर्ज राज्य के वित्तीय हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि कर्ज के ब्याज के भुगतान के बाद राज्य के पास विकास कार्यों के लिए कम संसाधन बचते हैं।

की घोषणा राजस्थान भी कर चुका है, जबकि हिमाचल इसी वादे पर कांग्रेस के साथ आया, लेकिन आर्थिक कमियों की वजह से दोनों ही राज्यों में यह योजना अब तक लागू नहीं हो सकी है।

ऐसा नहीं कि भाजपा इस दौड़ में पीछे है। चूंकि उसे भी वोट चाहिए, इसलिए वह भी हरसंभव तरह से मुफ्तखोरी के वादे कर रही है। बीते दिनों मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की। इसके तहत राज्य में 23 से 60 साल तक की उन महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए मिलेंगे, जिनके परिवार की जोतभूमि पांच एकड़ से कम और सालाना आमदनी ढाई लाख रुपए से कम है। पिछले आम चुनाव के पहले केंद्र की ओर से लागू किसान सम्मान निधि योजना को भी विपक्षी दलों ने मुफ्तवाद का ही विस्तार माना था। 80 करोड़ लोगों को दिए जा रहे मुफ्त राशन को भी इसी श्रेणी में रखा जा रहा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 विशेष रूप से राज्य को लोककल्याणकारी भूमिका निभाने की व्यवस्था देते हैं। इन अनुच्छेदों के दायरे में देखें तो मुफ्त में सहूलियतें देने की राज्यवार योजनाएं या राजनीतिक वादे भी लोककल्याणकारी राज्य के ही दायरे में आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुफ्त में दी जा रही इन सुविधाओं को लंबे वक्त तक लागू रखा जा सकता है? क्या इससे राज्यों पर आर्थिक दबाव नहीं बढ़ेगा? भारत का शायद ही कोई राज्य है, जो कर्ज के पहाड़ के नीचे न खड़ा हो, लेकिन सत्ता हासिल करने की दौड़ में राजनीतिक दल इस पहाड़ के दबाव को कम से कम वोटरों की अदालत में झुठला रहे हैं। मुफ्त के वादों के चक्कर में वोटर आ रहा है, यह जानते हुए भी कि अंततः ऐसे वादे उसके राज्य की आर्थिक सेहत को खराब ही करेंगे, जिसका असर उसकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। चूंकि यह असर परोक्ष होता है, जबकि मुफ्तखोरी से प्रत्यक्ष फायदा होता है, इसलिए मुफ्त के वादे के खुशनुमा जाल में लोग फंस जाते हैं।

तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे में बलिदान था, खुद को होम कर देने का भाव था। जबकि मुफ्त के वादे में हासिल करने का भाव है। इसमें दोनों हासिल करते हैं, राजनीतिक दल भी और वोटर भी, लेकिन समग्रता में अंततः दोनों का ही नुकसान होता है। इस तथ्य को सभी दल जानते हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। चूंकि आज राजनीति का मकसद सत्ता प्राप्त करना ही हो गया है, इसलिए हर राजनीतिक दल इसी चाहत में राज्य के साथ ही भविष्य की बलि देता जा रहा है। चूंकि कांग्रेस लगातार ऐसे वादे कर रही है। ऐसे में उसके मुकाबले वाले दूसरे दल क्यों पीछे रहेंगे?

राजकोषीय घाटा बढ़ा रहा चिंता

राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब किसी सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक होता है। फिर इस अंतर को पाटने के लिए राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम राजकोषीय घाटा 14,600 करोड़ रुपए है, जो कि इसके जीएसडीपी का 3.33 फीसदी है। इसके बाद तेलंगाना का राजकोषीय घाटा 52,167 करोड़ रुपए (इसके जीएसडीपी का 3.93 प्रतिशत) है। मप्र का राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ रुपए (इसके जीएसडीपी का 4 प्रतिशत) है और सबसे अधिक राजस्थान का राजकोषीय घाटा 58,212 करोड़ रुपए (इसके जीएसडीपी का 4.12 प्रतिशत) है। प्रतिबद्ध खर्च के दायरे में सैलरी और वेजेस, पेंशन और ब्याज भुगतान आते हैं। यानी सरकार को ये खर्च किसी भी हाल में करने जरूरी हैं। अगर इसमें बढ़ोतरी होती है, तो विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्पेस कम हो जाता है। मप्र इस सूची में सबसे आगे है क्योंकि प्राप्त रेवेन्यू के मुकाबले इसका प्रतिबद्ध खर्च सबसे कम (42.1 प्रतिशत) है, जबकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान ने क्रमशः 46.3 प्रतिशत, 48.6 प्रतिशत और 69.2 प्रतिशत खर्च किया है।

देश की आर्थिक सेहत के लिए इस मुफ्त के वादे की सीमा को निर्धारित करना ही होगा। अन्यथा दीर्घकाल में इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इस मामले में अब निगाहें चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इसे लेकर संवैधानिक संस्थाओं को कदम उठाने होंगे। सत्ता के खेल में जुटे राजनीतिक दल तो इस पर गंभीरता से विचार करने से रहे।

मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चार चुनावी राज्य हैं जो इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होंगे। इन चार राज्यों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए बीटी रिसर्च ब्यूरो ने इकोनॉमी की साइज, प्रति व्यक्ति आय, राज्य ऋण, टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल एक्पेंडिचर और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों जैसे प्रमुख मापदंडों की एक सूची तैयार की है।

भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन राज्यों के बजट और आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मौजूदा कीमतों पर वित्त वर्ष 2023 में 14.13 लाख करोड़ रुपए की ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ राजस्थान इन चार राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद तेलंगाना का 13.27 लाख करोड़ रुपए, मप्र का जीएसडीपी 13.23 लाख करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 4.38 लाख करोड़ रुपए है।

स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, पुलों, सड़कों, हवाई अड्डों आदि के निर्माण में खर्च होने वाली राशि को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2023 में 45,685 करोड़ रुपए के कैपेक्स के साथ मप्र चारों राज्यों में टॉप पर है। ये मप्र के कुल खर्च का 18.4 फीसदी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ 15,241 करोड़ रुपए (कुल खर्च का 14.7 प्रतिशत), तेलंगाना का कैपेक्स 29,728 करोड़ रुपए (कुल खर्च का 11.6 फीसदी) और राजस्थान का कैपेक्स 24,152 करोड़ रुपए है, जो उसके कुल खर्च का 10.3 फीसदी है। हाई कैपेक्स इस बात का संकेत देता है कि राज्य अधिक विकास कार्य करने में सक्षम है।

● **विपिन कंधारी**

अगस्त 2022 में जबसे नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा है तभी से भाजपा विरोधी दलों को एकसाथ लाने की मुहिम में जुटे थे। आखिरकार 23 जून को पटना में वो अपने अधिकारिक आवास 1, अणे मार्ग पर विपक्षी एकता के नाम पर प्रमुख दलों को एक छत के नीचे लाने में सफल रहे। 15 विपक्षी दलों के 27 नेता विपक्षी एकता के इस मेले में जुटे थे। नीतीश के आवास पर ढाई घंटे चली बैठक में सभी दलों ने अपने-अपने विचार रखे।

विपक्ष को मिला मोदी को हराने का फॉर्मूला!

विपक्षी दलों का जुटान हो गया, पटना में 15 दलों की बैठक हुई। इनमें कांग्रेस, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एनसीपी, नेशनल कांफ्रेंस पहले से सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले यूपीए का हिस्सा थीं। आरजेडी और शिवसेना भी लगभग यूपीए में ही थीं। विपक्षी जुटान में शामिल हुई नई पार्टियां है जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, समाजवादी पार्टी, पीडीपी और आम आदमी पार्टी। इसमें आरएसपी और मुस्लिम लीग को भी जोड़ लीजिए, ये दोनों पार्टियां भी पहले से यूपीए में हैं। कुल मिलाकर 17 दल बनते हैं। इन 17 दलों की लोकसभा में 154 सीटें हैं और 2019 में इन्हें कुल मिलाकर 38 प्रतिशत वोट मिला था।

वहीं, भाजपा को अकेले 437 पर 37.36 प्रतिशत वोट और 303 सीटें मिलीं थी, भाजपा ने 105 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी थीं, जिन्हें 7.7 प्रतिशत वोट और 50 सीटें मिलीं थी। यानि कुल 45 प्रतिशत वोट और 353 सीटें। इनमें जनता दल (यू) को 1.46 प्रतिशत वोट और 16 सीटें मिली थीं और शिवसेना को 2.10 प्रतिशत वोट और 18 सीटें मिली थीं। यानि 2019 के चुनाव नतीजों के वाद जेडीयू और शिवसेना 34 लोकसभा सीटों और 3.56 प्रतिशत वोटों के साथ एनडीए से बाहर हो गए। लेकिन यह जमीनी सच्चाई नहीं है, शिवसेना और जेडीयू दोनों ही टूट चुके हैं, शिवसेना का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, सभी शिंदे गुट में जा चुके हैं, जो एनडीए का हिस्सा है।

जनता दल (यू) के आधे से ज्यादा सांसद चुनाव आते-आते पार्टी छोड़कर अलग होने की तैयारी में हैं। इस समय बिहार में जो जेडीयू-आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन बना है, वह गठबंधन 2014 के चुनाव में भी था, तब आरजेडी को 4, जेडीयू को 2, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को एक सीट मिली थी। जबकि एनडीए को 31 सीटें मिली थी, जिनमें से भाजपा को 22, उसकी सहयोगी लोजपा को 6 और अन्य सहयोगी रालोसपा भी तीन सीटें जीत गई थी। 2019 में जेडीयू की ताकत भाजपा के साथ गठबंधन के कारण ही बढ़ी थी।

जो दल पटना में एक साथ बैठे थे, उनमें से आम आदमी पार्टी शिमला में होने वाली दूसरी बैठक में शामिल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि कांग्रेस इस बैठक से पहले अध्यादेश पर अपना रूख साफ करे। अन्य विपक्षी दलों के दबाव के बावजूद कांग्रेस ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को समर्थन नहीं देने का पार्टी के भीतर से भारी दबाव है। राहुल गांधी ने पटना बैठक के दौरान चाय के समय भी केजरीवाल से बात करने से इनकार करके उन्हें अपमानित किया।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को उनके और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के वे बयान दिखाए, जो राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ दिए गए थे। केजरीवाल ने उस समय कहा था कि बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन अगले ही दिन 24 जून को आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने राहुल गांधी के खिलाफ अब तक का सबसे हमलावर ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर विपक्षी दल देश को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वे तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दाव नहीं लगाएंगे, कांग्रेस विपक्ष पर इस तरह का दबाव भी नहीं डाले। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर करना देशहित में और संविधान बचाने से भी ऊपर है।

आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता सौरभ

विपक्षी एकता की आहट के बीच कुनबा बढ़ाने की कोशिशें

विपक्षी एकता की सक्रिय कोशिशों के बीच भाजपा ने भी एनडीए का कुनबा दोबारा जोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। 3 जून को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के अपने आवास पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, अकाली दल के नेता नरेश गुजराल और लोकजनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के साथ एक बैठक की। उस बैठक में उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा एनडीए में शामिल छोटे दलों का सम्मान किया है। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी हमने हमारे सहयोगी दलों को सरकार में शामिल किया। वह इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहते हैं। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर अपने पूर्व सहयोगियों से यह इसलिए कहा, क्योंकि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा था कि हमें एनडीए में शामिल सहयोगी दलों को भरोसा दिलाना है कि भाजपा अपने साथियों को पूरा मौका और सम्मान देती है। सहयोगी दल हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं, सेतु हैं।

सोनिया के 2004 के फॉर्मूले पर लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव

पटना की धरती से विपक्षी एकता का बिगुल फूंक दिया गया। महाबैठक में 2024 को सियासी लड़ाई का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है लेकिन अब विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होगी। बैठक के बाद 15 विपक्षी दलों ने साफ संदेश दिया कि 2024 चुनाव की लड़ाई संपूर्ण विपक्ष बनाम भाजपा के बीच होगी। मनभेद और मतभेद को भुलाकर सभी विपक्षी दलों ने एक मंच से एक सुर में कहा कि अनेकता में एकता का फॉर्मूला सभी को मंजूर है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये विपक्षी एकता की ऐतिहासिक बैठक हुई है। बिहार ज्ञान की धरती है। यहां बड़े-बड़े आंदोलन भी हुए हैं। चंपारण से लेकर जेपी आंदोलन तक यहीं से हुए हैं। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल की कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग जनता के हित के लिए एकजुट हुए हैं। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2004 के फॉर्मूले को फिर से लागू करेगी। कांग्रेस ने इस साल फरवरी में रायपुर में हुए 85वें अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता वाला 2004 का यूपीए फॉर्मूला सामने रखा था। कांग्रेस ने 2004 में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए चुनाव से पहले 5 राज्यों में समान विचारधारा वाले 6 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर किया था।

भारद्वाज ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो वह सबसे ज्यादा घमंडी होंगे। केजरीवाल पटना में हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी उन्हें एक मिनट का समय देने से भी इनकार कर देंगे। राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि केजरीवाल की तोड़-मोड़कर बोलने की छवि बन चुकी है, इसलिए उन्हें डर था कि मुलाकात के बाद वह बाहर जाकर न जाने क्या-क्या कह दें। इस नए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस भी राहुल गांधी के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए अरविंद केजरीवाल को गठबंधन से बाहर ही समझिए। इतना ही नहीं, जहां-जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे, वहां-वहां देशभर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े होंगे।

2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 31 प्रतिशत वोटों के साथ 282 सीटें मिलीं थी। 2019 में वोट शेयर 37.36 प्रतिशत हो गया और सीटें बढ़कर 303 हो गई थीं। वोट प्रतिशत तो 6.36 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सीटें सिर्फ 21 बढ़ीं। भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ने का मुख्य कारण यह था कि जहां 2014 में भाजपा ने 116 सीटें 2 लाख वोटों से ज्यादा अंतर से जीती थी, वहीं 2019 में यह संख्या बढ़कर 164 हो गई। इसी तरह 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोटों से जीतने वाली सीटों में भी बढ़ोतरी हुई थी। इससे वोट प्रतिशत तो बढ़ गया, लेकिन उस मुकाबले में सीटें उतनी नहीं बढीं।

देश में मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी कोई हवा भी नहीं चल रही कि इन 164 सीटों पर बड़ा उलटफेर हो जाएगा। विपक्षी गठबंधन से मीडिया में नेरेटिव जरूर बनता है, जमीन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाजपा ने उप्र में समाजवादी पार्टी और बसपा का महागठबंधन होने के बावजूद 80 में से 64 लोकसभा सीटें जीतीं थीं। जबकि बसपा से गठबंधन के बावजूद सपा सिर्फ पांच सीटें जीत पाईं, इनमें से दो सीटें उपचुनाव में हार गई, क्योंकि बसपा से गठबंधन टूट गया था।

समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी चुनाव लड़कर देख लिया है। इसलिए उप्र में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करके तभी फायदा हो सकता है, अगर उप्र का सारा मुस्लिम वोट मायावती का साथ छोड़कर उनके साथ आ जाए। ऐसी संभावना बन भी रही है। इसी संभावना को देखते हुए ही अखिलेश यादव ने गठबंधन का रूख किया है, लेकिन ऐसी सूरत में भी पिछली बार मुस्लिम-दलित गठबंधन के चलते 10 सीटें जीतने वाली मायावती को नुकसान होगा, भाजपा को नहीं।

गठबंधन का नाम देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन (पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक एलायंस) रखा जा रहा है। इस नाम का खुलासा बहुत छोटे से दल सीपीआई (एमएल) ने किया है, आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। इन तीनों शब्दों पर गौर करिए। पहला शब्द खुद का बचाव करने वाला है, क्योंकि विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गांधी की देशभक्ति पर भाजपा के नेता सवाल उठाते रहते हैं। दूसरा शब्द लोकतांत्रिक इसलिए है, क्योंकि विपक्ष का सारा नेरेटिव ही यह है कि मोदी के रहते लोकतंत्र खतरे में है और वे ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं। लेकिन जब तक उस नेरेटिव से जनता न जुड़े, तब तक नेरेटिव बना देने से न तो कोई चुनाव हार सकता है, न जीत सकता है। जमीनी हकीकत को देखें, तो 2019 में 9 राज्यों मप्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उप्र की 199 लोकसभा सीटों में से 180 सीटें एनडीए जीती थी, जिनमें से 177 उम्मीदवार भाजपा के जीते थे और तीन सहयोगी।

● इन्द्र कुमार

भूपेश की बिसात...

अमित शाह ने तैयार की चुनावी गणित

भाजपा में चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पांच मंत्रियों के संभाग दुर्ग में पहुंचकर अपना बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। अपने प्रवास के दौरान शाह ने भिलाई में पद्मश्री उषा बारले के घर पहुंचकर सतनामी समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो पार्टी से जुड़ें और पार्टी उनको सम्मान देगी। प्रदेश में सतनाम समाज की बड़ी आबादी है, जो एक तरह से कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। यही वजह है कि शाह का यह दौरा कांग्रेस के लिए चुनावी गणित बदलने वाला साबित हो सकता है। दुर्ग संभाग में 2018 के चुनाव में भाजपा के सारे गणित फेल हो गए थे। इसकी कुल 20 विधानसभा सीट में से 17 सीट कांग्रेस के खाते में आईं थी। भाजपा ने वैशालीनगर और राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की थी। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की सीट जोगी कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि यहां के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करने में सफल रही थी। यही वजह है कि इस बार शाह ने अपनी सभा के लिए दुर्ग को चुना था। दुर्ग संभाग भाजपा की सियासत का बड़ा केंद्र बिंदु है। कारण, यहां शुरू से गुटबाजी हावी रही है, खासकर भाजपा के संगठन जिले भिलाई व दुर्ग में। यहां संगठन विस्तार का काम भी चुनौतीपूर्ण रहता है। यही वजह है कि संगठन ने भी यहां शाह को आगे कर गुटबाजी दूर होने का संदेश देने का प्रयास किया है।

छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। सत्ताधारी पार्टी होने के चलते कांग्रेस का कैंपेन भी तेजी से चल रहा है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बना रही है? क्या सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी चल रही है या आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने प्रत्याशी ढूंढना शुरू कर दिया है। दरअसल एक महीने के भीतर कांग्रेस ने संभागीय मीटिंग से बूथ तक पहुंचने का टारगेट रखा है। महीने के शुरुआत में पांचों संभाग में कांग्रेस ने मीटिंग की। इसके बाद विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये भी अपने अंतिम चरण पर है। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की भी शुरुआत कर दी है। इस अभियान की शुरुआत 26 जून से हो गई है।

कहते हैं किसी नेता के सियासी कैरियर में टिकट कट जाने से ज्यादा बड़ा ग्रहण तब लगता है जब चुनाव हार चुके उम्मीदवार पर पार्टी एक बार फिर दांव खेले और पार्टी को निराशा ही हाथ लगे। कहानी यहीं नहीं रुकती। पार्टी दो बार हार चुके उम्मीदवार को फिर मौका देने का सोचती है और इस बार भी पार्टी को निराशा ही हाथ लगती है। मतलब 2008 में विधानसभा चुनाव और दो लोकसभा चुनाव हार उसके खाते में जुड़ जाते हैं। फिर भी, पार्टी हारे हुए नेता के नेतृत्व में ही 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने का सोचती है। इस बार नेता पार्टी के अरमानों पर खरा उतरता है और पार्टी उसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप देती है। इसे किस्मत कहें या कुछ और? ऐसी ही किस्मत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी है, जो हार पर हार के बावजूद अपनी बाजी पलटने में सफल रहे। कई राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि अगर भूपेश ने हार के सामने घुटने टेक दिए होते तो आज वे मुख्यमंत्री नहीं होते। आज भूपेश देश में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है जो एकाधिक बार हारने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं और पांच महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने जा रहे हैं।

जानकारों का मानना है कि उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह पारिवारिक पृष्ठभूमि है। राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में 2018 में शपथ लेते ही उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करके अपनी पारी की शुरुआत की। उनकी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जैसी नवाचारी पहल से लोगों को आसानी से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया है। बेरोजगारों को प्रतिमाह भत्ता मिलना प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की भी चिंता करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि कर उनका मान बढ़ाया है।

श्रमिकों का मान बढ़ाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तथा स्थायी विकलांगता की स्थिति में उन्हें देय राशि 50 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने की घोषणा की। साथ ही अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना करिश्मा दिखा चुके और कर्नाटक के चुनाव में पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत से गदगद भूपेश बघेल बजरंग बली के भक्त हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर बघेल कहते है, 'बजरंग बली हमेशा धर्म के साथ हैं, हमेशा अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में यही हुआ है और आगे भी यही होने वाला है। भाजपा के साथ बजरंग बली नहीं हैं।' जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ का चुनावी माहौल दक्षिण या पश्चिम के राज्यों से बिलकुल ही अलग है। यहां के लोग तो उस राजनीतिक दल और उम्मीदवार पर अपना स्नेह बिखेरने को तैयार रहते हैं जो सुख-दुख में उनका साथ देता है। आज भूपेश सत्ता में है और भाजपा बघेल सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। भाजपा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। भाजपा ने वादा किया है कि यदि वह विधानसभा चुनाव में विजयी होती है और सरकार बना लेती है, तो उपद्रवी तत्वों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर कार्रवाई को अमल में लाएगी। मतदाताओं ने भी भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों को देख लिया है, इसलिए इस बार वे बहुत सोच-समझकर अपना मत देंगे। फिलहाल, भूपेश बघेल के सियासी कद का कोई नेता राज्य में नहीं है। उस पर से उन्हें अपनी शुरू की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कका बघेल फिलहाल लोगों का आशीर्वाद लेने उनके बीच पहुंच चुके हैं, इंतजार चुनाव की तारीख का है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

बेटी को कमान, भतीजा आलाकमान

जून 2022 में एकनाथ शिंदे अपनी ही पार्टी शिवसेना के 39 विधायकों के साथ विद्रोह कर उद्धव सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय शरद पवार के भतीजे और राज्य के उपमुख्यमंत्री रहे अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच कहा था कि अगर उनके भाजपा के साथ जाने को शरद पवार साहब ने समर्थन दिया होता तो आज हमें सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता और पूरे पांच साल हम सत्ता में रहते। शरद पवार सरकार गिरने का अफसोस मना रहे थे तो उनके भतीजे अजीत पवार भाजपा के साथ न रह पाने का अफसोस मना रहे थे।

एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हर सप्ताह इस बात पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी कोई शिंदे उभरने वाला है? इशारा अजीत पवार की ओर था और शरद पवार भी **भतीजे के बयानों** और मीडिया की लगातार अटकलों से परेशान थे और इसका कोई स्थायी समाधान चाह रहे थे। एनसीपी और एमवीए नेतृत्व की तरफ से एक के बाद एक बयानों ने इन अफवाहों को हवा दी कि पवार के भतीजे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी का एक खेमा बगावत कर सकता है और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार से हाथ मिला सकता है। लेकिन शरद पवार ऐसे सियासी सुजान है जो किसी भी मुश्किल वक्त से सकुशल बाहर निकल आने का माद्दा रखते हैं। 80 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी अपने राजनीतिक तरकश में वो ऐसे कई तीर रखते हैं जो उचित समय पर विरोधियों पर चलाने के लिए होते हैं। ऐसा ही एक तीर शरद पवार ने 2 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपने भतीजे अजीत पवार पर लगाम लगाने के लिए चला था। शरद पवार के इस कदम को अजीत पवार के साथ सियासी शतरंज में उनकी चाल के तौर पर देखा गया। अपने इस्तीफे की घोषणा शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के नए संस्करण के विमोचन के मौके पर उस वक्त की जब अजीत पवार भाजपा के साथ हाथ मिलाने की रणनीति को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे।

शरद पवार ने अपने समर्थकों को हैरानी में डालते हुए कहा था कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि वे अपना राज्यसभा का कार्यकाल पूरा करेंगे लेकिन भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगे हाथ शरद पवार ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए एक कमेटी भी बना दी। शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते थे कि शरद पवार का इस्तीफा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व बदलने का मामला नहीं है, बल्कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच गहरे हो चुके अंदरूनी सत्ता संघर्ष की उपज है। असल में शरद पवार ने इस्तीफे का दांव चलकर अजीत पवार को अलग-थलग करने का इमोशनल कार्ड खेला था। शरद पवार जानते थे कि उनके इस्तीफे के बाद पार्टी उनके पीछे गोलबंद हो जाएगी और अजीत पवार को बता दिया जाएगा कि असली बॉस कौन है। हुआ भी वही। पार्टी के तमाम नेताओं के मान मनौव्वल के बाद शरद पवार ने 5 मई को अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे को वापस लेकर बता दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की असली ताकत कौन है।

5 मई को अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेकर अजीत के पार्टी तोड़ने की संभावनाओं पर विराम ही नहीं लगाया बल्कि एक महीने बाद 10 जून को पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और अपने भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपने भतीजे को पार्टी के भीतर अपनी हैसियत से भी अवगत करा दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष का पद बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सुप्रिया अब पार्टी के भीतर शरद पवार के बाद दूसरे नंबर की हैसियत में आ गई हैं। अभी तक महाराष्ट्र से जुड़ा फैसला शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील की सलाह से करते थे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जब से राजनीति में सक्रिय हुई हैं तब से उन्हें दिल्ली की राजनीति की दीक्षा दी गई है। शरद पवार ने सुप्रिया को अपनी सीट बारामती से सांसद बनाया और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय किया। दिल्ली में जब भी शरद पवार के घर विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई, सुप्रिया सुले ने घर आने वाले नेताओं के चाय पानी की व्यवस्था देखने के साथ दिल्ली के दावंपेचों को समझने की कोशिश भी की। यह बात अलग है कि राजनीति में इतने साल गुजारने और शरद पवार की राजनीति को करीब से देखने के बाद भी सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकीं। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष और महाराष्ट्र का प्रभार देकर भी यह साफ कर दिया है कि बेटी भतीजे से बढ़कर है और वही उनकी राजनीतिक वारिस होगी।

● बिन्दु माथुर

अजीत पवार की विधायकों में पकड़

अजीत पवार को दरकिनार करने की कोशिश करने वाले शरद पवार भी अजीत पवार की विधायकों में पकड़ से वाफिक है। शरद पवार भी इस बात को जानते हैं कि वह एक सीमा से अधिक अपने भतीजे को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि ज्यादातर विधायकों की वफादारी अजीत के साथ है। इसीलिए शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार के पास विपक्ष के नेता की बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे में उनको सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल से कम आंकना ठीक नहीं है। भले ही शरद पवार ने अपनी बेटी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यह संकेत दिए हों कि आने वाले समय में उनकी बेटी ही पार्टी की सर्वेसर्वा होगी, लेकिन पार्टी को टूट से बचाना है तो उन्हें आने वाले दिनों में अपने महत्वाकांक्षी भतीजे को भी भरोसे में लेना होगा। हालांकि अजीत पवार को भले ही सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का निर्णय रास न आ रहा हो लेकिन पार्टी से बगावत करना अजीत पवार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा।

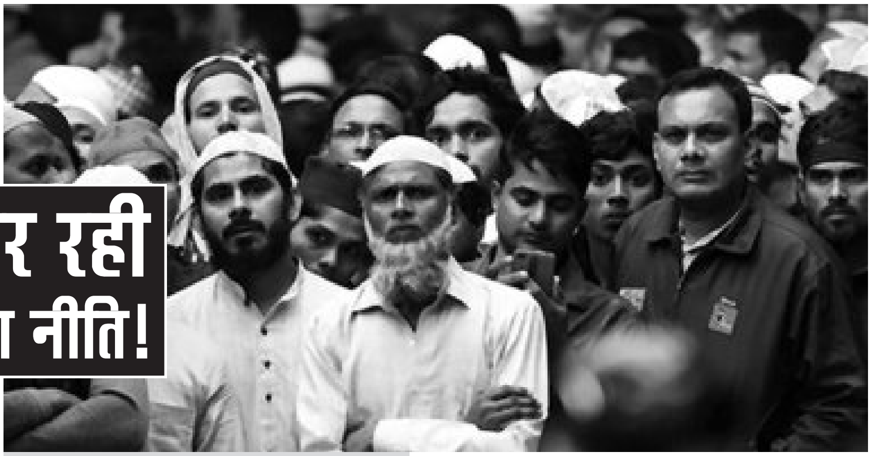

कारगर रही पसमांदा नीति!

कर्नाटक विधानसभा में भाजपा की हार पर उप्र के निकाय चुनाव में उसकी जीत ने कुछ हद तक जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। हालांकि विधानसभा और निकाय चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों चुनावों का वातावरण और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। फिर भी राजनीतिक पार्टियां इसको मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में जरूर लेती हैं। उप्र के निकाय चुनाव में सबसे अधिक जिस बात की चर्चा थी वो प्रधानमंत्री मोदी की पसमांदा नीति की थी। ज्ञात रहें कि पिछले वर्ष से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय पर बल देते हुए पसमांदा मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, जिस कारण पहली बार राष्ट्रव्यापी तौर पर मुख्यधारा में मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का प्रश्न चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक ओर देशज पसमांदा समाज और पसमांदा कार्यकर्ताओ में इसको लेकर उत्साह का माहौल है कि पहली बार राष्ट्रव्यापी स्तर पर उनके सुख-दुख की चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर अशराफ वर्ग और तथाकथित लेफ्ट लिबरल सेक्युलर खेमे में इसे संदेह की दृष्टि से देखते हुए मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को **आंतरिक मामला बता** इसे मुस्लिम समाज को बांटकर वोट की राजनीति करने का भी आरोप लगाया जा रहा है।

पसमांदा नीति को प्रयोग के रूप में राजनीतिक रूप से सबसे जटिल राज्य उप्र को प्रयोगशाला के रूप में चुना गया। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पदों पर पहली बार पसमांदा समाज के लोगों को आसीन किया गया। जहां अब तक पारंपरिक रूप से मुस्लिम समाज का संभ्रांत शासक वर्गीय अशराफ वर्ग ही काबिज होता आया था। लोक कल्याणकारी स्कीमों और हुनर हाट के जरिए पसमांदा समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया। उप्र विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हुए मुस्लिम समाज के वंचितों के उत्थान की बात की गई।

हालांकि भाजपा के पक्ष में मुसलमानों का केवल 8 प्रतिशत वोट ही मिला, जिसमें संभवत: अधिकांश भाग पसमांदा का था। लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि यह प्रतिशत पिछले विधानसभा की तुलना में लगभग दोगुना था। जिसका आंशिक रूप से ही सही चुनाव पर प्रभाव पड़ा और ऐसा अनुमान लगाया गया कि लगभग 70-80 सीटों पर जहां बहुत ही कम वोटों से हार जीत हुई वहां भाजपा के पक्ष में ये वोट निर्णायक साबित हुए। और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि इतिहास में पहली बार भाजपा ने सैय्यद को मंत्रालय देने की अपनी परंपरा को तोड़ते हुए पसमांदा बुनकर समाज से एक मंत्री बनाया।

निकाय चुनाव में पसमांदा नीति को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने लगभग 394 टिकट (निकाय सदस्य और निकाय अध्यक्ष हेतु) मुस्लिम समाज को दिए जिसमें अधिकांश पसमांदा समाज से थे। जिसमें लगभग 37 के आसपास अध्यक्ष पद के लिए और 350 के आसपास सदस्य पद के लिए थे। जिसमें पसमांदा समाज की तीन महिलाओं समेत कुल पांच अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विजयी हुए। सदस्य पद के लिए लगभग 55 प्रत्याशी विजेता घोषित हुए। भाजपा के नेतृत्व में पसमांदा महिलाओं का चुनाव जीतना भी एक नए युग की शुरुआत की ओर इशारा करता है। नगर निगम में महापौर के लिए किसी भी सीट पर भाजपा ने पसमांदा प्रत्याशी नहीं दिया था फिर भी सभी सीटें भाजपा के पक्ष में गईं, विशेष रूप से पसमांदा बहुल क्षेत्रों में। निसंदेह इसमें पसमांदा वोटरों ने एक बड़ी भूमिका निभाई।

हालांकि अभी भी भाजपा इस मामले में सपा और बसपा से पीछे रह गई जहां पसमांदा समाज के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी क्रमश: 16 और 11 की संख्या में विजयी हुए लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि भाजपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम जिसके क्रमश: 3 और 2 ही पसमांदा समाज के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जीत दर्ज कर सके आगे रही। पसमांदा समाज को भाजपा से जोड़ने की नीति के शुरुआत में यह एक अच्छा परिणाम माना जा सकता है, विशेष रूप से एक ऐसे समाज से जुड़ना जो अब तक भाजपा को अछूत मानकर चुनाव के दौरान उसे वोट देने की बात करना तो दूर सोचता तक नहीं था। निकाय चुनाव में पसमांदा वोटरों ने निर्भीक होकर अशराफ के विरूद्ध, पसमांदा प्रत्याशियों को और जहां पसमांदा नहीं थे वहां हिंदू प्रत्याशियों को अपना मत देना उचित समझा। जहां तक जानकारी का प्रश्न है 1946 के चुनाव (जो सेपरेट इलेक्ट्रेट और सीमित मताधिकार पर केंद्रित था) के बाद शायद यह पहला चुनाव था जिसमें पसमांदा समाज ने खुलकर अशराफ वर्ग के विरूद्ध चुनाव प्रचार और वोटिंग की। जिस कारण पिछले चुनाव की तुलना में अधिक संख्या में निर्दल एवं अन्य पार्टियों से भी पसमांदा उम्मीदवार जीत दर्ज कर सके।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

मुस्लिम अब भाजपा की ओर आकर्षित

पसमांदा ने मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाले अशराफ मुसलमानों के प्रभाव से निकलते हुए स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना सीखा फिर यह अवधारणा भी खत्म हुई कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं करता, दूसरा यह रास्ता भी मिल गया कि अगर भाजपा को मुसलमानों पर ध्यान केंद्रित करना है तो वो कौन सा वर्ग है जिस पर उसको ध्यान केंद्रित करना है और यह वर्ग निसंदेह मुसलमानों का वंचित तबका है जिसे अब देशज पसमांदा कहा जाने लगा है जो एक अनुमान के मुताबिक कुल मुसलमानों की जनसंख्या का लगभग 90 प्रतिशत भाग है। भाजपा के रणनीतिकार यह समझ रहे हैं कि इतने बड़े समूह को अगर जोड़ने का प्रयास किया गया तो अगर पूरा न सही कुछ भी लोग लामबंद हुए तो वोटरों की एक अच्छी संख्या उनके पक्ष में आ सकती है। इससे ना सिर्फ उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत में भी पांव पसारने में आने वाली रुकावटें काफी कम हो सकती हैं। जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को भाजपा के पक्ष में बदलने में निर्णायक साबित हो सकती है। और पसमांदा समाज जो अब तक राजनीतिक रूप से अपनी पहचान और नेतृत्व बनाने में नाकामयाब रहा है, भाजपा उनकी इस नाकामी को कामयाबी में बदल सकती है। इसलिए ऐसा अनुमान है कि आने वाले विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव में भाजपा की योजना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि अब वो मुसलमानों को अपने लक्ष्य से बाहर रखने के बजाय मुसलमानों के वंचित एवं बड़े तबके पसमांदा वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर अपने तरीके से आगे बढ़ेगी।

परंपरा बदलेगी क्या?

राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। हाल ही में बजट पेश कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2023 में 156 सीट जीतकर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। गहलोत ने रिटायरमेंट के चर्चे को भी सिरे से खारिज कर दिया है। राजनीति में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत के हालिया बयान से भाजपा भी चौकन्ना हो गई है। 5 साल से सत्ता से बाहर चल रही भाजपा भी नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन अशोक गहलोत के दांव को चित करना पार्टी के लिए आसान नहीं दिख रहा है। 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बेहद लो प्रोफाइल में रहने वाले और कड़क चाय के शौकीन गहलोत संगठन और सरकार में बड़े पदों पर रह चुके हैं। राजस्थान समेत उत्तर भारत के राजनीतिक हालातों से वे भली-भांति वाकिफ हैं।

पिछले 25 सालों से राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इस परंपरा की चपेट में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे 2-2 बार आ चुके हैं। पायलट गुट कांग्रेस हाईकमान से रिवाज **पॉलिटिक्स का उदाहरण देकर** मुख्यमंत्री बदलने की भी मांग कर रही है। हालांकि, गहलोत का दावा है कि इस बार यह परंपरा टूट जाएगी और कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी। अशोक गहलोत ने इसके लिए रणनीति भी तैयार की है।

अशोक गहलोत सरकार पिछले 5 सालों में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है। इनमें चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा रसोई योजना और ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना प्रमुख हैं। इन सभी योजनाओं के जरिए 2 करोड़ लोगों तक सीधा पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। हाल के दिनों में गहलोत की टीम ने सभी माध्यमों से इन योजनाओं का खूब प्रचार-प्रसार भी किया गया है। अशोक गहलोत ने हाल ही में कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की है, जो काफी चर्चा में है। राजस्थान सरकार ने राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। 70 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा गरीब परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा सरकार ने किया है। अशोक गहलोत को उम्मीद है कि ये सभी योजनाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी को लगाम लगाते हुए हाल ही में अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री ही चुनाव में चेहरा होता है। गहलोत के इस बयान का कांग्रेस हाईकमान की ओर से अब तक खंडन नहीं किया गया है। कांग्रेस के भीतर गहलोत को हटाने की मांग भी उठ रही थी, लेकिन यह भी ठंडे बस्ते में चला गया है। जुलाई तक अगर कोई बड़ा बदलाव राजस्थान में नहीं होता है, तो कांग्रेस में अशोक गहलोत ही चुनाव का चेहरा हो सकते हैं। भाजपा में अभी भी सिरफुटौव्वल जारी है। करीब एक महीना बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला नहीं हो सका है। भाजपा में वसुंधरा राजे फिर से सक्रिय हो गई हैं। इसी बीच अशोक गहलोत ने एक चुनावी एजेंसी को हायर किया है। यह एजेंसी पहले भी कई राज्यों में काम कर चुकी है। एजेंसी गहलोत के चेहरे पर फोकस कर रही है। भाजपा की तरह राजस्थान में कांग्रेस भी अशोक गहलोत बनाम कौन का नारा बुलंद कर सकती है। गहलोत के इस दांव ने भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है।

दिग्गज नेताओं के टिकट कटेंगे

2003 और 2013 में अशोक गहलोत के रहते राजस्थान में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। हार की बड़ी वजह दिग्गज मंत्रियों और विधायकों का चुनाव हारना था। पार्टी इस बार इससे सबक लेकर कई नेताओं का टिकट काट सकती है। 2013 में कांग्रेस ने 75 विधायकों को फिर से टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 5 विधायक ही चुनाव जीत पाए। गहलोत कैबिनेट के 31 नेता चुनाव हार गए। इनमें शांति धारीवाल, भंवरलाल मेघवाल, ब्रजकिशोर शर्मा, परसादीलाल, डॉ. जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारीक, हेमाराम और हरजीराम बुरड़क जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। बात 2003 की करें तो उस वक्त कांग्रेस के सिर्फ 34 विधायक फिर से चुनाव जीतकर आने में सफल रहे। सरकार के 19 मंत्री बुरी तरह चुनाव हार गए। इनमें कमला बेनीवाल, हरेंद्र मिर्धा और शांति धारीवाल जैसे नाम शामिल थे। कांग्रेस इस बार बड़ी संख्या में मंत्रियों और विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी ने पिछले ही साल कुछ दिग्गज नेताओं को संगठन में भेजकर मंत्री पद ले लिया था। आने वाले वक्त में इस फॉर्मूले को और तेजी से लागू किया जा सकता है।

अशोक गहलोत आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान को 8 नए जिलों की सौगात दे सकते हैं। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक बाड़मेर से अलग कर बालोतरा, अजमेर से अलग कर ब्यावर, जोधपुर से अलग कर फलोदी और जालौर से अलग कर सांचौर को जिला बनाया जा सकता है। इसके अलावा जयपुर से अलग कर कोटपूतली, सवाई माधोपुर से अलग कर गंगापुर सिटी, भरतपुर से अलग कर बयाना और नागौर से अलग कर डीडवाना को जिले बनाने की चर्चा है। अशोक गहलोत इस दांव से करीब 40 सीटों पर सीधा पकड़ बना लेंगे। इन जिलों की मांग लंबे वक्त से उठ रही है। कांग्रेस सरकार के मंत्री और नेता भी इसकी मांग उठा रहे हैं।

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर सीधे राजस्थान सरकार केंद्र पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री मोदी की एक मीटिंग में गहलोत ने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया था और उनकी ओर से किए गए वादे को भी याद दिलाया था। यह प्रोजेक्ट अगर राजस्थान में शुरू हो गया तो राज्य के 13 जिलों को पानी मिलेगा। गहलोत आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर केंद्र की घेराबंदी करेंगे। गहलोत सरकार संजीवनी घोटाले को भी जोरशोर से उठा रही है। अशोक गहलोत ने इस घोटाले में मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी परिवार की भूमिका पर सवाल उठाया था। अशोक गहलोत को पार्टी के भीतर ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी सचिन पायलट और हरीश चौधरी गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

उद्घाटन से पहले ही क्यों गिर रहे पुल?

17 10 करोड़ रुपए के बजट से बन रहा बिहार का अगवानी-सुल्तानगंज गंगा महासेतु अपने आप, खड़े-खड़े पल भर में नदी में समा गया। पुल लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका था और कुछ महीने बाद ही इसका उद्घाटन होने वाला था। जिस तरह यह पुल गिरा उस तरह तो रेत की भी कोई दीवार कभी नहीं गिरी होगी।

निर्माणाधीन पुल के गिरने से बिहार की सरकारी मशीनरी, उपयोग में लाई जा रही तकनीकी और सामग्री तथा निगरानी तंत्र सवालों के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं कि जनता के अरबों रुपए की इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका उत्तर देने में बिहार सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही। हां, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, निर्माता कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी दे दिया गया है और सप्ताह भर में ही हमेशा की तरह मामले को ठंडे बस्ते में जाने लायक बनाया जा चुका है। 4 जून को यह घटना हुई और 12 जून तक निर्माता कंपनी का कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण तक सामने नहीं आया है। बहरहाल, मामला सनसनीखेज है, लोगों के संज्ञान में है तो राजनीतिक बयानबाजी में कोई कमी नहीं है। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच **शाब्दिक युद्ध** जमकर चल रहा है। भाजपा ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि जब बालासोर रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है, तो बिहार में निर्माणाधीन महासेतु के बार-बार ढहने की जांच भी तकनीकी कमेटी के साथ-साथ सीबीआई से भी होनी चाहिए।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, इस पुल के घटिया निर्माण की बात बार-बार सदन में उठाई गई। सरकार ने कहा था जांच होगी। बड़े अधिकारी कमीशन लेकर सरकार तक पहुंचाते हैं। नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं कि न्यायिक जांच कराए क्योंकि इसमें जो लिप्त हैं वे सरकार में हैं। विपक्ष के जवाब में सत्ताधारी पक्ष की ओर से राजद नेता और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर ही आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा, सीबीआई वाले इंजीनियर तो हैं नहीं कि इसकी जांच करेंगे। वहीं तेजस्वी के बड़े भाई और मंत्री तेज प्रताप यादव तो यहां तक कह गए कि हम पुल बना रहे हैं और भाजपा गिरा रही है।

हर बार की तरह मामला दो-चार दिनों के आरोप-प्रत्यारोप के बाद ठंडा हो गया है। लेकिन कई गंभीर सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सरकार को ढूंढना ही चाहिए। पहला सवाल यह है कि बिहार में उद्घाटन से पहले ही बार-बार पुल क्यों गिर जाते हैं। गौरतलब है कि पिछले कोई एक-डेढ़ साल में ही राज्य में चार बड़े पुल या बड़ी संरचनाएं निर्माण के दौरान या उद्घाटन से ठीक पहले ध्वस्त हुए हैं। दिसंबर, 2022 में बेगुसराय में बूढ़ी गंडक पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया था। पिछले साल ही नवंबर में नालंदा जिले में एक बड़ा पुल निर्माण के दौरान धाराशायी हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। किशनगंज और सहरसा में भी कुछ समय पहले बड़ी लागत से बन रहा पुल और फ्लाईओवर गिर गया था। लेकिन कभी भी न तो इसका कारण सार्वजनिक हुआ न ही निर्माता कंपनी पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। अगवानी-सुल्तानगंज महासेतु तो 14 महीने के अंदर ही दो बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। 30 अप्रैल 2022 को पुल के पिलर नंबर 4, 5 और 6 का हिस्सा गिर गया था। इसके बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी आईआईटी रूड़की की एक विशेषज्ञ टीम को दी गई थी। लेकिन जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अनवरत काम चलता रहा। जबकि अनाधिकारिक रूप से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि पुल के डिजाइन में दोष है।

गौरतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही है, बिहार में उसका रिकॉर्ड खराब रहा है। कम से कम चार मौकों पर इस कंपनी द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने का मामला सामने आ चुका है। तीन वर्ष पूर्व पटना में लोहिया पथ चक्र के निर्माण के दौरान एक बड़ा स्लैब गिर गया जिसकी चपेट में आकर तीन बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन इसे लेकर क्या कार्रवाई हुई, यह सवाल अनुत्तरित है। इसके अलावा कंपनी द्वारा कोसी महासेतु के निर्माण के दौरान भी पुल का एक हिस्सा नदी में बह गया था। इसके बावजूद कंपनी को राज्य में कई सारी बड़ी निर्माण परियोजना का ठेका मिला हुआ है। आखिर क्यों? इसी प्रश्न के अंदर सारा जवाब छिपा हुआ है।

● **विनोद बक्सरी**

निर्माण परियोजनाओं से दिखता है विकास

दरअसल, बिहार सरकार ने हाल के एक दशक में सर्वाधिक प्रशंसा निर्माण परियोजना के क्षेत्र में हासिल की है। राज्य में बड़ी संख्या में सड़क, पुल, विद्यालय भवन समेत सरकारी भवनों का निर्माण कार्य हुआ है और हो रहा है। तमाम राजनीतिक जोड़तोड़ और प्रशासनिक अनिश्चितता के बावजूद निर्माण परियोजनाएं अनवरत गति से चलती रहती हैं। सरकार की अन्य विकास परियोजनाएं भले ही बाधित हो जाएं या शुरू भी न हों, लेकिन सामान्यतः निर्माण परियोजनाएं बाधित नहीं होतीं। बाधा आने पर इसे प्राथमिकता के साथ दूर किया जाता है। निर्माण परियोजना की मंजूरी से लेकर टेंडर और बजट आवंटन में एक स्फूर्ति बिहार में हर स्तर पर दिखाई देती है। क्यों? समझना आसान है, लेकिन साबित करना कठिन है। कुछ साल पहले इस पंक्ति के लेखक को बिहार और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे ने कहा था- निर्माण परियोजना ही एकमात्र ऐसी सरकारी परियोजना होती है, जिसमें हर किसी को खुश करने का अवसर रहता है। जनता के लिए यह उपयोगी होती है और सीधे सबको नजर आती है। इसका बजट सामान्यतः काफी बड़ा रहता है, जिसमें नीचे से ऊपर तक हर किसी को खुश करने की गुंजाइश रहती है।

चीन की चुनौती को भारत का जोजिला जवाब

जिस गति से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार मूलभूत ढांचे का निर्माण कर रही है वह अभूतपूर्व और अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय इसलिए कि कोई विकसित और उन्नत तकनीकी दक्ष देश भी ऐसे दुरूह प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने से पहले सौ बार सोचेगा। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जोजिला सुरंग। समुद्र तल से 11,600 फुट ऊपर यह दर्रा दुरूहतम दर्रों में एक है। जोजिला दर्रा (पास) इतना दुरूह है कि कम से कम 5-6 महीने हिमपात और हिम जमाव के कारण इस पर आवागमन संभव ही नहीं होता। यह पास कश्मीर क्षेत्र को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। यह श्रीनगर से लगभग 100 किमी दूर कारगिल जिले में स्थित है। लद्दाख को जोड़ने वाले मात्र दो ही पास (दर्रे) हैं, एक हिमाचल से होकर जाने वाला रोहतांग पास और दूसरा कश्मीर से जाने वाला जोजिला पास। ये दोनों ही पास लद्दाख को भारत की मुख्य भूमि से पूरे वर्ष जोड़कर रखने में सक्षम नहीं हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र शेष भारत भूमि से सड़क मार्ग से कटा रहता है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे टकराव और मूलभूत ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है और कर रही है। इन दोनों दर्रों के नीचे पहाड़ को चीरकर पूरे वर्ष प्रयोग किए जाने वाला राजमार्ग (आल वेदर रोड) बनाया जा रहा है। रोहतांग के विकल्प के रूप में अटल सुरंग तैयार हो चुकी है। अब जोजिला सुरंग की बारी है। इस सुरंग के निर्माण का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया। यह सुरंग लगभग 14 किमी लंबी है। यह दो-तरफा सुरंग मार्ग जो एशिया में अपने तरह का सबसे लंबा है।

इस प्रोजेक्ट के महत्व को समझने के लिए इतना जान लेना ही काफी होगा कि इसे केंद्रीय स्तर पर निरंतर निगरानी में बनाया जा रहा है। अप्रैल के महीने में जहां सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ जोजिला का दौरा करके निर्माण कार्य का जायजा लिया था वहीं दो दिन पहले लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने इस जगह का दौरा करके निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस सुरंग का निर्माण कार्य सरकार के शिखर नेतृत्व की पहल पर हो रहा है। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के उपराज्यपाल तथा केंद्रीय राजमार्ग मंत्री स्वयं इसका समय-समय पर निरीक्षण करते रहते हैं।

ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार

जोजिला दर्रे के पास का इलाका बेहद दुर्गम है, यहां हर साल कई घातक दुर्घटनाएं होती हैं। जोजिला टनल का काम पूरा होने के बाद हादसों की संभावना जीरो हो जाएगी। यह सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच सालभर संपर्क प्रदान करेगी, जो लद्दाख के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय सामानों की मुक्त आवाजाही और आपात स्थिति में भारतीय सशस्त्र बलों की आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मोदी सरकार की यह पहल वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट चीन द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व ढांचागत विकास का एक उपयुक्त उत्तर है। यह पूर्व सरकारों की नीति से बिल्कुल विपरीत इस बात का प्रमाण है कि भारत-चीन के समक्ष बिल्कुल झुकेगा नहीं और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है।

जम्मू-कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 19 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत जोजिला में 6800 करोड़ रुपए की लागत से 13.14 किलोमीटर लंबी टनल व अप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह 7.57 मीटर ऊंची घोड़े की नाल के आकार की सिंगल-ट्यूब, 2-लेन सुरंग है, जो कश्मीर में गांदरबल और लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरेगी। परियोजना में एक स्मार्ट टनल प्रणाली शामिल है, जिसका निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके किया गया है। यह सीसीटीवी, रेडियो कंट्रोल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, वेंटिलेशन जैसी सुविधाओं से लैस है। इस परियोजना में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से भारत सरकार के 5000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है।

जोजिला टनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 13,153 मीटर की मुख्य जोजिला टनल, कुल लंबाई 810 मीटर की 4 पुलिया, 4 नीलग्रार टनल, कुल लंबाई 4,821 मीटर, 8 कट एंड कवर कुल लंबाई 2,350 मीटर और तीन 500 मीटर, 391 मीटर और 220 मीटर ऊर्ध्वाधर वेंटिलेशन शाफ्ट प्रस्तावित हैं। अभी तक जोजिला टनल का 28 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इस टनल के बनने से लद्दाख के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी हो जाएगी। वर्तमान में जोजिला दर्रे को पार करने में औसत यात्रा समय कभी-कभी तीन घंटे लगते हैं, इस सुरंग के पूरा होने के बाद यात्रा का समय घटकर 20 मिनट रह जाएगा। यात्रा के समय में कमी से अंततः ईंधन की बचत के अलावा कई फायदे होंगे।

एक, पूरे वर्ष वाहनों का आवागमन अबाधित रूप से चलता रहेगा। सेना के रसद और उपस्कर पूरे वर्ष पूर्ति किए जा सकेंगे। आयुध, अम्युनिशन, युद्धक सामग्री की अबाध पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। युद्ध की स्थिति में यह सुरंग रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दुर्घटनाएं कम होंगी। लद्दाख में तैनात लगभग 60,000 सैन्य बल को ताजे फल, भोजन, मीट, सब्जियां इत्यादि उपलब्ध हो सकेगी। अभी लगभग 8 महीने की आवश्यक सामग्री संग्रहीत करके रखनी होती है। इस टनल के बन जाने से सेना का मनोबल और आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा। अतः ऐसा ढांचागत निर्माण जहां चीन की ढांचागत श्रेष्ठता को समाप्त करेगा वहीं भारतीयों का मनोबल ऊंचा होगा।

● कुमार विनोद

दोस्ती या मजबूरी

भारत के परंपरागत मोटे अनाजों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इसके उपयोग की सलाह देते रहते हैं। इसका कारण है मोटे अनाज से सेहत को होने वाला फायदा। यही कारण है कि 22 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगर प्रधानमंत्री मोदी को दिए शाही भोज में अगर बाजरे को शामिल करवाया तो निश्चय ही उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य के साथ भारत-अमेरिका रिश्तों को एक नई गर्माहट देने का संकेत भी दिया है।

रिश्तों में जबर्दस्त उत्साह तब दिखा जब राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी को भोजन के उपरांत एक विंटेज अमेरिकी कैमरा उपहार में दिया, साथ ही पहले कोडक कैमरे के लिए जॉर्ज ईस्टमैन के पेटेंट का एक अभिलेखीय प्रतिकृति प्रिंट भी भेंट किया, जो फोटोग्राफी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। राष्ट्रपति बाइडेन को संभवतः ज्ञात है कि प्रधानमंत्री मोदी को फोटोग्राफी का पुराना शौक है। इसके अलावा अमेरिकी वन्यजीवों पर एक हार्डकवर पुस्तक भी प्रदान की जिसमें अमेरिका की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता पर प्रकाश डाला गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमानों के लिए इंजन और तकनीक के साथ 3 बिलियन डॉलर के रक्षा ड्रोन सौदे पर हस्ताक्षर करना है जो कि भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा के अन्य विंग को मजबूत करेगा। भारतीय शेयर बाजार में इसी बात पर जबर्दस्त उत्साह का माहौल देखा गया कि भविष्य में भारत ड्रोन निर्माण का बड़ा केंद्र बन जाएगा। बाजार को मध्यम से लंबी अवधि में इनहाउस डिफेंस ड्रोन की मांग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों अमेरिका के स्टेट गेस्ट के रूप में पहुंचे हैं और पूरा अमेरिका उनकी इस यात्रा को लेकर जबर्दस्त उत्साहित है। बिजनेस हाउस से लेकर डिप्लोमेट तक मोदीमय हो चुके हैं और ऐसा होने के वाजिब कारण भी हैं। कभी भारत को हल्के में लेने वाले तमाम अमेरिकी अपने रूख में यदि परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके पीछे भारत की उन्नति तो है लेकिन अमेरीकियों की अपनी मजबूरी भी है। घोषित रूप से अमेरिकी विदेश विभाग जब यह कहता है कि अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को बनाए रखने सहित साझा मूल्यों पर आधारित है तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन अमेरिका के लिए व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, वैश्विक सुरक्षा, वैश्विक स्थिरता और अब खुद अमेरिकी आर्थिक समृद्धि के लिए भारत के साथ साझेदारी बनाना हितकर है।

राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने व्यक्तिगत रूप से इन संबंधों को यहां तक पहुंचाने में अपनी-अपनी ओर से खूब पहल की है। दोनों ने कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड लीडर्स तंत्र को भी विकसित किया है। वैश्विक शांति सुरक्षा और स्थिरता के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदारी भी की है। भारत के लिए यदि चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए यह भागीदारी जरूरी है तो अमेरिका के लिए चीन की आर्थिक समृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों से जूझने की यह ताकत है। अब तो अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी संख्या भी है। अमेरिका की कुल 34 करोड़ की जनसंख्या में भारतीय मूल के भी अब चार करोड़ लोग हो गए हैं। यानी अमेरिकी लोकतंत्र में भारतवासियों की अच्छी खासी हिस्सेदारी भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की इस राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका ने जबर्दस्त तैयारियां की है। अमेरिकी विदेश और रक्षा सचिवों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच 22 मंत्रिस्तरीय वार्ता की गई। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने दर्जनों द्विपक्षीय वार्ता और कार्य समूहों का भी सहयोग लिया गया। जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर स्वास्थ्य, ऊर्जा से लेकर उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र शामिल हैं। यूएस-इंडिया काउंटरटेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप को भी इस तैयारी में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अगले दो दिन जिन विषयों पर वार्ता और समझौता करने वाले हैं उनमें स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, साइबर डायलॉग, सिविल स्पेस वर्किंग ग्रुप, शिक्षा और कौशल विकास वर्किंग ग्रुप, व्यापार नीति मंच, रक्षा नीति समूह, और काउंटरनारकोटिक्स कार्य समूह के मसौदे भी शामिल हैं।

भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता मोदी के इस दौरे का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस समय व्यापार रिकॉर्ड 160 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। कई अमेरिकी कंपनियां इस समय मोदी से मिलने और भारत में निवेश के लिए इंतजार कर रही हैं। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह भारत में अपना प्लांट लगाएगी। इसी तरह, भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के समर्थन से भारत दो साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल रह चुका है। अब भारत की कोशिश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनने में है। अमेरिका इसका समर्थन कर चुका है, परंतु चीन लगातार इसमें अड़ंगा लगा रहा है। अब जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही हैं उसमें चीन के लिए भारत का खुला विरोध भारी पड़ सकता है। क्योंकि भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र को ठोस लाभ प्रदान करने के लिए क्वाड के रूप में एकजुटता दिखाई है। क्वाड को लेकर चीन अब काफी सतर्क हो गया है।

● **अक्स ब्यूरो**

दोस्ती दोनों देशों की जरूरत

अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में नई मिठास के लिए दोनों देशों की परस्पर एक-दूसरे की आवश्यकताएं हैं। अमेरिका में संसाधनों की अधिकता है और मानव संसाधनों की कमी है। अभी तक चीन अमेरिकी निवेश का बड़ा हिस्सा अपने यहां ले जाता था पर अमेरिका के प्रति चीन के बदलते रूख ने अमेरिका को भारत की ओर झुकने को मजबूर किया है। अमेरिका की नजर में भारत ही एक ऐसा देश है जो साम्राज्यवाद की सोच से दूर है। भारत को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अमेरिका को कोई बड़ी कीमत अदा नहीं करनी है। दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए भारत की समुद्री सीमा को मजबूत करना उसके लिए फायदेमंद है। इसीलिए वह भारतीय नौसेना को आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बेचने से पीछे नहीं हट रहा है।

चुनावी चौसर पर मप्र की महिलाएं

मप्र में क्या महिलाएं ही तय करेंगी कि अगली सरकार किसकी होगी? इस सवाल की वजह है मप्र का चुनावी मैदान, जिसके दोनों प्रमुख सेनापति महिलाओं को ही लुभाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इसकी शुरूआत 10 जून को राज्य की संस्कारधानी के रूप में मशहूर जबलपुर के गैरीसन मैदान से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, तो अगले दिन उनके जवाब के रूप में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसी शहर से अपना चुनावी अभियान शुरू किया। शिवराज ने अपनी महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना शुरू की तो अगले दिन प्रियंका गांधी ने कमलनाथ के उन वादों को एक बार फिर दोहराया, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने डेढ़ हजार रुपए और पांच सौ रुपए में गैस का सिलेंडर देने का वादा है। कांग्रेस महासचिव एक कदम आगे बढ़ गईं, उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा भी कर डाला।

सवाल यह है कि आखिर महिलाओं पर ही राज्य के दोनों दल क्यों मेहरबान नजर आ रहे हैं? दरअसल राज्य में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 52 फीसदी है, यानी पुरूषों की तुलना में करीब **चार फीसदी ज्यादा।** यहां याद कर लेना चाहिए कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 5 करोड़ 39 लाख वोटर हैं। दोनों दलों की ओर से महिलाओं पर दांव लगाने की दूसरी वजह महिला वोटरों का बदलता वोटिंग ट्रेंड है। महिलाएं अपने घर के पुरूषों, पति या पिता की सोच और आदेश के मुताबिक उनकी पसंदीदा पार्टी और मतदाता को वोट बीते दिनों में देती थीं। अब ऐसा नहीं होता।

अब महिलाएं अपने ढंग से सोचती हैं और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देती हैं। इसका उदाहरण हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल, पंजाब, उप्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं। जहां महिला मतदाताओं ने अपने ढंग से वोट डाला, अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को चुना। कुछ इसी अंदाज में शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस दोनों ही महिलाओं को ही लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जिस लाड़ली बहना योजना की शुरूआत की, उसके हिसाब से राज्य की करीब 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को प्रति महीने एक हजार रुपए मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत 23 से 60 साल की उम्र वाली करीब सवा करोड़ महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनके खातों को जांचने के लिए योजना शुरू होने के तीन दिन पहले एक रुपए डाला गया था। इनमें से करीब 5 लाख खातों में पैसे नहीं पहुंचे, लेकिन जिन 1 करोड़ 20 लाख खातों में एक रुपए का सफल ट्रांजेक्शन हुआ, उनमें पैसे भेजे जा चुके हैं। इस योजना के तहत उन महिलाओं को चुना गया है, जिनके परिवार के पास पांच एकड़ से कम जमीन है और जिनके परिवार की सालाना आमदनी ढाई लाख से कम है।

कर्नाटक और हिमाचल में मुफ्त सुविधाएं देने के वायदे की बुनियाद पर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी कर ली है। कांग्रेस इससे जहां उत्साहित है, वहीं भाजपा मुश्किल महसूस कर रही है। उसी के जवाब में शिवराज ने लाड़ली बहना योजना की शुरूआत की। हालांकि उनके सामने चुनौती कांग्रेस की डेढ़ हजार रुपए मासिक देने का वादा है। शायद जबलपुर में ही अगले दिन होने वाली प्रियंका की रैली और उसके असर की आशंका रही कि गैरीसन मैदान में बने भव्य मंच पर पहुंचने के बाद शिवराज ने लाड़ली बहना योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसके तहत उन्होंने सुविधाएं पाने के लिए महिलाओं की उम्र सीमा का दायरा 23 से घटाकर 21 कर दिया। बशर्ते कि उनकी शादी हो गई हो। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले वे धन का इंतजाम करेंगे और इस रकम को बढ़ाकर पहले साढ़े बारह सौ महीना करेंगे। फिर धन का इंतजाम करेंगे और इस रकम को और बढ़ाकर 1750 रुपए प्रति महीना करेंगे। फिर धन का इंतजाम हुआ तो इसे बढ़ाकर तीन हजार कर देंगे। यानी कांग्रेस के वायदे से दो गुना का इंतजाम। फिलहाल इस योजना के लिए शिवराज सरकार ने 8 हजार करोड़ का इंतजाम किया है। इसकी घोषणा शिवराज सरकार ने बजट के दौरान ही की थी।

मुख्यमंत्री शिवराज के इस वायदे को कांग्रेस के वायदे का जवाब माना जा रहा है। मप्र भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि शिवराज की इस घोषणा से उनके वोट बैंक में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई है। सरकारी योजनाओं की राह में सबसे बड़ी बाधा उनकी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाना रही है। शायद इसी का ध्यान रखते हुए मप्र के करीब 32 हजार मतदान केंद्रों पर शिवराज की घोषणा को सीधे दिखाने-सुनाने का इंतजाम प्रदेश भाजपा ने किया था जो कुल 64 हजार मतदान केंद्रों का आधा बैठता है।

आज का वोटर चमक-दमक से भी प्रभावित होता है। मप्र में वोटरों को अपने पाले में करने के लिए चमक-दमक का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की बंदिशों की सीमा में चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियों की ओर से यह चमक-दमक खूब दिखेगी। शिवराज ने जबलपुर में धूमधड़ाके के साथ योजना की शुरूआत की, महिलाओं के पांव पखारे, उनके पांव छुए। जबलपुर से निकलने के पहले उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती उमा भारती का आशीर्वाद लिया। माना जा रहा है कि मप्र भाजपा को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। फिर कांग्रेस के वायदे भी भाजपा पर भारी पड़ेंगे। लेकिन ऐसा सोचते वक्त एक तथ्य भुला दिया जाता है। कांग्रेस जहां वादा कर रही है, वहीं भाजपा अपनी सरकार के जरिए चुनावों तक तकरीबन हर जरूरतमंद महिला तक पांच हजार रुपए पहुंचा चुकी होगी। किसी-किसी परिवार में दो या तीन महिलाएं भी इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना आसान होगा कि जिस परिवार में पांच, दस या पंद्रह हजार रुपए पहुंचेंगे तो उस परिवार की सोच क्या होगी? निश्चित तौर पर उस परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। अगर योजना के तहत रजिस्टर्ड सवा करोड़ महिलाओं की तुलना में 60 प्रतिशत ने भी शिवराज सरकार के प्रति सहानुभूति दिखाई तो यह संख्या 75 लाख होती है। यानी भाजपा के खाते में थोक में इतने वोट आएंगे। इससे स्पष्ट है कि भाजपा को चुनावी मैदान में फायदा हो सकता है। इसी फायदे पर बीजेपी की निगाह है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

mycem
cement
HEIDELBERGCEMENT
mycem power
Trusted German Quality
Over 150 Years
Send 'Hi' 7236955555

बेरोजगारी

गरीबी और भूख से व्याकुल, बेरोजगारी से परेशान, एक अदद नौकरी के लिए एक दफ्तर और दूसरे और फिर तीसरे दफ्तर भटकते-भटकते रामदयाल पांडेय अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ।

मृत्यु देवता ने उसके सुकर्मों को देखते हुए कहा- तुमने पिछले जनम में बहुत अच्छे काम किए हैं। इसलिए तुम्हें फिर से एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्रदान किया जा रहा है।

रामदयाल पांडेय मृत्यु देवता के पैरों में गिर पड़ा। कातर भाव से बोला- मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं चाहिए महाराज! यदि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे देखते हुए कृपया मुझे किसी अच्छे खाते-पीते अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार में जन्म लेने दीजिए ताकि फिर से मुझे बेरोजगारी का सामना करना न पड़े।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

मुंह पर थप्पड़

मानसी और जयंत बचपन से साथ-साथ पढ़े थे। एमबीए की पढ़ाई के बाद मानसी ने जॉब कर ली थी, उधर जयंत ब्रेक लेकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था।

दोनों की दोस्ती जब प्यार में बदली, तो परिवार वालों की सहमति से दोनों की शादी तय कर दी गई। उनकी शादी को सिर्फ एक हफ्ता ही बचा था कि यूपीएससी का रिजल्ट निकला और जयंत की काफी अच्छी रैंक आने के कारण उसका आईएएस प्रौपर में चयन हो गया था। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था कि एक दिन जयंत के चाचा जी घर आए और शादी की खातिरदारी से लेकर दहेज की एक लंबी लिस्ट थमाकर यह कहकर चले गए कि अब तो आपकी बेटी की शादी एक आईएएस से होने जा रही है तो आपको उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर शादी करनी होगी, वगैरह-वगैरह।

मानसी को जब यह पता चला तो उसने जयंत को फोन किया। पहले तो जयंत ने मानसी का फोन अटैंड नहीं किया, और जब फोन उठाया तो सीधे जवाब देने की बजाय टालमटोली करता रहा, और जब मानसी ने सीधे-सीधे सवाल किया कि जयंत तुम यह बताओ कि वह तुम्हारे जो चाचाजी दहेज की सूची दे गए हैं, तो वह क्या तुम्हारी जानकारी में है?

हां! है तो।

या, तुम उससे सहमत नहीं?

नहीं।

मतलब असहमत हो?

नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा।

मतलब यह कि वह सूची मेरे पापा व चाचा ने बनाई है, तो सहमत न होते हुए भी मुझे मानना पड़ेगा। और फिर इसमें बुराई भी क्या है, आखिर तुम्हारी शादी आईएएस जो हो रही है। तुम्हारे जीवन के शान व सुख-सुविधा से गुजरने की गारंटी भी तो है।

मतलब, यह तुम लोगों का अंतिम फैसला है?

हां! ऐसा ही समझो।

और हमारे प्यार का क्या?

वह तो हमने तब किया था, जब मैं आईएएस नहीं था।

ओके! तो मैं इस रिश्ते को अभी खत्म करती हूं। मुझे नहीं करना दहेज के लालचियों के घर अपना रिश्ता।

और फुंफकारती हुई मानसी चली गई, और जुट गई जी-जान से यूपीएससी की तैयारी करने में।

- प्रो. (डॉ.) शरद नारायण खरे

गीत

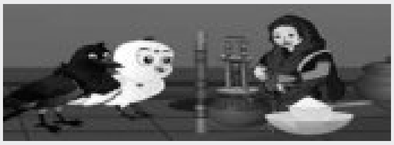

काट करके पंख तूने पक्षियों से गगन छीना,
व्याध तुझको शाप है, तेरा पतन हो!
पीर पर हंसता रहा तू,
हाय कुत्सित बुद्धि वाले।
सिर्फ चेहरा ही नहीं,
हैं कर्म तेरे और काले।

तू स्वयं में पाप है, तेरा पतन हो।
व्याध तुझको शाप है...

पक्षियों के मधुर कलरव,
हो गए हैं मौन सारे।
भय भरे हैं नीड़ सब,
तूने जहर के तीर मारे।

विपिन मे संताप है, तेरा पतन हो।
व्याध तुझको शाप है...

बोझ हत्याओं का लादे,
तू अधम चलता रहा है।
स्वार्थ में खगवृंद को
यमदूत बन डसता रहा है।
अति अधम तू सांप है, तेरा पतन हो।
व्याध तुझको

शाप तेरी मति हमेशा,
अधम कर्मों मे लगाए।
मन सशंकित ही रहे,
तू शांति को ढूंढ न पाए।
मौन ही अभिशाप है, तेरा पतन हो।
व्याध तुझको शाप है...

- डॉ. दिवाकर दत्त त्रिपाठी

इस बार एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर

इस बार एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं माना। इसके बाद हाइब्रिड मॉडल की बात पाकिस्तान ने कही जिसके तहत भारत के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होने थे और बाकी पाकिस्तान में। इसको भी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने अस्वीकार कर दिया था। मगर अब काफी मशक्कत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को बीसीसीआई सचिव जय शाह की अध्यक्षता वाली एसीसी की बैठक में हरी झंडी मिल गई है।

कई महीनों की खींचातान के बाद आखिरकार एशिया कप 2023 का ऐलान हो गया है। जिसके बाद सभी टीमें इस खिताब को अपने नाम करने के लिए तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन इस बार टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। जबकि फाइनल समेत बाकी मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। यानी क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर भारत-पाक के बीच वर्ल्डकप से पहले रोमांचक क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। वैसे भी भारत-पाकिस्तान की टीमें जब आमने-सामने होती हैं, तो फिर क्रिकेट अलग स्तर का हो ही जाता है। दरअसल, एशिया कप के आयोजन को लेकर उठा विवाद अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान के पास इस बार एशिया कप की मेजबानी है, जिसमें भारत-पाकिस्तान समेत कुल छह टीमों को हिस्सा लेना है। इस टूर्नामेंट को लेकर बीसीसीआई की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि भारतीय टीम किसी भी कीमत पर एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। ऐसे में पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट करने का प्रस्ताव दिया था। जिसको जय शाह की अध्यक्षता वाली एसीसी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाला टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेगा।

उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई के पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद पीसीबी अध्यक्ष नजम सेठी ने यह हाइब्रिड मॉडल प्रस्तावित किया था। एशिया कप 2023 भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल सहित छह टीमों का टूर्नामेंट होगा। नेपाल ने पहली बार इस आयोजन में जगह बनाई है। टूर्नामेंट में मौजूद 6 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। हर समूह से दो टीमें सुपर फोर चरण में आगे बढ़ेंगी। इसके बाद शीर्ष दो टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान के एक ही समूह में होने की उम्मीद है ताकि 13 मैचों की चैंपियनशिप में संभावित तीन बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले हो सकें। पाकिस्तान की टीम अपने मुकाबले लाहौर में खेलेगी। भारत और पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक पाकिस्तान में 4 मुकाबले खेले जाएंगे और 9 मुकाबले श्रीलंका में होने हैं। साल 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित टी-20 एशिया कप में पाकिस्तान को हराने के बाद श्रीलंका गत एशियाई चैंपियन है। इस साल श्रीलंका ग्रुप-बी में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है, जबकि भारत को लीग चरण में पाकिस्तान और नेपाल के ग्रुप में रखा गया है। हर ग्रुप से दो टीमें सुपर-चार चरण में प्रवेश करेंगी। दूसरे चरण में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें फाइनल में एक-दूसरे का सामना करेंगी।

एशिया कप की शुरुआत के बाद से अब तक भारत और पाकिस्तान का 13 बार आमना-सामना हो चुका है। इन मुकाबलों में जीत की बात करें तो भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है। भारत ने अब तक एशिया कप में पाकिस्तान को 8 बार हराया है। वहीं पाकिस्तान की टीम भारत को 5 बार हराने में कामयाब रही है। दोनों के बीच एक मुकाबला बारिश के कारण ड्रॉ रहा है। इस बार भारत और पाकिस्तान की टीम 28 अगस्त को आमने-सामने होंगी। एक ओर भारतीय टीम अपने टी-20 वर्ल्ड कप 2021 में मिली करारी हार का बदला लेना चाहेगी तो वहीं पाकिस्तान की टीम भारत को हराकर एशिया कप में अपने आंकड़े ठीक करना चाहेगी। एशिया कप के इतिहास में अब तक इसके 14 संस्करण हो चुके हैं। इस बार एशिया कप का 15वां सीजन खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत का दबदबा रहा है। भारत ने इस टूर्नामेंट को 7 बार अपने नाम किया है। वहीं श्रीलंका ने 5 बार और पाकिस्तान ने 2 बार इसे जीता है। एशिया कप के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम रही है। वर्ष 1984 में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। पहली बार भारत ने ही इस कप को अपने नाम किया था। पाकिस्तान की टीम वर्ष 2000 में पहली बार एशिया का सरताज बनने में सफल हो सकी। अब तक भारतीय टीम ने 7 बार एशिया कप को अपने नाम किया है। वहीं, श्रीलंका की टीम 5 बार इस खिताब को जीत चुकी है। जबकि पाकिस्तान की टीम 2 ही बार एशिया कप जीतने में सफल हो सकी। वहीं, बांग्लादेश ने अभी तक इस खिताब को नहीं जीता है। एशिया कप इस बार 50-50 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि विश्वकप को देखते हुए सभी टीमें इस खिताब की तैयारी में जुटी हैं। वहीं पाकिस्तान भी कप जीतने की रेस में बनी हुई है। ऐसे में इस बार टूर्नामेंट में काफी सारा रोमांच देखे जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

● आशीष नेमा

क्या था पूरा विवाद

आईसीसी के कैलेंडर में 2023 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई है। बीसीसीआई ने कैलेंडर जारी होते ही यह साफ कर दिया था कि भारतीय टीम खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं माना, क्योंकि अपनी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति संवारने के लिए उसे एशिया कप से ही उम्मीद है। पूरा मामला यह था कि टी-20 वर्ल्डकप 2022 के दौरान पाकिस्तान का दौरा करने से बीसीसीआई सचिव जय शाह ने मना कर दिया था। इसके बाद यह विवाद बढ़ता गया। तत्कालीन पीसीबी चीफ रमीज रजा ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत नहीं आने की भी धमकी दे डाली थी। फिर कुछ दिनों बाद पाकिस्तान क्रिकेट में सत्ता बदली और नजम सेठी आए। उन्होंने भी इस टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं करवाने की जिद पकड़े रखी। इसके बाद हाइब्रिड मॉडल की बात पाकिस्तान ने कही, जिसके तहत भारत के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होने थे और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में। इसको भी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब काफी मशक्कत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को बीसीसीआई सचिव जय शाह की अध्यक्षता वाली एसीसी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया है।

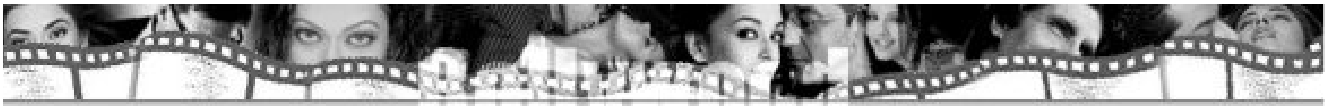

फिल्म के सेट पर माधुरी दीक्षित को पड़ती थी डांट...परेशान थे डायरेक्टर

90 के दशक में आई आमिर खान और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म दिल को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म की कहानी, किरदार और गानों को भी काफी पसंद किया गया था। यूं तो आमिर और माधुरी ने बहुत ज्यादा साथ में काम नहीं किया, लेकिन साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म दिल में दोनों सेट पर काफी मस्ती करते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी को मेकर्स से काफी डांट पड़ती थी।

आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल उस समय 2 करोड़ के बजट के साथ तैयार की गई थी। 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 20 करोड़ की बंपर कमाई की थी। इस फिल्म से मेकर्स भी मालामाल हो गए थे। ये फिल्म साल 1990 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म के सेट पर माधुरी को खूब डांट पड़ती है। हालांकि बाद में इसी फिल्म से धक धक गर्ल को पहला फिल्म फेयर अवॉर्ड भी मिला था। इस फिल्म के बीच में ही कुछ ऐसा भी हुआ था आमिर और माधुरी ने एक-दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। जब इस फिल्म को 30 साल पूरे हुए थे तो खुद माधुरी ने अपनी एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, आमिर खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बड़ा ही मजेदार था। मुझे आज भी याद है कैसे हम सेट पर पूरे दिन मस्ती किया करते थे और सेट पर लोगों के साथ प्रैंक करते थे। इसके लिए हमें खास तौर पर मुझे डायरेक्टर से डांट भी पड़ा करती थी।

2 करोड़ की फिल्म ने 20 करोड़ की थी धुंआधार कमाई

जब एक मजाक के चलते खफा हो गई थीं माधुरी

आमिर खान और माधुरी फिल्म दिल के सेट पर खूब मस्ती किया करते थे। इस बात का खुलासा खुद माधुरी भी कर चुकी हैं। वहीं आमिर भी अपने काम को सीरियसली करते हैं। लेकिन सेट पर अपने को-स्टार्स के मस्ती के आपने भी कई किस्से सुने होंगे। फिल्म दिल की शूटिंग के दौरान भी ऐसा ही हुआ। इसके बारे में उन्होंने खुद खुलासा किया था। आमिर ने बताया था कि एक बार वो माधुरी से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं हाथ देखकर लोगों के बारे में बता सकता हूं। बस फिर क्या था माधुरी दीक्षित ने हाथ बढ़ाया और आमिर ने हाथ देखते हुए उनसे कहा कि तुम काफी इमोशनल हो, तुम लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेती हो और ये कहते हुए उनके हाथ पर थूक दिया था। ये मजाक एक्ट्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आया था दोनों की सेट पर ही बातचीत भी बंद हो गई थी। बता दें कि इस फिल्म में माधुरी ने मधु और आमिर ने राजू नाम के लड़के का किरदार निभाया था। दोनों की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया था।

दिग्गज एक्टर बनना चाहते थे हीरो, एक वजह से बने बॉलीवुड के खूंखार विलेन

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। साल 1960 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रेम चोपड़ा ने सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी खलनायकी दिखाई कि लोग डर जाते थे। प्रेम चोपड़ा का ऐसा खौफ था कि लोग उनके सामने अपनी पत्नियों को छुपा लेते थे।

उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि, सभी एक्टर्स की तरह मैं भी हीरो बनना चाहता था। मैंने शुरुआत में कई पंजाबी फिल्मों में हीरो का रोल किया, जो अच्छी चलीं, लेकिन जब मैंने हिंदी सिनेमा में हीरो की भूमिका निभाई, तो फिल्में पिट गईं। एक्टर ने बताया कि अगर हीरो के तौर पर उनकी फिल्में चल जाती, तो वह हीरो बन जाते, लेकिन अच्छी बात ये हैं कि जब उन्होंने विलेन का रोल करना शुरू किया, तो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब हिट हुईं। हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहता था कि प्रेम चोपड़ा उनकी फिल्मों में निगेटिव रोल करें। उन्होंने बताया कि सिल्वर स्क्रीन पर निभाए गए उनके किरदारों को देखकर लोगों को लगता था कि वह बुरे इंसान हैं, तो इसे वह एक कॉम्प्लिमेंट की तरह लेते थे।

कभी पढ़ाई के लिए किया वेटर और टैक्सी ड्राइवर का काम, फिर बने बॉलीवुड स्टार

कलाकार किसी डिग्री डिप्लोमा के मोहताज नहीं होते लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं, जो एक्टर तो कमाल के हैं ही, लेकिन उन्होंने पढ़ाई-लिखाई के साथ भी कोई समझौता नहीं किया। यहां बात हो रही है बॉलीवुड के मशहूर स्टार रणदीप हुड्डा की। उनका जन्म 20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। उनके परिवार का बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। ऐसे में उनकी बॉलीवुड एक्टर बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है।

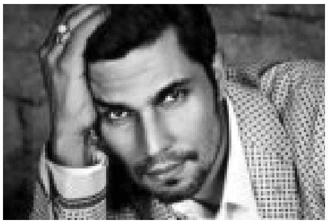

एक इंटरव्यू में रणदीप बताते हैं कि स्कूली पढ़ाई के बाद वह ग्रेजुएशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में चले गए। वहां से उन्होंने मार्केटिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में ह्यूमन रिसोर्स से एमबीए किया। रणदीप अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहना उनके लिए आसान नहीं था। वहां पर गुजर-बसर के लिए उन्हें टैक्सी ड्राइवर, वेटर से लेकर कार वॉश तक का काम करना पड़ा था। वापस भारत आकर उन्होंने एक एयरलाइन में कुछ समय तक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और थियेटर में भी काम करने लगे। प्ले के रिहर्सल के दौरान डायरेक्टर मीरा नायर ने उन्हें अप्रोच किया और यहां से उनकी फिल्मों की जर्नी शुरू हो गई।

कवि सम्मेलन में संचालक का जलवा

मंचासीन कवियों में किसके साथ संचालक के मधुर और किसके साथ कटु संबंध हैं? यह भी संचालक जी की बातों और हावभाव से पता लग जाता है। चूंकि संचालक ही मंच का सर्वेसर्वा होता है। उसी के हाथ में होता है कि किसे मंच पर कब लाना है? किसे हिट और किसे हूट करवाना है?

जिस तरह फिल्मी लोग फिल्म बनाते वक्त क्रिएटिव लिबर्टी अर्थात् कलात्मक आजादी लेते हैं और किसी भी कहानी को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर डालते हैं। कुछ उसी तरह कवि सम्मेलन का संचालक भी होता है, जो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आजादी लेता है। मंच संचालक को इस बात का पूरा हक होता है कि वह कवि सम्मेलन के दौरान किसी की भी कविता सुनाए, घिसे-पिटे चुटकुले सुनाए, कभी किसी कवयित्री से छिछोरे मजाक करे तो कभी मनगढ़ंत किस्से सुनाए। इस तरह संचालक पूरे समय... समय की बात करते हुए... समय को सलीके से चुटकुले और दूसरों की लिखी कविताओं के साथ हजम कर जाता है। इसके साथ ही वह हर आने वाले कवि को यह कहकर समय के सदुपयोग का पाठ भी याद कराता रहता है कि कवि मित्र समय सीमा का ध्यान रखें। हमारे पास समय कम है इसलिए एक ही रचना सुनाएं।

मंचासीन कवियों में किसके साथ संचालक के मधुर और किसके साथ कटु संबंध हैं? यह भी संचालक जी की बातों और हावभाव से पता लग जाता है। चूंकि संचालक ही मंच का सर्वेसर्वा होता है। उसी के हाथ में होता है कि किसे मंच पर कब लाना है? किसे हिट और किसे हूट करवाना है? देखा जाए तो कवि सम्मेलन और क्रिकेट मैच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। संचालक भी क्रिकेट के कप्तान की तरह समझदारी से बल्लेबाज अर्थात् कवि चुनकर कार्यक्रम को शानदार बना सकता है। किससे मैच अर्थात् सम्मेलन की ओपनिंग करानी है? किसको बाद में लाना है? इस तरह के तमाम निर्णय उसी के होते हैं। इसी के बहाने संचालक किसी कवि से पुराना खुन्नस भी बड़े ही मोहक अंदाज में निकाल डालता है। जैसे-एमएस धोनी के बाद किसी साधारण बल्लेबाज को उतारा जाए तो क्या हश्र होगा? उसे हिट विकेट करवाने के लिए वह किसी जमने वाले कवि के बाद हल्के कवि को मंच पर भेज देते हैं। इसी के साथ संचालक जी कातिल मुस्कान के साथ एक और चुटकुला पटक मारते हैं और इशारों-इशारों में जता देते हैं कि मुझसे पंगा लेने का हश्र देख लिया न बच्चू।

इस दुनिया में यदि सबसे धैर्यवान प्राणी की बात होगी तो उसमें कवियों का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि पांच मिनट की कविता के लिए यह कवि रूपी प्राणी पांच घंटे मन मारकर बैठा रहता है। इस दौरान संचालक की काल्पनिक कहानियों का पात्र भी बनता रहता है। मसनद पर बैठा कवि पहले ही आरामदायक पोज की मेहनत में जूझ रहा होता है और संचालक उसे काल्पनिक किस्से के बहाने मसलता रहता है। कवि भी अंदर ही अंदर भिन्नाते हुए अपनी बारी का इंतजार करता रहता है। कवि का नंबर आता है। वह बदला लेने का विफल प्रयास करता है, लेकिन संचालकनुमा रेफरी उसे सफल नहीं होने देता, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल के ड्राइवर की तरह ब्रेक अर्थात् एक माइक उसके पास हमेशा होता है। इस माइक की मदद से संचालक बीच-बीच में कवि के लिए वाह-वाह, बहुत सुंदर या कृपया समय सीमा का ध्यान रखें, करते हुए उसे अहसास दिलाता रहता है कि बेटा असली ड्राइवर अपुन हैं।

जिन लोगों को बचपन से ही ज्यादा बोलने पर डांट पड़ती हो वे कवि सम्मेलन या किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम के संचालन के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बकैती ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। संचालक कवि नहीं होता, न ही उसके पास अपनी लिखी कविता होती है। वह संबंध बनाने में माहिर होता है, बल्कि कहें तो वही सबसे बड़ा मार्केटिंग गुरु होता है। सो, कार्यक्रम लाने से लेकर कार्यक्रम करवाने तक का जिम्मा उसी के कंधों पर होता है। यही वह इंसान है, जो खालिस जुबान की खाता है अर्थात् बातों की खाता है। दिमाग वालों को तो वह चलाता है। किसी जमाने में मंच संचालक अलग काम था और कवि होना अलग, लेकिन आज काव्य की दुनिया में संचालक होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। बड़े-बड़े कवि भी इसी शर्त पर आना स्वीकार करते हैं कि उन्हें मंच संचालक बनाया जाए। उसके बाद मंच से कविता बेचारी तो चुपके से नीचे उतर जाती है। और वहां जो शेष रह जाता है, वह होता है-संचालक का पांडित्य प्रदर्शन, कुछ चुटकुले, कुछ कवि कहे जाने वाले प्राणी और थोड़ा-सा ग्लैमर।

● **अर्चना चतुर्वेदी**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress- and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

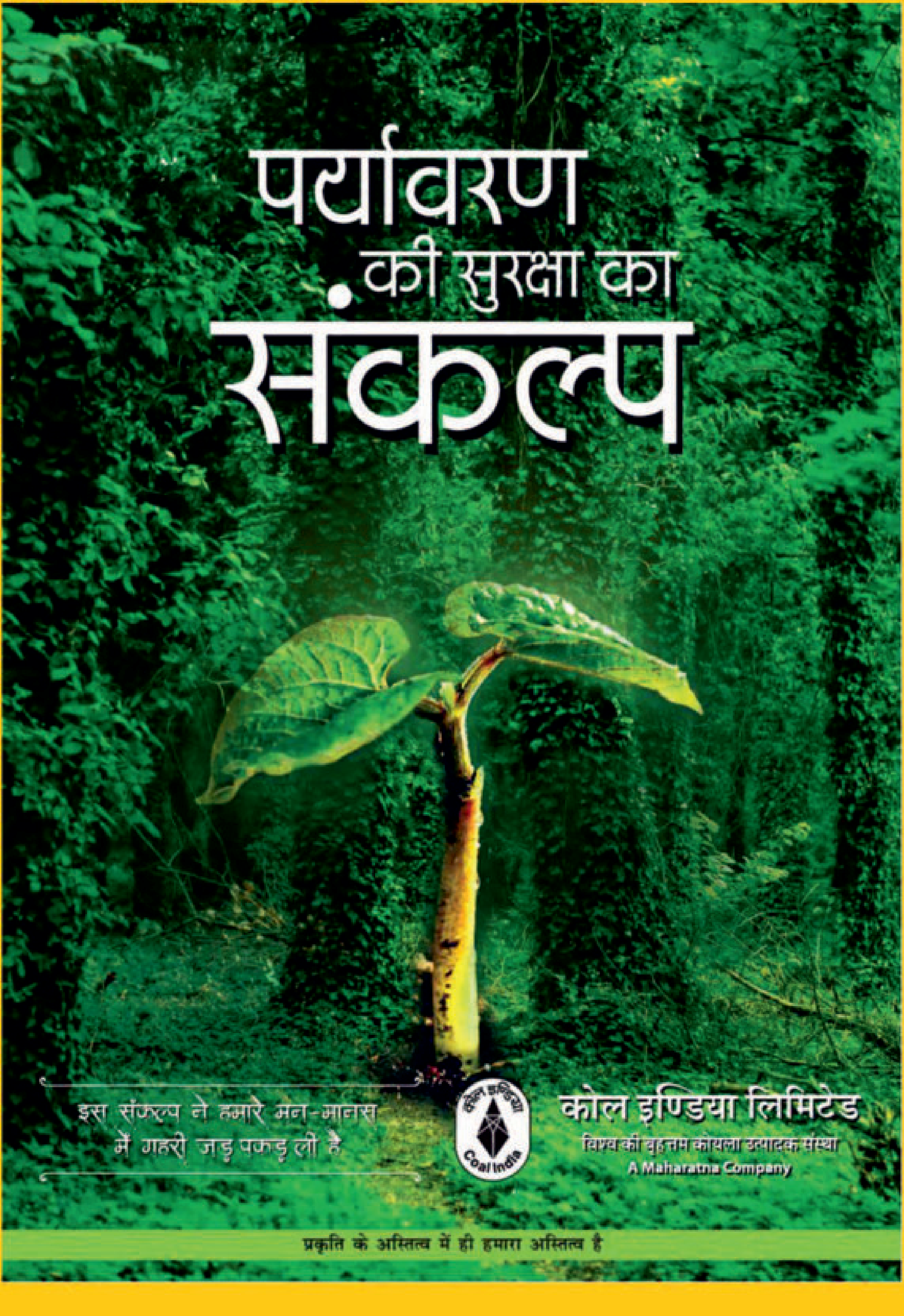

पर्यावरण
की सुरक्षा का
संकल्प
इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है
Coal India
कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की वृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company
प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है